यूनियन धारा
50
स्वर्णिम वर्ष

यूनियन धारा
Union Dhara

जिल्द. 50, सं. 2, मुंबई, अप्रैल-जून, 2025
VOL. 50, No.2, Mumbai, April-June, 2025

गृह पत्रिका • House Magazine of
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

गृह पत्रिका • House Magazine of
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन धारा Union Dhara

प्रकाशन तिथि- 14.08.2025
जिल्द. 50, सं. 2, मुंबई, अप्रैल-जून, 2025
VOL. 50, No.2, Mumbai, April-June, 2025

संरक्षक / Patrons

नितेश रंजन Nitesh Ranjan
कार्यपालक निदेशक Executive Director

एस. रामसुब्रमणियन S. Ramasubramanian
कार्यपालक निदेशक Executive Director

संजय रुद्र Sanjay Rudra
कार्यपालक निदेशक Executive Director

मुख्य संपादक / Chief Editor

सुरेश चन्द्र तेली Suresh Chandra Teli
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं) Chief General Manager (HR)

संपादकीय सलाहकार / Editorial Advisors

ए. के. विनोद A.K. Vinod
मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager

अरुण कुमार Arun Kumar
मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager

संपादकीय सलाहकार / Editorial Advisors

विट्ठल बनशंकरी Vithal Banashankari
महाप्रबंधक General Manager

अम्बरीष कुमार सिंह Ambarish Kumar Singh
उप महाप्रबंधक Dy. General Manager

विवेकानंद Vivekanand
सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.) Asst. General Manager (OL)

संपादक / Editor

गायत्री रवि किरण Gayathri Ravi Kiran
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.) Chief Manager (OL)

संपादकीय सहयोग / Editorial Support

जागृति उपाध्याय Jagriti Upadhyay
सहायक प्रबंधक (रा.भा.) Asst. Manager (OL)

मोहित सिंह ठाकुर Mohit Singh Thakur
सहायक प्रबंधक (रा.भा.) Asst. Manager (OL)

आवरण पृष्ठ

माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली दृष्टि दिव्याङ्ग महिला तथा पहली भारतीय दृष्टि दिव्याङ्ग –
सुश्री छोंजिन अंगमो, सहायक प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Cover Page

The first visually challenged Women in the world and first visually challenged Indian to climb Mount Everest –
Ms. Chhonzin Angmo, Assistant Manager, Union Bank of India

अवलोकन
OVERVIEW

प्रिय यूनियनाइट्स,

हमारे बैंक की द्विभाषी पत्रिका 'यूनियन धारा' के 'विकसित भारत' विशेषांक अंक के माध्यम से आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

'विकसित भारत' का संकल्प आत्मनिर्भरता, नवाचार, संवहनीय विकास और समावेशी प्रगति की यात्रा है। 'विकसित भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक आर्थिक गतिविधि विधि-सम्मत, पारदर्शी एवं राष्ट्रहित में हो। हमारा मूल दायित्व देश की वित्तीय प्रणाली को अवैध लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग तथा विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है ताकि बैंकिंग तंत्र सुरक्षित एवं विश्वसनीय बना रहे। आर्थिक अपराध न केवल वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि निवेश, उद्योग और समग्र विकास की गति को भी बाधित करते हैं।

जुलाई माह में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा आयोजित समारोह में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ईज़ 7.0 सुधार सूचकांक के अंतर्गत हमारे बैंक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। बैंक द्वारा ईज़ 7.0 सुधार एजेंडा के तीन विषयों में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु सम्मानित भी किया गया।

हमारे बैंक द्वारा एचआर सप्ताह का सफल आयोजन किया गया। एचआर सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता सभी स्टाफ सदस्य को हार्दिक बधाई।

बैंक की सफलता का सबसे बड़ा आधार हमारा मानव संसाधन है। बैंक कार्य-जीवन संतुलन को प्राथमिकता देता है और कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। हमारा मानना है कि नेतृत्वकर्ताओं को सक्रिय रूप से अपने साथियों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, छोटी–छोटी सफलताओं का उत्सव मनाना चाहिए और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। ये छोटे, किंतु प्रभावी कदम टीम–स्पिरिट को बढ़ाने और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाने में अत्यंत सहायक होते हैं।

'यूनियन धारा' का यह अंक 'विकसित भारत' के सभी दृष्टिकोण को साझा करने के लिए एक सशक्त मंच है। हमें उम्मीद है कि यहाँ छपे लेख आदि आप सभी को प्रेरित करेंगे और भविष्य में लिखने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। साथ ही 'यूनियन धारा' की संपादकीय टीम को भी इस अद्भुत संकलन के लिए बधाई।

शुभकामनाओं सहित

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

Dear Unionites,

It gives me great pleasure to address you all through the 'Viksit Bharat' special issue of our Bank's bilingual house magazine, 'Union Dhara'.

The vision of 'Viksit Bharat' is a journey of self-reliance, innovation, sustainable development and inclusive growth. To achieve the goal of 'Viksit Bharat', it is necessary that every economic activity should be lawful, transparent and in the national interest. Our basic responsibility is to protect the country's financial system from illicit transactions, money laundering and misuse of foreign exchange so that the banking system remains safe and reliable. Economic offences not only affect financial stability but also impede the pace of investment, industry and overall growth.

In July, our Bank secured second position under the EASE 7.0 improvement index for the financial year 2024-25 at a function organized by the Indian Banks' Association (IBA). It is a matter of great pride for us. The bank was also honoured for outstanding performance in three themes of the Ease 7.0 reform agenda.

Our bank has successfully organized HR Week. Hearty congratulations to all the staff members who won in the competitions held during HR week.

The strongest foundation of the bank's success is our human resource. Bank prioritizes work–life balance and takes care of the mental, emotional and physical well-being of the employees and their family members. We believe that leaders should actively engage with their peers, celebrate small successes, and foster a culture of respect. These small yet effective steps play a vital role in enhancing team spirit and creating a positive workplace environment.

This issue of 'Union Dhara' is a powerful platform to share the vision of 'Viksit Bharat'. We hope that the articles published here will inspire all of you and also encourage you to write in the future. Also, congratulations to the 'Union Dhara' editorial team for this wonderful compilation.

With best wishes,

(Nitesh Ranjan)
Executive Director

अवलोकन
OVERVIEW

प्रिय यूनियनाइट्स,

'यूनियन धारा' 'विकसित भारत' विशेषांक के माध्यम से मेरे विचार साझा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है।

'विकसित भारत' के निर्माण में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सर्वोपरि है। 'विकसित भारत' एक ऐसी संकल्पना है जो केवल आर्थिक वृद्धि या बुनियादी ढांचे की मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समावेशी, नवाचार-आधारित और डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ने का अभियान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल पूंजी और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, बल्कि वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता और सतत विकास की दिशा में भी बड़ा योगदान देते हैं।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंकों ने डिजिटलीकरण, फिनटेक सहयोग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाए हैं। बैंकों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे जन-धन योजना, डिजिटल पेमेंट्स, मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप फंडिंग आदि के कार्यान्वयन ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़ा है। इससे न सिर्फ रोजगार का सृजन हुआ, बल्कि महिलाओं, युवाओं और किसानों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए हैं।

इस दिशा में हमारे बैंक ने वित्त की उपलब्धता को और आसान और सुलभ बनाने हेतु यूनियन चैनल फ़ाइनेंस जैसे पारदर्शी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट पावर की सफलता को देखते हुए बैंक ने इस वर्ष प्रोजेक्ट पावर 3.0 की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य उभरती चुनौतियों का समाधान करना, पूर्व में अर्जित सीख से लाभ उठाना तथा बैंक को अपनी दीर्घकालिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। यह "राइज़" थीम का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य धारणीय संवृद्धि, बाज़ार हिस्सेदारी में वृद्धि, लाभप्रदता में वृद्धि तथा केंद्रित दृष्टिकोण के साथ चिन्हित किए गए 126 आकांक्षी जिलों में ग्राहक सेवा को विस्तार देना है।

इस सार्थक अंक के प्रकाशन हेतु मैं टीम 'यूनियन धारा' और सभी योगदानकर्ताओं को बधाई देता हूँ। आशा है कि आप इस सूचनाप्रद संकलन से नया बोध और दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

(एस. रामसुब्रमणियन)
कार्यपालक निदेशक

Dear Unionites,

It's a great pleasure to share my thoughts through 'Union Dhara' 'Viksit Bharat' special issue.

Access to banking services is paramount in building of a developed nation. 'Viksit Bharat' is a vision that is not limited to just economic growth or strengthening of infrastructure, but is a drive to move towards an inclusive, innovation-based and digital India. The role of the banking sector is crucial in achieving this goal as they not only provide capital and services, but also contribute significantly towards financial inclusion, digital literacy and sustainable development.

Banks in both rural and urban areas have taken steps to encourage digitization, fintech collaboration and entrepreneurship. The implementation of various schemes of the government through banks such as Jan Dhan Yojana, digital payments, Mudra loans, start-up funding, etc. has connected crores of people to formal financial institutions. This has not only created employment but has also brought about positive changes in the lives of women, youth and farmers.

Our Bank has introduced a transparent platform like Union Channel Finance to make the availability of finance easier and more accessible. Building upon the success of Project Power, this year Bank has rolled out Project Power 3.0, which aims to address emerging challenges, leverage past learnings, and propel Bank towards achieving its long-term aspirations. It is an integral part of theme "RISE", aimed at sustainable growth, enhancement in market share, increasing profitability, and enhance customer service in identified 126 Aspirational Districts with the focussed approach.

I congratulate 'Union Dhara' team and all contributors for bringing out this issue. May you gain new insights and fresh perspective through this informative read.

With best wishes,

(S. Ramasubramanian)
Executive Director

अवलोकन
OVERVIEW

प्रिय यूनियनाइट्स,

मुझे यह प्रसन्नता है कि यूनियन धारा का यह अंक भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलों में से एक विकसित भारत को समर्पित है। मुझे यह साझा करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 के ईज़ 7.0 सुधार एजेंडा के "विकसित भारत की ओर बैंकिंग" के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु सम्मानित किया गया।

भारत आज विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने के ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है । "विकसित भारत" केवल आर्थिक समृद्धि का एक दृष्टिकोण नहीं है; यह एक समूहिक स्वप्न का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुरक्षित संवहनीय पर्यावरण मिलता है।

हमने ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं से सशक्त बनाने के लिए कई डिजिटल जागरूकता पहल शुरू की हैं। हमारी फिनटेक नीति के तहत, बैंक उन्नत फिनटेक कंपनियों को सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है, जिससे नवाचार और अनूठी वित्तीय सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। डिजिटल उत्पादों, मोबाइल बैंकिंग और खुदरा नवाचार के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता दोनों को लगातार बढ़ा रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 'कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी (पीसीएएफ)' की सदस्यता लेने वाला पहला बड़ा भारतीय बैंक बनकर एक मानक स्थापित किया है। यह कदम जलवायु और हरित भविष्य के के प्रति हमारे समर्पण और उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

ये प्रयास न केवल बैंकिंग सेवाओं को अधिक स्मार्ट, अधिक सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाते हैं, बल्कि भारत के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए, आइए हम सभी भारत को न केवल आर्थिक विकास के मामले में, बल्कि मानवीय मूल्यों, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन के मामले में भी एक वैश्विक आदर्श बनाने का संकल्प लें।

शुभकामनाओं सहित

संजय रुद्र

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

Dear Unionites,

I am delighted to note that this issue of Union Dhara is dedicated to one of India's most significant national initiative, Viksit Bharat. It gives me immense pride to share that our Bank has been recognized with the Outstanding Performance award under the Ease 7.0 Reform Agenda for the FY 2024-25 under the theme Banking towards a Developed India.

India today stands at a historic juncture from where it is transitioning from developing to developed nation. "Viksit Bharat" is not merely a vision of economic prosperity; It represents a collective dream where every citizen has access to equal opportunities, quality education, modern healthcare facilities, world class infrastructure and safe sustainable environment.

We have undertaken multiple digital awareness initiatives to empower customers with safe banking practices. Under our FinTech Policy, Bank has been actively onboarding advanced FinTech companies, paving the way for innovation and unique financial services. digital products, mobile banking, and retail innovation, Union Bank of India continues to enhance both the reach and quality of banking services.

Union Bank of India has set a benchmark by becoming the first large Indian bank to subscribe to the 'Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)'. This step reflects our dedication to climate responsibility and building a greener future.

These efforts not only make banking services smarter, more secure, and more accessible, but also contribute significantly to India's economic, social and environmental development.

As we look ahead, let us all resolve to make India a global role model not only in terms of economic growth, but also in human values, social equality and environmental balance.

With best wishes,

(Sanjay Rudra)
Executive Director

संपादकीय
EDITORIAL

प्रिय पाठकगण,

इस ऐतिहासिक दौर में जब भारत अमृत काल की ओर अग्रसर है 'यूनियन धारा' का 'विकसित भारत विशेषांक' आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है।

'यूनियन धारा' प्रबंधन के दृष्टिकोण को शाखाओं तक पहुँचाने बैंक के साथ-साथ यूनियनाइट्स के विचार, अनुभव और सृजनशीलता को एक सशक्त मंच प्रदान करते हुए आंतरिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनी हुई है। यह संगठन की सामूहिक महत्वाकांक्षाओं और कार्मिकों के अभिव्यक्ति के मध्य सेतु बनकर समय के साथ प्रासंगिक बनी हुई है।

इस अंक में भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले अनेक महत्वपूर्ण विषयों को स्थान दिया गया है। इसमें प्रस्तुत लेख हमारे देश के विकास की आधारशिलाओं पर केंद्रित हैं तथा भारत की कार्यक्षमता एवं कौशल विकास की दिशा में किए जा रहे ठोस प्रयासों को रेखांकित करते हैं। इस अंक में तकनीकी और डिजिटल युग से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों पर भी विचार किया गया है और हमारे आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की स्पष्ट छवि पेश करने का प्रयास किया गया है।

इस विशेषांक का आवरण पृष्ठ एवरेस्ट पर फतह हासिल करनेवाली भारत की प्रथम तथा विश्व की पाँचवीं दृष्टि दिव्यांग महिला सुश्री छोंजिम अंगमों, जो यूनियन बैंक की स्टाफ है, की अद्‌भुत उपलब्धि को समर्पित है। वह उच्चतम शिखर से शुभारंभ करते हुए अब सात महाद्वीपों की उच्चतम शिखर पर विजय प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आपके अदम्य साहस और अद्‌भुत उपलब्धि निश्चित रूप से पाठकों को उत्साहित और प्रेरित करेगी।

'यूनियन धारा' की सृजनात्मक यात्रा को निरंतर गति देने हेतु संपादकीय सलाहकार समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझाव अवश्य ही अमूल्य हैं। इससे विषयवस्तु में नवीनता और प्रस्तुति में निखार आया है।

हमें विश्वास है कि यह अंक आपको न केवल जानकारी और प्रेरणा प्रदान करेगा, बल्कि हमारे साझा सपनों और लक्ष्यों के प्रति एक नई प्रतिबद्धता भी जगाएगा। आपके बहुमूल्य सुझाव हमारी इस यात्रा को और समृद्ध करेंगे।

भवदीया

(गायत्री रवि किरण)

Dear Readers,

We take immense pride in presenting this issue of 'Union Dhara' in the historic era of India's Progression towards Amrit Kaal.

'Union Dhara' has been a vibrant medium of internal dialogue — conveying the vision of top management to the field and providing a creative platform for Unionites to share ideas, experiences, and talents. Over time, it has become a dynamic bridge between organisational aspirations and the voice of its employees.

This issue covers a range of subjects that define the direction of India's future. The Articles featured herein focus on the fundamental pillars of national development and highlight concrete steps being taken to enhance productivity and skill development in the country. This issue also addresses the opportunities and challenges of the digital and technological age and efforts have been made to provide a clear picture of our economic and social aspirations.

The cover page of this special issue is dedicated to the stupendous achievement of Ms. Chonjim Angmo, the first Indian and fifth visually impaired woman in the world to conquer Everest, who is an employee of Union Bank. She began with the tallest and is now steadily moving towards her dream of standing on the highest point of all seven continents. Her indomitable spirit and amazing achievement will surely inspire the readers.

The inputs from Editorial Advisory Committee members in sustaining the creative journey of 'Union Dhara' is truly invaluable. Their guidance has enriched the content with freshness and enhanced its presentation.

We are confident that this issue will not only inform and inspire you but will also rekindle our shared commitment towards common dreams and goals. Your valuable feedback will continue to enrich our journey.

Yours sincerely,

(Gayathri Ravi Kiran)

गृह पत्रिका • House Magazine of

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन धारा Union Dhara

प्रकाशन तिथि- 14.08.2025

जिल्द. 50, सं. 2, मुंबई, अप्रैल-जून, 2025

VOL. 50, No.2, Mumbai, April-June, 2025

अनुक्रमणिका

- विदाई / सुस्वागतम 01
- भारत@2047: शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता 02
- ईज़ 7.0 04
- अवसंरचना विकास: नए भारत की नींव 05
- संवहनीय कृषि हेतु किसान कल्याण योजनाएं 07
- शिखर की ओर / शुभमस्तु 09
- नवीकरणीय ऊर्जा और भारत का भविष्य 11
- कविता - उद्यमित भारत विकसित भारत 13
- उद्घाटन 14
- स्किल इंडिया मिशन 15
- रोजगार सृजन में प्रौद्योगिकी का भूमिका 17
- जलवायु परिवर्तन और कृषि नवाचार 19
- कविता - विकसित भारत 21
- साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता 22
- Economic Leadership and Financial Inclusion 25
- India's Journey towards Sustainable Development Goals 28
- Renewable Energy and India's Future 31
- UBI's Accessible CBDC App 33
- सेंटर स्प्रेड 35
- 100% Skilled Workforce: Challenges and Solutions 37
- कविता - Bookworms 39
- Women Entrepreneurship and Startup Participation 40
- कविता - बैंक क्वार्टर - "संजना अपार्टमेंट" 42
- India's Mission: Zero Poverty 43
- बैंक में आयोजित विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम 45
- Digital Rails to a Brighter Financial Future 47
- India@2047: Education, Health, and Equality 50
- कविता - दिल से आभार 52
- Powering Growth while Pursuing Net Zero 53
- प्रतियोगिता 174 56
- Uncertainty of the Certainity 57
- Digital Fraud Fiasco: A Comedic Cautionary Tale 59
- हमें गर्व है 60
- विशेष साक्षात्कार सुश्री आयुषी, आईएएस 61
- सीएसआर गतिविधियां 63
- अतीत के झरोखों से 65
- समाचार 69
- खेल समाचार 74
- आपकी पाती 75

ई-मेल E-mail: uniondhara@unionbankofindia.bank | gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank
Tel.: 022-41829288 | Mob.: 9849615496

यूनियन धारा में प्रकाशित लेख आदि में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.
The views expressed in the articles published in Union Dhara are solely that of the author and do not necessarily reflect the views of the management.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित.
Published by Union Bank of India for internal circulation

विदाई

सुश्री ए मणिमेखलै ने 03 जून, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आप तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं। आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमशः शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर कार्य किया। आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्य नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए मणिमेखलै केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने कार्यनीतिक योजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया। आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समामेलन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पांच अन्य कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव है, इनमें कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। आप केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं।

भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों में एक सदस्य के रूप में आपने नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भविष्य के रोड मैप को तैयार करना, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-श्रृंखला वित्तपोषण, बैंकिंग संवाददाता मुद्दे और हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह के लिए तालमेल बनाना शामिल है।

सुश्री मणिमेखलै ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

आप 02 जून, 2025 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी & सीईओ के रूप में आपका कार्यकाल समाप्त हुआ। वर्तमान में आप आईबीए की उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं ।

सुस्वागतम

श्री सूरज श्रीवास्तव को 11.04.2025 से बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया किया गया। आपको कराधान एवं लेखा परीक्षा में सनदी लेखाकार (सीए) के रूप में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है और अपने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों में वैधानिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट और शाखा ऑडिट किए हैं। आप विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सह सदस्य हैं। श्री श्रीवास्तव ने आईसीएआई से सूचना प्रणाली ऑडिट (आईएसए) मूल्यांकन परीक्षण भी पुराण किया है ।

श्री सूरज श्रीवास्तव पूर्व में भी 21, दिसंबर 2021 से 20, दिसंबर 2024 तक बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

भारत@2047: शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता

कल्पना कीजिए एक सुबह जब 2047 की पहली किरणें भारत के क्षितिज पर फैल रही हों। आज़ादी के सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं और चारों ओर उल्लास का माहौल है। हर घर में तिरंगा लहरा रहा है और हर नागरिक के चेहरे पर गर्व की चमक है। इस दिन का सपना तो हमने 1947 में ही देख लिया था — एक ऐसा भारत जो शिक्षित हो, स्वस्थ हो और जहां हर किसी को बराबरी का हक़ हो।

वर्ष 2047 भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा — यह स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का क्षण भी होगा: हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे और कहाँ जाना है। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हर नागरिक को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पा सके, और समाज में हर वर्ग को समान अवसर प्राप्त हों। इन तीन स्तंभों — शिक्षा, स्वास्थ्य, और समानता — पर टिके भारत@2047 का सपना हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा तय करेगा।

शिक्षा क्षेत्र में प्रगति और चुनौतियाँ

शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विद्यालयी तंत्र ने 9.8 मिलियन शिक्षकों की मदद से 14.72 लाख स्कूलों में 24.8 करोड़ से अधिक छात्रों को शिक्षा दी है। सामुदायिक और निजी स्कूलों में भी विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ी है। वयस्क साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है; यह 2011 में 69.3% से बढ़कर 2023 में 77% हो गई है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को सुगम, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए तमाम सुधार लाती है। इसमें पाठ्यक्रम में अनावश्यक बोझ कम करने, डिजिटल तकनीक और उच्च-गुणवत्ता वाले ई-कंटेंट को अपनाने का उल्लेख है। शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यावसायिक कौशल से जोड़ने के लिए 'स्किल इंडिया' व 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' जैसी पहलें भी शुरू की गईं। सरकारी प्रयासों में समग्र शिक्षा अभियान, स्टार्स (एसटीएआरएस) पाठ्यक्रम सुधार, दीक्षा (डीआईकेएसएचए) डिजिटल शिक्षा मंच, पीएम शहरी विद्यालय (PM SHRI), बालवाटिका, और बालिका शिक्षा (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय) जैसी योजनाएँ शामिल हैं। इन पहलों ने विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर बढ़ाए हैं। ग्रामीण भारत में स्कूल पहुँच 90% से अधिक हो गई है। जनजातीय और सीमांत क्षेत्रों में मोबाईल शिक्षा व टेंट-शालाओं ने लचीलापन दिखाया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:-

- **(एनईपी 2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के तहत 5+3+3+4 संरचना अपनाई गई, जिससे बाल्यावस्था से ही सीखने की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई।
- **विद्यालयों में प्रौद्योगिकी की हिस्सेदारी:** 2019-20 में 38.5% स्कूलों में कंप्यूटर थे जो बढ़कर 2023-24 में 57.2% हो गए, और इंटरनेट सुविधा वाले स्कूल 22.3% से बढ़कर 53.9% हो गए।
- **उच्च शिक्षा में सुधार:** एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग ने संस्थानों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता को बढ़ावा दिया। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51,534 से बढ़कर 2022-23 में 58,643 हो गई, अर्थात् 13.8% की वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए कॉलेजों की संख्या 21.1% बढ़कर 38,498 से 46,624 हो गई है।
- **छात्र ड्रॉप आउट दर में गिरावट:** अब प्राथमिक शिक्षा में 1.9%, माध्यमिक में 5.2% और उच्च माध्यमिक में 14.1% है।
- **डिजिटल शिक्षा का विस्तार:** 2020 के बाद से दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म पर 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए।

चुनौतियाँ, जैसे:

- शिक्षकों की कमी, ग्रामीण-शहरी आधारभूत सुविधाओं का अंतर ।
- स्कूल ड्रॉपआउट दर विशेष रूप से किशोरियों में अब भी चिंताजनक ।
- निजी और सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता ।
- स्कूलों में संसाधनों का असंतुलन बना हुआ है।
- शिक्षा पर सरकारी व्यय वर्तमान में लगभग 3.0% है, जबकि राष्ट्रीय नीति इसका 6.0% लक्ष्य रखती है।
- पाठ्यक्रम सुधार में धीमापन।

भारत@2047 शिक्षा क्षेत्र में प्रगति के लिए कुछ आवश्यक कदम:

- उच्च शिक्षा में स्नातकों की गुणवत्ता व रोजगारोन्मुखी कौशल बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
- भारत@2047 के विकास हेतु शिक्षा को और अधिक समावेशी, नवाचार पूर्ण और रोजगारोन्मुखी बनाना होगा।
- तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान-उन्मुख विश्वविद्यालय और निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण को और प्रोत्साहन दिया जाना है।
- कार्य आधारित शिक्षा को मुख्यधारा में लाना है।
- एआई, रोबोटिक्स, डेटा विज्ञान जैसे विषयों को विद्यालय स्तर पर लाना है।
- पुस्तक आधारित रटने की बजाय अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना।

समावेशी पाठ्यक्रम, डिजिटल कक्षाएँ और सामुदायिक सहभागिता से हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ:

स्वतंत्रता के समय भारत की स्वास्थ्य प्रणाली संकटग्रस्त थी - जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से भी कम, शिशु मृत्यु दर अत्यधिक और महामारी व्यापक। आज के भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। 1970 में जीवन प्रत्याशा 47.7 वर्ष से बढ़कर 2024 में 70.62 वर्ष हो गई है। इसी तरह मातृ-मृत्यु दर 130 (2014-16) से 97 प्रति लाख (2018-20) और शिशु मृत्यु दर 189 (सन 1950) से 24.98 (सन 2025) प्रति हजार तक गिर गई है। इन आंकड़ों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का पता चलता है, तथापि सभी राज्यों में प्रगति समान नहीं रही। सरकारी प्रयासों की बदौलत कई लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है।

मुख्य सरकारी पहलें:

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (पीएम जेएवाई) के अंतर्गत रु. 5 लाख तक का वार्षिक इलाज कवर उपलब्ध हुआ है। 2024 में 70 वर्ष से ऊपर के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया। 2025 तक 36.9 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। इसी अवधि में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हुआ और लोगों का जेब-खर्च 62.6% से घटकर 39.4% हो गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)– ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत टेली-स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं।

स्वच्छता और जल योजनाएँ – स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय और नल-जल कनेक्शन पहुंचाए गए, जिससे जलजनित रोग कम हुए हैं।

टीकाकरण– कोविड-19 सहित कई संक्रामक रोगों के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान चले।

महिला और बाल स्वास्थ्य: पोषण (POSHAN) अभियान से मातृ एवं बाल पोषण सुधर रहा है। मातृत्व वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं से कुपोषण और मातृ-मृत्यु दर में सुधार आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा (ASHA) और एएनएम (ANM) कार्यकर्ताओं की भूमिका सराहनीय रही है।

टेलीमेडिसिन: डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और एआई आधारित निदान प्रणाली, दूरदराज़ क्षेत्रों में भी सटीक उपचार उपलब्ध हुआ है।

जन औषधि केंद्र: देश भर में कम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त दवाइयों की बिक्री की जा रही है, जिससे सामान्य जनता को सुविधा हो रही है।

चुनौतियाँ:

- ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80% स्टाफ की कमी है और केवल 20% स्वास्थ्य सुविधाएँ न्यूनतम मानकों पर खरी उतरती हैं, जिस कारण सरकारी अस्पतालों में भीड़, संसाधनों की कमी देखी जा रही है।
- देश का स्वास्थ्य बजट सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.1% है, जबकि राष्ट्रीय नीति में इसे 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है।
- गैर-संचारी रोगों (जैसे मधुमेह, हृदय रोग) का बोझ बढ़ गया है और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अपर्याप्त है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक उपकरणों की अनुपलब्धता।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

भारत@2047 के लिए आवश्यक कदम:

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली (UHC) लागू करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक-आधारित बनाना।
- उच्चस्तरीय अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार किया जाना।
- मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक चर्चा का विषय बनाना।
- टेली-स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म मजबूत करना होगा।
- अनुसंधान एवं स्थानीय चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा दिया जाना।

स्वस्थ्य जनशक्ति विकास की सबसे बड़ी पूंजी है; इसलिए 2047 तक हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी।

सामाजिक समानता और समावेशन

संवैधानिक दृष्टिकोण: भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सामाजिक समानता केवल नीति नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व है तदनुसार,

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है।
- **महिला आरक्षण विधेयक 2023-** संसद में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

आर्थिक समावेशन:

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 15 जनवरी 2025 तक 54.5 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 55.7% खाता धारक महिलाएँ हैं।
- उज्ज्वला, आवास और रसोई गैस योजनाओं ने पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद की है।
- गरीबी रेखा पर जीवन यापन करने वालों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है: विश्व बैंक के अनुसार, $3.65/दिन मानक पर गरीबी दर 2011-12 में 61.8% थी, जो घटकर 2022-23 में 28.1% रह गई है।

लैंगिक समानता:

- **"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ":** 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो 2023-24 में बढ़कर 930 हो गया है। बालिकाओं का माध्यमिक शिक्षा में नामांकन 75.5% से बढ़कर 78% हो गया है. इन पहलों

से लिंगानुपात में सुधार आया है और महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। इन उपलब्धियों के बावजूद "ग्लोबल जेंडर गैप" सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर है, जो बताता है कि पूरी समानता अभी दूर है।

- श्रमशक्ति में महिला भागीदारी केवल 25% के आसपास है।
- कार्यस्थलों में लैंगिक असमानता बनी हुई है।

डिजिटल समानता: डिजिटल इंडिया की क्रांति समावेश के लिए एक अवसर है, लेकिन डिजिटल विभाजन भी मौजूद है। ग्रामीण-शहरी, लैंगिक और आर्थिक आधार पर इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की पहुँच असमान बनी हुई है।

भारत@2047 में समानता की दिशा

- सभी वर्गों, जातियों और लिंग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समावेशन को जोड़ना।
- नवोन्मेष, स्टार्टअप, और कौशल विकास को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना।
- दिव्यांगजनों, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाना।
- नागरिकों को कर्तव्यों का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना अधिकारों का।

भागीदारी और उत्तरदायित्व: सरकार अकेले यह बदलाव नहीं ला सकती। निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठन, शैक्षिक संस्थान और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। समानता का मतलब केवल अवसर देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई उन्हें पाने की स्थिति में हो।

2047 का भारत – एक उम्मीद, एक संकल्प: शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता – ये एक-दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। एक शिक्षित समाज अधिक स्वास्थ्य-जागरूक होता है। एक समान समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य तक समान पहुँच संभव होती है। वर्ष 2047 में भारत का हर नागरिक जब गर्व से कह सके कि "मैं अवसरों की कमी से नहीं, अपनी मेहनत से तय करता हूँ अपना भविष्य," तभी यह यात्रा सफल होगी।

भारत@2047 केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का दर्पण है। जब हम यह सुनिश्चित कर पाएँगे कि:

- हर बच्चा स्कूल जाए और सीखने के अधिकार से वंचित न रहे।
- कोई मरीज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न हो।
- जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति किसी के सपनों को साकार करने में बाधा न बने।

तभी हम कह सकेंगे कि हमने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर अपने लोकतंत्र, विकास और मानवता के मूल्यों को निभाया है। भारत@2047 का सपना तभी साकार होगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता हर घर की पहचान बनें। आइए, हम सब मिलकर इस संकल्प को साकार करें।

सुशील मैठाणी
अं.ज्ञा.कें., हैदराबाद

दिनांक 03.07.2025 को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा आयोजित समारोह में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ईज़ 7.0 सुधार सूचकांक के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तथा बैंक द्वारा ईज़ 7.0 सुधार एजेंडा के तीन विषयों "विकसित भारत की ओर बैंकिंग", "प्रभावी जोखिम / धोखाधड़ी प्रबंधन, संग्रह और वसूली" तथा "उभरती बैंकिंग प्राथमिकताओं के लिए कर्मचारियों का विकास" में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु सम्मानित किया गया। श्री एम. नागराजू, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक, श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक, श्री अनिल कुरिल, मुख्य महाप्रबंधक, श्री सी.एम. मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक, श्री ताता वेंकेट वेणुगोपाल, मुख्य महाप्रबंधक तथा श्री अविनाश वसंत प्रभु, मुख्य वित्तीय अधिकारी ।

अवसंरचना विकास: नए भारत की नींव

"जब नींव मजबूत होती है,
तभी इमारतें आसमान छूती हैं।"

यह कहावत भारत के आधुनिक विकास पर पूर्ण रूप से लागू होती है। 21वीं सदी का भारत वैश्विक मंच पर अपने आर्थिक और सामाजिक उत्थान की कहानी लिख रहा है। इस सफलता की बुनियाद अवसंरचना पर टिकी हुई है। अवसंरचना विकास देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाली शक्ति है। सड़कों से लेकर डिजिटल हाईवे तक, बिजली से लेकर जलापूर्ति तक, बंदरगाह से लेकर स्मार्ट सिटी तक — ये सभी नए भारत की अवसंरचना को परिभाषित कर रहे हैं।

अवसंरचना विकास से तात्पर्य है कि समाज के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे, जैसे कि सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, और संचार प्रणालियों का निर्माण और सुधार करना। अवसंरचना विकास देश में आवश्यक भौतिक संरचनाओं का निर्माण और विकास करना है, जो अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने और समाज को बेहतर ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

भारत में अवसंरचना विकास की वर्तमान स्थिति:

सार्वजनिक अवसंरचना आर्थिक विकास की रीढ़ है, जो कनेक्टिविटी, व्यापार और समग्र जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत ने पिछले दशक में अवसंरचना विकास निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के योगदान ने विकास की गति को आकार दिया है। भारत का कुल बुनियादी ढांचा व्यय तेजी से बढ़ा है, 2024-25 में ₹11,11,111 करोड़ यानी जीडीपी का 3.4% बजट आबंटित किया गया है। अवसंरचना विकास समृद्धि, समावेशिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर है। अवसंरचना का अर्थ अब केवल सड़कें और बिजली नहीं है, बल्कि यह डिजिटल कनेक्टिविटी, गैस पाइपलाइन नेटवर्क और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सेवाओं का प्रसार भी है।

अवसंरचना विकास के पहलू:

- **भौतिक अवसंरचना:** इसमें सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
- **डिजिटल अवसंरचना:** इसमें इंटरनेट, दूरसंचार, मोबाइल नेटवर्क और डेटा सेंटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
- **सामाजिक अवसंरचना:** इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आवास जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

अवसंरचना विकास का महत्व- अवसंरचना विकास, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परिवहन, ऊर्जा, संचार, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव है।

"भारत में विकास की असली कहानी तब लिखी जाएगी जब हर गांव तक सड़क और इंटरनेट पहुँचेगा।"
- नीति आयोग

1) **आर्थिक विकास:** एक अच्छी अवसंरचना कारोबार को स्थापित और विस्तृत करने, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और परिवहन को बढ़ावा देने तथा व्यापार को प्रोत्साहित करने में मदद करती है, जिससे आर्थिक विकास होता है।

2) **सामाजिक विकास:** सामाजिक विकास, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र, नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करना।

3) **डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल अवसंरचना से सरकारी सेवाओं में सुगमता, कारोबार में तेजी और नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद मिलती है।

4) **रोजगार सृजन:** अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण तथा रखरखाव रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, जो लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं।

5) **जीवन की गुणवत्ता:** एक मजबूत अवसंरचना स्वच्छ पानी, उचित स्वच्छता, सुरक्षित परिवहन और अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है।

6) **अंतरराष्ट्रीय संबंध:** एक मजबूत अवसंरचना किसी देश को विदेशी निवेशकों और व्यापारिक भागीदारों को आकर्षित करती है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं।

नए भारत की दिशा में सरकार की प्रमुख अवसंरचना योजनाएं- अवसंरचना विकास आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में अग्रसर है। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर नागरिक को बेहतर सेवाएं और अवसर मिलें। सरकार ने अवसंरचना के विकास में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया है।

1) **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी):** यह पहचाने गए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक निवेश योजना है, जो देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी तरह की पहली कवायद है। एनआईपी का प्रयास इसे कुशल तरीके से पूरा करना है। सरकार ने ₹1.97 लाख करोड़ की प्रारंभिक स्वीकृति के साथ 7,400 परियोजनाओं का खाका तैयार किया है, जो 2025 तक पूर्ण होने की योजना

है। इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे और शहरी अवसंरचना शामिल हैं।

2) **प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना:** वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को रेलवे और रोडवेज सहित विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे अंतिम मील की कनेक्टिविटी बढ़े और यात्रा का समय कम हो। यह ₹1.2 ट्रिलियन की योजना है।

3) **भारतमाला परियोजना:** वर्ष 2017 में शुरू की गई भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की गई है, इसमें 550 जिलों को 4-लेन हाईवे से जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे माल परिवहन लागत में कमी और क्षेत्रीय विकास में वृद्धि होगी।

4) **सागरमाला परियोजना:** भारत में कुल 12 सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाह और लगभग 217 छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। यह परियोजना समुद्री मार्गों के माध्यम से बंदरगाहों को उत्पादन केंद्रों से जोड़ने का प्रयास है, जिससे संभार लागत में कमी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

5) **अन्य अवसंरचना योजनाएं:**

- **योजना का नाम - विवरण**

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना - यह योजना पीपीपी परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 के अंतर्गत 2014-15 से 2024-25 तक शहरी अपशिष्ट संग्रह में 97% की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - 2024-25 में 7,71,950 किलोमीटर सड़कें पूरी की गईं, जिस पर कुल ₹ 331,584 करोड़ खर्च हुए।

अमृत योजना - हर घर में नल से पानी की आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन हो, हरियाली और सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके, गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम किया जाए।

रूफटॉप सोलर मिशन - नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ना।

स्मार्ट सिटी मिशन - इस मिशन का लक्ष्य 100 स्मार्ट शहरों का विकास, कुल 8,076 परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत ₹1,64,706 करोड़ हैं, जिनमें से ₹1,54,351 करोड़ की लागत वाली लगभग 7,401 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

जल जीवन मिशन - इस मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत के समय, केवल ₹3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन था। दिनांक 1 फरवरी, 2025 तक, जल जीवन मिशन ने ₹12.20 करोड़ ग्रामीण घरों में सफलतापूर्वक सुरक्षित पेयजल कनेक्शन हो गया है ।

नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना भी की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इसके अलावा, भारत में शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) भी है जो शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है

अवसंरचना विकास में भारत की रैंकिंग बेहतर हो रही है लेकिन अब भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक देश को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाना। इसके लिए निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
- हर क्षेत्र में सतत एवं समावेशी विकास
- हाइब्रिड ऊर्जा और हरित अवसंरचना
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा आधारित स्मार्ट सिटीज़

हाल ही में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" के रूप में अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश में अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देना है।

अन्य चार एआईएफआई (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान) हैं: भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

अवसंरचना विकास केवल भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, समानता और समृद्धि का मार्ग है। एक सशक्त अवसंरचना न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी अवसर प्रदान करती है। भारत जिस गति से अपने विकास पथ पर अग्रसर है, उसमें अवसंरचना उसकी रीढ़ बनकर खड़ी है। "नया भारत तब बनेगा, जब हर नागरिक तक विकास की पहुँच होगी। और यह तभी संभव होगा जब उसकी नींव - यानी अवसंरचना - मजबूत होगी।"

प्रवीण कुमार
अनूप नगर शाखा,
क्षे.का., इंदौर

संवहनीय कृषि हेतु किसान कल्याण योजनाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में कृषि उपजों की व्याख्या और कृषि उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं की महत्ता का विवरण इस बात का द्योतक है कि भारत अनादि काल से कृषि प्रधान देश रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ों कि खोदाई और लौह काल में निर्मित कृषि में प्रयोग किए जाने वाले औज़ार भारत के समृद्ध कृषि पृष्ठभूमि को प्रतिबिम्बित करते हैं।

भारत में कृषि कि महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत में कृषि विनिर्माण विशेषकर बड़े बांधों जैसे कि हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, सिंचाई इकाइयों नहर ट्यूबवेल व कृषि खाद कारखानों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1972 में प्राथमिक क्षेत्र ऋण की अवधारणा प्रकाश में आई तथा देश में कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1975) की स्थापना, 06 अन्य बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1980), नाबार्ड (1982) का गठन तथा 1998 में लाई गई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भारत में कृषि विकास में मील का पत्थर साबित हुई। भारत के किसानों नें अपने अथक प्रयास से वर्ष 1960 के मध्य में लाई गई हरित क्रांति के सपनों को सच कर दिखाया जिससे भारत अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाया। भारत में किए गए इन सभी प्रयासों के कारण ही 1950-51 से 2020-21 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न में 6.21 गुना, बागवानी फसलों में 11.53 गुना, मछली उत्पादन में 21.61 गुना दुग्ध उत्पादन में 13.01 गुना और अंडों के उत्पादन में 70.74 गुना वृद्धि हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अनुमानों के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 3322.98 लाख मीट्रिक टन रहा जो 1950-51 के 510 लाख मीट्रिक टन से कहीं अधिक है। भारत में किसान कल्याण हेतु उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए&एफ़डबल्यू): यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है इस विभाग का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार और दो अन्य राज्य मंत्रियों द्वारा किया जाता है। इस विभाग का मुख्य कार्य देश में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना: इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों के अनुरूप स्केल आफ फाइनेंस और भूमि जोत के अनुसार किसी भी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी संस्था से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2 लाख तक ऋण लेने वाले किसानों को अब किसी भी समपार्श्विक प्रतिभूति या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा पशुपालक और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड - पशुपालन और मत्स्य पालन (केसीसी-एएचएफ) नाम से भी उपलब्ध है।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना: यह योजना मुख्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋणों पर लागू होती है। इस योजना में ₹3.00 लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड या ₹2.00 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड - पशुपालन और मत्स्य पालन योजना के किसान लाभार्थी शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 7% की दर से पहले वर्ष में ऋण प्रदान किया जाता है तथा बैंकों को सरकार द्वारा 1.5% की सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा सही समय से ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई): किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी, 2016 को प्रारम्भ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में किसानों को बहुत कम और सस्ती बीमा प्रीमियम दरों का भुगतान करना होता है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: 08 अप्रैल, 2015 को लांच की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी समपार्श्विक प्रतिभूति के ₹ 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध करना है। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी प्रदान कराया जा सकता है जो डेरी, पोल्ट्री या कृषि संयन्त्रों की खरीद हेतु ऋण सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि: दिनांक 24 फरवरी, 2025 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19 वीं किश्त भारत के किसानों के खातों में अंतरित की गई। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार किसानों के खातों में प्रति वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कुल ₹6000.00 का भुगतान करती है। दिसंबर - मार्च 2024-25 में इस योजना के कुल लाभार्थी किसानों की संख्या 10,04,67,693 रही।

ई-नाम पोर्टल: इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रिकल्चर मार्केट जिसे ई-नाम से भी जाना जाता है एक कृषि उपज ट्रेडिंग पोर्टल है। इस पोर्टल का उद्देश्य कृषि उपज हेतु एक देश एक बाजार के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान एपीएमसी मंडी को एकीकृत करके एक पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करना है। सरकार की इस पहल से किसानों को फसल का उचित मूल्य, पारदर्शिता, बाजार की जानकारी आसानी से प्राप्त हो पा रही है।

प्रधान मंत्री कृषि मान धन योजना : प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना (पीएम-

केएमवाई) भारत सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित आय प्रदान करना, ताकि वे बुढ़ापे में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, पात्र किसानों को प्रति माह न्यूनतम ₹3,000 की निश्चित पेंशन राशि मिलेगी।

कृषि शिक्षा व अनुसंधान: भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 16 जुलाई, 1929 में स्थापित इंडियन काउंसिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में कृषि के साथ साथ बागवानी, मछली पालन, पशु विज्ञान इत्यादि क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। वर्तमान में पूरे देश में 113 आईसीएआर और 74 कृषि विश्वविद्यालय के नेटवर्क के साथ कृषि शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है।

भारत में संवहनीय कृषि हेतु उठाए गए प्रमुख कदम : संवहनीय कृषि (Sustainable Agriculture) या टिकाऊ खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, आर्थिक रूप से व्यवहार्य रहकर और सामाजिक रूप से न्यायसंगत तरीकों से खेती को बढ़ावा देती है। भारत सरकार द्वारा संवहनीय कृषि की दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है, जो किसानों को उनके खेत की मिट्टी की जांच के बाद दी जाती है। इस कार्ड में मिट्टी के 12 प्रमुख रसायनिक तत्वों/मापदंडों की जानकारी होती है।

नेशनल मिशन फॉर नैचुरल फ़ार्मिंग: नेशनल मिशन फॉर नैचुरल फ़ार्मिंग का लक्ष्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना , कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों को बहाल करना और कृषि में जलवायु लचीलापन (क्लाइमेंट रेजिलिएंस) का निर्माण करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए धरती माता के कायाकल्प और स्थिरता को सुनिश्चित करना है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जैविक खेती से संबन्धित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए "राष्ट्रीय मिशन प्रकृतिक खेती प्रबंधन एवं ज्ञान पोर्टल"-naturalfarming.dac.gov.in की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के तत्वाधान में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत के पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना इत्यादि है। इस योजना के अन्य उद्देश्यों में बेहतर जल दक्षता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ, सतही-भूगर्भीय जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना, जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार करना जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि हो सके और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिल सके।

परंपरागत कृषि विकास योजना: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लिए प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) का एक घटक, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) चलाई जा रही है। पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जैविक क्लस्टरों में 03 साल के लिए ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें सीधे किसानों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से खेत के अंदर और बाहर (ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म) जैविक इनपुट हेतु ₹15000 प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन: राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत चलने वाली योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बजटीय प्रावधान ₹2400 करोड़ का वर्ष 2021–2024 तक के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए संवहनीय तरीके से गोवंश का संवर्धन और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना है। इस योजना के अंतर्गत त्वरित नस्ल सुधार के लिए आईवीएफ़ गर्भाधान पर ₹5000, वर्गीकृत वीर्य की लागत का 50% सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाती है तथा नस्ल गुणन फार्म की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत का 50% तक या अधिकतम ₹2.00 करोड़ तक उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान आदिकाल से ही महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद, सरकार ने कृषि उत्थान के लिए कई अहम कदम उठाए। भूमि सुधार, बड़े बांधों का निर्माण, सहकारी समितियों का विस्तार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और नाबार्ड जैसी संस्थाओं की स्थापना ने किसानों को सशक्त किया। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा और आय में वृद्धि प्रदान की।

ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने में मदद की, जबकि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। आईसीएआर, कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। संवहनीय कृषि के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कदम उठाए गए। इन प्रयासों से भारत न केवल खाद्य आत्मनिर्भर बना, बल्कि कृषि उत्पादों का प्रमुख निर्यातक भी बन गया है। खाद्यान्न, बागवानी और पशुधन उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के जीवन में सुधार आया है और देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

मो. शाहीद कबीर
अं.ज्ञा.कें., भुवनेश्वर

शिखर की ओर

मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई

ताता वेंकेट वेणुगोपाल

जी के सुधाकर राव

बिरजा प्रसाद दास

महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई

हर मोहन साहू

रवि शंकर

सत्यजित मोहंती

जूना रोस्लिन

डॉ एच. टी. वासप्पा

सिद्धार्थ किरण मजूमदार

दिलीप मिश्रा

कुमार राहुल

वी माधवी

राजेंद्र कुमार

कल्याण वर्मा

राजकुमार एस ए

तजविंदर कौर

उप महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई

नरेश कुमार वाई

इश्तियाक अर्शद

शैलेंद्र कुमार

पी. एम. सेंथिल कुमार

रंजीता सुरेश

हिमांशु व्यास

अंकुर सर्राफ

एम. वी. तिलक

एम वी के किशोर

टी वी कपिल राज

मुकेश कुमार

अच्युत हरि मुदलियार

एस जय राजू

सरोज कुमार राउत

समीर कुमार

अजय खरे

गौरव कुमार

अश्वनी कुमार त्रिपाठी

जी रामप्रसाद

संजीव कुमार सिंह

रेवती रमण विकास सिन्हा

हिमांशु मिश्रा

सुनिल वी पाटिल

विभूति भूषण राउत

नवनीत परुथी

तेजस्विनी वी. सी.

विकास ईडा

रवि रंजन

प्रिंस डी

प्रिया चौधरी

हम आपके नेतृत्व में बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं

शुभमस्तु

सुदर्शन भट्ट, मुख्य महाप्रबंधक

के एस डी शिव प्रसाद, महाप्रबंधक

एन. चेझियन, महाप्रबंधक

प्रमोद कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक

मोहनदास, उप महाप्रबंधक

हम आपके सुखद एवं सक्रिय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं

नवीकरणीय ऊर्जा और भारत का भविष्य

भारत का दृष्टिकोण नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिसे खपत की तुलना में प्राकृतिक स्रोतों से अधिक मात्रा में पुनःपूर्ति की जा सकती है। यह परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा किफायती तथा पर्यावरण के अनुकूल होती है। यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखना है तो जीवाश्म ईंधन यथा - कोयला, तेल और गैस जैसे कार्बन उत्सर्जी ईंधनों की खपत को सीमित कर नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग की ओर अग्रसर होना होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन जलाए जाने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता जो जलवायु परिवर्तन संकट का कारण है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति में शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन संकट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार:

सौर ऊर्जा: सौर ऊर्जा एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें सिलिकॉन जैसे अर्धचालक धातु से बने फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 5,000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति-घंटे सौर ऊर्जा प्रवाहित होती है और अधिकांश भागों में यह प्रति दिन 4-7 किलोवाट प्रति-घंटे प्रति वर्गमीटर प्राप्त होती है। सैद्धांतिक रूप से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का छोटा अंश भी यदि प्रभावी ढंग से उपयोग कर लिया जाए तो यह पूरे देश की बिजली आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ऊर्जा परिदृश्य में सौर ऊर्जा के सफल उपयोग ने पर्यावरण अनुकूल तरीके से भारतीय गांवों में लाखों लोगों का भोजन पकाने, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर उन्हें लाभान्वित किया है। परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के कंडे आदि के द्वारा रसोई में खाना पकाने वाली ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को धुएँ के कारण फेफड़ों और आंखों की बीमारियों के जोखिम को कम किया है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन का अवसर मिला है तथा सामाजिक जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम), सौर पार्क योजना, वीजीएफ योजनाएं, सीपीएसयू योजना, केनाल टॉप योजना, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना आदि शुरू की हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के मुक़ाबले 2024-25 में सौर ऊर्जा उत्पादन में 23.83 गीगावाट वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में कुल स्थापित सौर क्षमता 105.65 गीगावाट है। इसमें ग्राउंड-माउंटेड इंस्टॉलेशन 81.01 गीगावाट, रूफटॉप सोलर 17.02 गीगावाट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के सोलर कंपोनेंट से 2.87 गीगावाट और ऑफ-ग्रिड सिस्टम से 4.74 गीगावाट शामिल हैं।

पवन ऊर्जा: पवन-चक्की के सहायता से टर्बाइन को घुमाकर हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा की यह प्रक्रिया पवन की औसत गति के उपर निर्भर होता है अतः समुद्र के तटीय क्षेत्र या बड़े जल स्रोत के तट जहां तेज हवाएँ चलती है, पवन-चक्की स्थापित करने का आदर्श स्थान होता है।

सरकार, विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से पूरे देश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है जिसमें नीजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना प्रमुख है। भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसिक हो चुकी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार देश में पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट प्रति वर्ष है। वर्ष 2024-25 के दौरान पवन ऊर्जा में 4.15 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है। कुल संचयी स्थापित पवन क्षमता अब 50.04 गीगावाट है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा की मजबूत भूमिका को दर्शाता है।

भू - तापीय ऊर्जा: पृथ्वी के केंद्र यानी कोर का तापमान लगभग 4000°C है जिसके कारण भूतल के नीचे पिघली हुई चट्टानों की कई परतें है जिसे मैग्मा कहा जाता है। कभी-कभी भौगोलिक घटनाओं के कारण ये मैग्मा ऊपर उठकर पृथ्वी के सतह के नीचे जमा हो जाते है। जब ये मैग्मा भूजल के सम्पर्क में आता है तो जल को वाष्पित कर एक हॉट-स्पॉट क्षेत्र का निर्माण करता है। इस हॉट-स्पॉट क्षेत्र में छेद कर अत्यधिक दवाब वाले वाष्प को पाइप के माध्यम से लाकर विद्युत जेनेरेटर से जुड़े टर्बाइन को घुमाया जाता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह स्थान विशिष्ट है। भूतापीय ऊर्जा के हॉट-स्पॉट अधिकांशतः ऐसे क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि का खतरा लगातार बना रहता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में लगभग 350 भूतापीय ऊर्जा स्थान खोजे हैं। इनमें से सबसे अधिक आशाजनक स्थिति लद्दाख की पुगा घाटी में है। भारत में 7

भू-तापीय प्रांत हैं यथा - हिमालय, सोहना, पश्चिमी तट, कैम्बे (गुजरात), गोदावरी, महानदी और सोन-नर्मदा-तापी (सोनाटा)।

जल विद्युत: जल प्रवाह की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर जल विद्युत प्राप्त की जाती है। किसी जलाशय या नदी के पानी को बांध बनाकर संगृहीत किया जाता है, इसके बाद पानी के तेज धार को विद्युत जेनेरेटर से जुड़े टरबाइन से गुजार कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। हमारे देश में वर्षा की मात्रा या पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन विशेषकर सुखे की स्थिति इसकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

भारत में अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जल विद्युत है। हाल के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 197 पन बिजली परियोजनाएं संचालित हो रही हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 46,928 मेगावाट है, जबकि लघु पन बिजली परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) की क्षमता 5,100.55 मेगावाट दर्ज की गई है। इस प्रकार भारत की कुल पन बिजली क्षमता लगभग 52,028 मेगावाट हो चुकी है, जो वैश्विक परिदृश्य में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। भारत में पन बिजली उत्पादन का लगभग 92.5% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हाथों में है। इनके निरंतर प्रयासों से भारत पन बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

देश की प्रमुख पन बिजली परियोजनाएं:

टिहरी बाँध - उत्तराखंड में स्थित है भारत की सबसे बड़ी इस पन बिजली परियोजना की स्थापित क्षमता 2,400 मेगावाट है।

कोयना परियोजना - महाराष्ट्र में स्थित इस परियोजना की स्थापित क्षमता 1,960 मेगावाट है।

सरदार सरोवर बाँध – गुजरात में नर्मदा नदी पर निर्मित इस परियोजना की क्षमता 1,450 मेगावाट है।

भाखड़ा नांगल बाँध - हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित इस परियोजना की क्षमता 1,379 मेगावाट है।

ये सभी परियोजनाएं न केवल बिजली उत्पादन में बल्कि सिंचाई और पेयजल आपूर्ति, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, नौवहन जैसी बहुआयामी सेवाओं में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

महासागरीय ऊर्जा: पृथ्वी के तीन भागों पर स्थित महासागर अपने में विशाल ऊर्जा समेटे हुए है जिसे महासागरीय ऊर्जा कहते है; प्रौद्योगिकियों के सहायता से इससे तीन प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है:

1. **ज्वारीय ऊर्जा (टाइडल एनर्जी):** महासागर में उठने वाले ज्वार-भाटा में विद्यमान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी के इर्द-गीर्द स्थित चंद्रमा की कक्षा के एक निश्चित पैटर्न के कारण महासागरीय तटों पर ज्वार-भाटा आता है जिसे समुद्र के किसी संकरे मुखद्वार पर बांध बनाकर संचित कर लिया जाता है। बांध के मुखद्वार पर एक टर्बाइन लगा कर ज्वारीय ऊर्जा को विद्त ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की काफी संभावनाएं हैं।
2. **तरंग ऊर्जा (वेव एनर्जी):** समुद्र की सतह पर उठने वाली तरंगों के गतिज ऊर्जा के माध्यम से टर्बाइन घुमाकर विद्त यानी तरंग ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। 150 मेगावाट की क्षमता वाली पहली तरंग ऊर्जा परियोजना त्रिवेन्द्रम के पास विझिंजम में स्थापित की गई है।
3. **महासागरीय तापीय ऊर्जा (ओशन थर्मल एनर्जी):** महासागर का सतही जल पर्याप्त रूप से गर्म हो जाने पर उसके माध्यम से अमोनिया (25°C पर वाष्पित) को गर्म कर वाष्पशील कर लिया जाता है अब इस वाष्प की सहायता से टर्बाइन को घुमाकर विद्त उत्पादित किया जाता है। उसके पश्चात सागर की गहराई से ठंडा जल खींच कर अमोनिया के वाष्प को पुनः तरल रूप में संघनित कर चक्रीय रूप से इसे काम में लाया जाता है।

   हमारे देश में महासागरीय ऊर्जा अभी विकास के चरण में है और भविष्य में इसकी काफी संभावनाएं हो सकती हैं।

जैव ऊर्जा: जैव ऊर्जा यानी बायोएनर्जी का उत्पादन कई तरह की जैविक सामग्रियों, जिन्हें बायोमास कहा जाता है जैसे - लकड़ी, चारकोल, गोबर, खादें एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ से किया जाता है। आधुनिक जैव ऊर्जा अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि यह स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कई सामाजिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है। जैव ऊर्जा का प्रयोग वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है तथा स्थानीय रोजगार एवं कारोबार के अवसर भी उपलब्ध कराता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने चरण-1 के तहत दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए 858 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित उपयोजनाएं चलाई जा रही हैं:

1. **अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम:** शहरी, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्टों/ अवशेषों से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।

2. **बायोमास कार्यक्रम:** ब्रिकेट एवं पैलेट के निर्माण में सहायता और बायोमास (गैर-खोई) आधारित उद्योगों में सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।

3. **बायोगैस कार्यक्रम:** योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1 से 2500 क्यूबिक मीटर के बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

जैव ऊर्जा संयंत्रों की विद्त उत्पादन की कुल क्षमता 11.58 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें ऑफ-ग्रिड और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं से 0.53 गीगावाट शामिल है।

ग्रीन हाइड्रोजन: इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभाजित कर हाइड्रोजन को संगृहीत कर ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में विद्युत उर्जा की खपत होती है अतः आवश्यक है कि उपर्युक्त प्रक्रिया केवल नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर या पवन ऊर्जा) द्वारा ही किया जाए।

भारत का लक्ष्य 2030 तक पांच मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता पर निर्भर करता है। 2025 तक इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता 8 गीगावाट प्रति वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2030 तक भारत में हरित हाइड्रोजन बाज़ार का संचयी मूल्य $8 बिलियन तक पहुँच सकता है और भारत को हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने के लिये कम-से-कम 50 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चला रही है। इसके अंतर्गत आरंभिक चरण में वर्ष 2029-30 तक 17,490 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था यथा इलेक्ट्रोलाइजरों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विद्त उत्पादन क्षेत्र में क्रातिकारी परिवर्तन लाई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 223 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित कर लिया है - जिसमें सौर ऊर्जा से 108 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 51 गीगावाट शामिल है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार 2030 तक भारत की बिजली खपत बढ़कर 817 गीगावाट तक पहुंच सकती है। 2029-30 तक ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 44% जबकि ताप विद्युत का उत्पादन 78% से घटकर 52% होने की उम्मीद है।

सरकार की प्रतिबद्धता और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा एक स्थायी और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत के रूप में भारत के ऊर्जा मिशन में अपनी भूमिका को और मजबूत करेगी।

राजीव रंजन
क्षे.का., बालेश्वर

उद्यमित भारत विकसित भारत

उद्यमी बन प्रेरित करें
विकसित भारत निर्मित करें।

भारत की अर्थव्यवस्था में
कैसे सुधार और लाना है।
अब देश को विकसित करना है
और कारोबार बढ़ना है।।

शिक्षा भी बहुत जरूरी है
हमें पढ़ना और पढ़ाना है।
उद्यमिता से होगा विकास
यह जन-जन को समझाना है।।

भुखमरी गरीबी मिटे यहाँ
और सबको रोजगार मिले।
भारत के बच्चे-बच्चे को
तब खुशियों का संसार मिले।।

कौशल और ज्ञान के संगम से
सजती विकास की धरती है।
आशा के अनुरूप धरा पर
सुख समृद्धि बरसती है।।

करें प्रयास उद्यम करें
युवा विकास का प्रण करें।
हर क्षण का मूल्य संवर्धन करें
विकसित भारत हेतु प्रयत्न करें।।

अपराजिता प्रीति
क्षे.का., वरंगल

उद्घाटन

डेलापीर शाखा, क्षे.का., बरेली

साबरमती शाखा, अंचल कार्यालय, गांधीनगर

पडुबिद्री शाखा, क्षे.का., उडुपि

एटीएम, भद्रावती बी एच रोड शाखा, क्षे.का., शिवमोग्गा

वाडवल्ली शाखा, अंचल कार्यालय, कोयम्बत्तूर

डीजीएमएस शाखा, क्षे.का., धनबाद

गोधरा शाखा, क्षे.का., आणंद

मण्णुत्ति शाखा, क्षे.का., तृश्शूर

यूनियन प्रीमियर शाखा, क्षे.का., गोवा

कृषि ऋण केंद्र (एएलपी) परिसर, क्षे.का., बठिंडा

क्षे.का., तिरुनेलवेली

अयत्तिल शाखा, क्षे.का., कोल्लम

तिलियापुर शाखा, क्षे.का., बरेली

राया शाखा, क्षे.का., आगरा

पेनुकोंडा शाखा, क्षे.का. अनंतपुर

स्किल इंडिया मिशन

आज जहाँ विश्व में अधिकांश देशों की युवा जनसंख्या बहुत ही कम है, वहीं भारत में आधे से अधिक आबादी की उम्र पच्चीस वर्ष से कम है। किसी भी देश के भविष्य का निर्धारण वहाँ की युवा पीढ़ी के सपनों, क्षमताओं और उनके सशक्तिकरण से ही होता है। लेकिन जब किसी देश का युवा बेरोज़गारी, कुशलता की कमी और अवसरों के अभाव के कारण भटकने लगे, तो यह देश की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसी ही स्थिति से बचने और समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया — "स्किल इंडिया मिशन", जिसका उद्देश्य युवाओं को केवल रोज़गार दिलाना नहीं था, बल्कि उन्हें कार्यकुशल और योग्य बनाना था ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, स्वयं के पैरों पर खड़े हो सकें और देश की विकास गति में अपना योगदान दे सकें।

ऐसे ही महत्वपूर्ण अभियान की आवश्यकता कई दशकों से महसूस की जा रही थी। भारत में हर वर्ष लाखों युवा विद्यालयों और महाविद्यालयों से शिक्षा पूर्ण करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को अपनी शिक्षा के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती। इसका कारण है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में "कौशल" की कमी और कौशल विकास पर कम ध्यान देना। ऐसी स्थिति में एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता थी जो युवाओं को उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दे तथा आधुनिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी भी दे ।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 जुलाई, 2015 को स्किल इंडिया मिशन की नींव रखी गई। इस मिशन का नारा था — "कौशल भारत, कुशल भारत"। इस पहल के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशलों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, किंतु इसके पीछे एक बड़ा सपना था — भारत देश के हर एक युवा को यह एहसास कराना कि देश का भविष्य उसी के हाथ में है। वह केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकता है।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं शुरू की गईं। इनमें प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत लाखों युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। इस योजना में प्रत्येक युवा को लगभग 3 से 6 महीने की अवधि में व्यावसायिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुनर सिखाए गए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र और रोजगार की संभावनाएँ प्रदान की गईं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। यह संस्था निजी एवं सरकारी संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करती है।

स्किल इंडिया मिशन को सफल बनाने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों का भी अहम योगदान रहा है। कई दशकों से ये संस्थान केवल डिग्री या डिप्लोमा देने तक सीमित थे किंतु अब इन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि यहाँ से उत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ उद्योग जगत में प्रभावी भूमिका निभा सकें। किंतु केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उनका प्रभाव तभी स्पष्ट होता है जब ज़मीनी स्तर पर उसका असर दिखाई दे। ऐसा ही कुछ स्किल इंडिया मिशन के साथ भी हुआ। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला से सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब अपने गाँव में 15 महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं। एक पुरुष जो पहले पलायन के लिए मजबूर थे, आज एक सफल मोबाइल मरम्मत की दुकान चला रहे हैं। यह उदाहरण न केवल इस अभियान की सफलता के प्रमाण हैं बल्कि इस बात की भी गवाही देते हैं कि जब व्यक्ति को सही संसाधन और दिशा दी जाती है तो वे हर असंभव को संभव बना सकते हैं और हर विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं।

स्किल इंडिया मिशन का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखा गया है। इस मिशन का दोहरा असर देखने को मिला है — जहाँ एक ओर यह ग्रामीण और शहरी युवाओं के

बीच की दूरी को कम कर रहा है, वहीं यह मिशन महिलाओं को भी आर्थिक सम्मान दिला रहा है। कौशल विकास से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, जिससे वे न केवल अपने परिवार की, बल्कि समाज में भी योगदान दे रही हैं।

इसके अतिरिक्त इस अभियान ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को भी सशक्त किया है। एक कुशल कार्यबल हमारे देश की आर्थिक नींव बन रहा है। इस मिशन के द्वारा हमारा युवा कार्यबल तकनीकी रूप से सक्षम हो रहा है, जिससे उत्पादन, नवाचार और उद्यमिता में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो रही है।

आज यह भी आवश्यक है कि कौशल विकास के इस अभियान में समाज के सभी वर्गों को समावेशी रूप से जोड़ा जाए, विशेषकर वे युवा जो किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँचने के लिए विशेष सुविधाएँ, अनुकूल पाठ्यक्रम और संवेदनशील प्रशिक्षक उपलब्ध कराना समय की माँग है। जब तक समाज का हर अंग आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना अधूरी ही मानी जाएगी। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना और स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि भाषा या साधनों की कमी बाधा न बने।

भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा विश्लेषण, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास पर विशेष जोर देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आने वाला समय तकनीकी दक्षता की माँग करेगा। इसके लिए अभी से एक दीर्घकालिक रणनीति बनाई जानी चाहिए, जिसमें विद्यालयों के स्तर से ही व्यावहारिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। केवल युवाओं को हुनरमंद बनाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा दृष्टिकोण देना भी आवश्यक है जिससे वे जीवन की समस्याओं को समाधान में बदल सकें। यदि हम आज हर युवा के भीतर यह विश्वास जगा सकें कि उसका ज्ञान और हुनर न केवल उसकी किस्मत बदल सकता है बल्कि देश की दिशा भी तय कर सकता है, तो निःसंदेह भारत कौशल के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनकर उभरेगा।

देखा जाए तो इस मिशन की राह में कम चुनौतियाँ नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है — प्रशिक्षण की गुणवत्ता। इसके अलावा चुनौतियों में आता है ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षण केंद्रों की कमी, डिजिटल साक्षरता में बाधाएँ और प्रशिक्षण के बाद नौकरी से जोड़ने की प्रक्रिया में धीमापन। इन सभी ने इस अभियान की गति को कुछ हद तक धीमा किया है। साथ ही कई बार युवाओं को नौकरी मिलने में देरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय की कमी है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए और अधिक गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ कदम जो इस मिशन को और प्रभावशाली बना सकते हैं, वे हैं — स्थानीय स्तर पर उद्योगों की माँग के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करना, प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की नियमित निगरानी करना और उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ऋण एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। यह भी अत्यंत आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़ा जाए — विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े जिलों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं को। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे भी कौशल प्राप्त कर समाज की बराबरी में खड़े हो सकते हैं और देश की प्रगति में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।

आज जब भारत "आत्मनिर्भर भारत" बनने की ओर अग्रसर है तब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का हर युवा आत्मनिर्भर तो बने ही, साथ ही दूसरों को भी रोज़गार प्रदान करे। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी होती है। इस मिशन द्वारा हर युवा में यह मानसिकता आनी चाहिए कि — "मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं निर्माण कर सकता हूँ।" यही स्किल इंडिया मिशन युवाओं में विश्वास पैदा करने का कार्य कर रहा है। अब भारत का समय बदल रहा है। भारत का युवा बदल रहा है। यह सब संभव हो पाया है क्योंकि आज का ग्रामीण युवा स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, महिलाएँ सीमाओं को लाँघकर उद्योग की अगुवाई कर रही हैं।

अंततः स्किल इंडिया मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह बदलाव की ओर एक बड़ा कदम है — एक ऐसा कदम जो भारत को एक कुशल, आत्मनिर्भर और गौरवशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जा रहा हैं; और यह कदम उठा रहा है- आज के भारत का युवा। इनको जितना अधिक प्रोत्साहन, अवसर और मार्गदर्शन मिलेगा, उतनी ही तेज़ी से देश विकास की दौड़ में अग्रणी होगा। देश के हर युवा को यह समझना होगा कि उसके हाथ में केवल कलम या औजार नहीं है — पूरे देश का भविष्य है। और जब वह अपने भीतर के इस हुनर को पहचान लेगा, तब न केवल वह स्वयं को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पूरे भारत को आगे ले जाएगा।

निखिल पांडे
नामली शाखा,
क्षे.का., इन्दौर

रोजगार सृजन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है और प्रौद्योगिकी ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है — शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और सम्प्रेषण सभी में इसके प्रभाव से कार्यशैली में क्रांतिकारी बदलाव आया है। जहाँ कुछ पारंपरिक नौकरियाँ तकनीकी बदलाव से समाप्त हुई हैं, वहीं प्रौद्योगिकी ने कई नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी योजनाओं ने तकनीक आधारित सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और स्टार्टअप संस्कृति ने भी तकनीक आधारित नौकरियों को जन्म दिया है। गिग इकॉनॉमी और फ्रीलांसिंग जैसे नए कार्य मॉडल, तकनीक की बदौलत ही संभव हुए हैं, जिनसे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।

इस प्रकार, यदि युवा समय के साथ अपने कौशल को अपडेट करें और प्रौद्योगिकी को अपनाएँ, तो यह न केवल उनके लिए रोजगार का साधन बनेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा।

आज के युग में प्रौद्योगिकी मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चाहे वह शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, कृषि या औद्योगिक क्षेत्र, प्रौद्योगिकी ने इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि तकनीकी प्रगति के साथ रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं क्योंकि मशीनें मानव श्रम का स्थान ले लेती हैं। तथापि, यह दृष्टिकोण एकपक्षीय है क्योंकि प्रौद्योगिकी जहां एक ओर कुछ पारंपरिक नौकरियों को समाप्त करती है, वहीं दूसरी ओर अनेक नए रोजगार के अवसर भी सृजित करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में रोजगार: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र ने पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व विकास किया है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह क्षेत्र लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ी है।

स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार: प्रौद्योगिकी ने स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया है। आज अनेक युवा उद्यमी तकनीक आधारित स्टार्टअप्स की स्थापना कर रहे हैं जो विभिन्न सेवाओं, जैसे कि ई-कॉमर्स, हेल्थटेक, एग्रीटेक, फिनटेक आदि में नवीन समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। ये स्टार्टअप न केवल नए उत्पाद और सेवाएं लाते हैं, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी हस्तक्षेप और रोजगार: डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के अंतर्गत ग्रामीण भारत में भी तकनीक की पहुँच बढ़ी है। अब गांवों में इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल उपकरणों की मदद से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और वित्तीय सेवाओं में सुधार आया है। इससे स्थानीय युवाओं को डिजिटल सेवा केंद्रों, ई-कॉमर्स डिलीवरी, मोबाइल मरम्मत, ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर मिले हैं।

कृषि में तकनीकी नवाचार: परंपरागत कृषि में तकनीकी हस्तक्षेप से न केवल उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि नए तरह के रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। ड्रोन तकनीक, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, मिट्टी परीक्षण उपकरण, कृषि ऐप्स आदि के उपयोग से कृषकों को वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है। इन सेवाओं के संचालन, मरम्मत और प्रशिक्षण में भी युवाओं को रोजगार मिला है।

ऑनलाइन शिक्षा और ई-लर्निंग: कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने एक नया आयाम प्राप्त किया। तकनीक आधारित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतू आदि ने हजारों शिक्षकों, कंटेंट राइटर्स, वीडियो एडिटर्स और तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार दिया है।

गिग इकॉनॉमी और फ्रीलांसिंग: प्रौद्योगिकी के माध्यम से गिग इकॉनॉमी का उदय हुआ है। लोग अब स्वतंत्र रूप से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपवर्क, फ्रीलैन्सर, फीवर आदि पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे पारंपरिक रोजगार ढांचे से हटकर लचीले और आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर मिले हैं।

ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स: अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिशो आदि जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने हजारों लोगों को वितरण, पैकेजिंग, कस्टमर सपोर्ट और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में रोजगार दिया है। छोटे विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिला है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी प्रगति: टेलीमेडिसिन, हेल्थ ऐप्स, ई-फार्मेसी और एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स ने चिकित्सा क्षेत्र में नए रोजगार उत्पन्न किए हैं। तकनीकी जानकारों के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी नए अवसर सृजित हुए हैं।

डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट निर्माण: सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति ने डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसे नए क्षेत्र खोले हैं। यह क्षेत्र युवाओं के लिए एक सशक्त स्वरोजगार का माध्यम बन गया है।

हरित प्रौद्योगिकी और संवहनीय विकास: नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार ने नई प्रकार की नौकरियों को जन्म दिया है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन भी संभव हुआ है।

फिनटेक यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी का मतलब वित्त से संबंधित कार्य हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग और ऐसे कार्य करने वाली कंपनी को फिनटेक कंपनी कहा जाता है ।

फिनटेक नवोन्मेष के सक्रिय क्षेत्र:

क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल कैश: क्रिप्टोकरंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है और इसका नियंत्रण किसी एक संस्था के पास नहीं होता। यह सुरक्षित, पारदर्शी और नामरहित लेनदेन की सुविधा देती है। डिजिटल कैश पारंपरिक मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो बैंकों या सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। यह ऑनलाइन लेनदेन को तेज और सुविधाजनक बनाती है।

ब्लॉकचेन तकनीक: इसके तहत किसी केंद्रीय बहीखाते की बजाय कंप्यूटर नेटवर्क पर लेन-देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है।

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट: इसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से (अक्सर ब्लॉकचेन का उपयोग करते हुए) खरीददारों और विक्रेताओं के बीच अनुबंधों को स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाता है।

ओपन बैंकिंग: ओपन बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत बैंक नए एप्लीकेशन और सेवाओं को विकसित करने हेतु तीसरे पक्ष को अपने 'एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (एपीआई) की सुविधा प्रदान करते हैं। ओपन बैंकिंग के तहत कार्यरत बैंकों को फिनटेक के साथ प्रतिस्पर्द्धा की बजाय साझेदारी करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

इंश्योर टेक: इसके तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बीमा उद्योग को सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया जाता है।

रेगटेक: रेग टेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी यानी विनियामक प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग व्यवसायों को कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के नियमों का पालन करने में सहायता के लिए किया जाता है।

साइबर सुरक्षा: देश में साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि और विकेंद्रीकृत डेटा के कारण फिनटेक तथा साइबर सुरक्षा के मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

फिनटेक से जुड़ी संभावनाएँ:

व्यापक वित्तीय समावेशन: वर्तमान में भी देश की एक बड़ी आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है। वित्तीय प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से पारंपरिक वित्तीय और बैंकिंग मॉडल में वित्तीय समावेशन से जुड़ी चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। व्यापक वित्तीय समावेशन करना बहुत जरूरी है। एमएसएमई क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में देश में सक्रिय 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' के अस्तित्व के लिए पूंजी का अभाव सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। बहरहाल, कई फिनटेक स्टार्टअप द्वारा आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर एमएसएमई को कई बार बैंक जाने और जटिल कागज़ी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी।

ग्राहक अनुभव और पारदर्शिता में सुधार: फिनटेक स्टार्टअप सहूलियत, पारदर्शिता, व्यक्तिगत , और व्यापक पहुँच तथा उपयोग में सुलभता जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो ग्राहकों को सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। ग्राहक अनुभव और पारदर्शिता में सुधार भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए कि फिनटेक स्टार्टअप सहूलियत, पारदर्शिता, व्यक्तिगत और व्यापक पहुँच तथा उपयोग में सुलभता जैसी महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो ग्राहकों को सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। यही वजह है कि फिनटेक उद्योग द्वारा जोखिमों के आकलन के लिए अद्वितीय और नवीन मॉडल का विकास किया जाएगा, जिसके तहत बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ऋण जोखिम के निर्धारण हेतु वैकल्पिक डेटा का लाभ उठाकर और सीमित क्रेडिट इतिहास वाले ग्राहकों के लिए क्रेडिट स्कोर विकसित कर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार लाने में सहायता प्राप्त होगी।

फिनटेक उद्योग द्वारा जोखिमों के आकलन के लिये अद्वितीय और नवीन मॉडल का विकास किया जाएगा।

बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ऋण जोखिम के निर्धारण हेतु वैकल्पिक डेटा का लाभ उठाकर और सीमित क्रेडिट इतिहास वाले ग्राहकों के लिये क्रेडिट स्कोर विकसित कर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार लाने में सहायता प्राप्त होगी।

प्रौद्योगिकी का विकास एक ओर जहां कुछ पारंपरिक नौकरियों को अप्रासंगिक बना देता है, वहीं दूसरी ओर यह नवीन क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार भी खोलता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समय के साथ स्वयं को भी तकनीकी रूप से दक्ष बनाएं। शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी कौशल को शामिल करना, युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और सरकारी नीतियों को इस दिशा में सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी को एक खतरे की बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो समाज के समग्र विकास में सहायक हो सकती है।

रमेश कुमार
आर.एल.पी., रायपुर

जलवायु परिवर्तन और कृषि नवाचार: भारत की कृषि का भविष्य

वर्षों से जारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण भारत में औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1901–2018 की अवधि में भारत का औसत तापमान लगभग 0.7°C बढ़ चुका है। साथ ही, समुद्री सतह तापमान में भी वृद्धि हुई है। इस वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभाव स्वरूप भारतीय मानसून अस्थिर हुआ है और अत्यधिक मौसमीय घटनाएँ बढ़ी हैं। इन मौसमीय घटनाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष है। हाल ही में किए गए अध्ययन में पाया गया कि जनवरी-सितंबर 2024 के दौरान लगभग प्रत्येक दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में अतिवृष्टि, सूखा या अन्य बड़ी मौसमी घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं की वजह से वर्ष 2024 तक कुल 32 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई तथा लगभग 10 हजार पशुओं की मृत्यु हुई। यह आंकड़े देश में बढ़ते जलवायु-जोखिम की गंभीरता को दर्शाते हैं।

मॉनसून में भी मौसमी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की समय-सीमा और वितरण अस्थिर हो गया है। उदाहरणार्थ, जून 2023 में मॉनसून के देर से शुरू होने और अल नीनो प्रभाव जैसी वैश्विक घटनाओं के कारण कई क्षेत्रों में जलवायु असंतुलन बना रहा। बरसात का समय पहले या बाद में आना, अत्यधिक बारिश के बाद अचानक सूखा पड़ना जैसी स्थितियां कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इन सभी परिवर्तनों का परिणाम हिमालय और आसपास के मैदानों में जलस्रोतों की कमी, भूजल संकट एवं सिंचाई संकट के रूप में सामने आ रहा है।

कृषि पर प्रभाव:

जलवायु परिवर्तन की इन तमाम चुनौतियों का सबसे सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है। तापमान वृद्धि और असामान्य वर्षा से प्रमुख फसलों की उत्पादकता घटने लगी है। आईसीएआर की रिपोर्ट (एनआईसीआरए) के मुताबिक यदि अनुकूलन उपायों को न अपनाया गया तो वर्षा पर निर्भर धान की पैदावार 2050 तक 20% और 2080 तक 47% तक घटने की आशंका है। सिंचित धान में अपेक्षाकृत कम गिरावट (2050 में 3.5%, 2080 में 5%) का अनुमान है। गेहूं की पैदावार पर भी गहरा असर पड़ेगा – 2050 तक अनुमानित 19.3% और 2080 तक 40% तक की गिरावट का आकलन है। इसी तरह, खरीफ मक्का की पैदावार 2050-2080 में लगभग 18-23% तक घटने का अनुमान है। इन गिरावटों के कारण खाद्यान्न की कुल आपूर्ति प्रभावित होगी और किसानों की आय पर गंभीर दबाव पड़ेगा।

नवीनतम आकलनों के अनुसार भारत के प्रमुख धान और गेहूं उत्पादन में 6-10% तक की कमी हो सकती है। यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारत की लगभग 80% जनसंख्या सब्सिडी वाले अनाजों पर निर्भर करती है। 2023-24 में भारत ने 113.29 मिलियन टन गेहूं और 137 मिलियन टन धान की फसल ली थी, जो 14 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यदि जलवायु परिवर्तन के कारण इन प्रमुख फसलों का उत्पादन गिरता है, तो घरेलू खाद्यान्न सुरक्षा पर संकट गहरा जाएगा।

कृषि नवाचारों की भूमिका:

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कृषि नवाचारों की अहम भूमिका है। इन नवाचारों के अंतर्गत कई क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

- **जलवायु-प्रतिरोधी फसलों का विकास:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत राष्ट्रीय जलवायु-प्रतिरोधी कृषि (एनआईसीआरए) परियोजना ने सूखा/बाढ़ सहिष्णु किस्मों पर काम किया है। वर्ष 2014 से अब तक 1,888 से अधिक ऐसी जलवायु-प्रतिरोधी फ़सलों की किस्में विकसित की जा चुकी हैं, इनमें सूखा सहिष्णु धान, बाढ़-प्रतिरोधी गेहूं, चना-ज्वार की सूखा-प्रतिकारक किस्में आदि शामिल हैं। इन्हें खेत में उपलब्ध कराने से चरम मौसम में भी फसल उगाने की क्षमता बढ़ती है।
- **स्मार्ट कृषि (एआई, आईओटी, सैटेलाइट डेटा आदि):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण आधारित तकनीकों का उपयोग खेती को अधिक कुशल और लचीला बना रहा है। उदाहरण के लिए, सरकार ने किसान ई-मित्र नामक बहुभाषी एआई-चैटबोट विकसित किया है, जो किसानों को प्रधानमंत्री योजनाओं की जानकारी देता है। इसी तरह आईसीएआर ने आईओटी आधारित सिंचाई सिस्टम विकसित किए हैं जो मिट्टी और मौसम डेटा के आधार पर स्वचालित जल प्रबंधन करते हैं। निजी क्षेत्र में स्टार्टअप्स ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है: बेंगलुरु की कंपनी क्रोपिन, उपग्रह छवियों और मौसम विश्लेषण का उपयोग कर किसानों को परिशुद्ध कृषि की सलाह देती है।
- **टिकाऊ सिंचाई तकनीक:** जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई विधियाँ जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। भारत की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" इसके तहत माइक्रो-इरिगेशन

को बढ़ावा देती है। उदाहरणस्वरूप, इज़राइल की अग्रणी कंपनी नेटाफिम द्वारा विकसित ड्रिप इरिगेशन तकनीक से फसल की जड़ तक सीधे पानी पहुँचाने पर 50-70% तक जल की बचत हो सकती है। महाराष्ट्र में इस तकनीक का प्रयोग करने वाले गन्ना किसान पानी की खपत में 40% तक की कमी और उत्पादन में 20% तक की वृद्धि की सूचना देते हैं।

- **कार्बन फुटप्रिंट कम करने वाले उपाय:** कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और टिकाऊ प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं। भारत में कृषि-वनरोपण और मैंग्रोव आधारित कार्बन परियोजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इससे ग्रामीण आमदनी बढ़ने के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। साथ ही, मिट्टी संरक्षण, जैविक खेती और जैविक उर्वरक जैसे उपायों से नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है।
- **सटीक कृषि (प्रिसिशन फार्मिंग):** जीपीएस, सेंसर और ड्रोन जैसी तकनीकों से अब खेतों की सूक्ष्म मॉनिटरिंग हो रही है। पानी, उर्वरक और कीटनाशक का खपत वांछित मात्रा तक नियंत्रित करने से लागत घटती है। हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार कृषि क्षेत्र में एआई-आधारित सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है; वर्ष 2023 में भारतीय एआई-खेती बाज़ार का आकार $1.7 बिलियन था और यह 2028 तक $4.7 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है, सीएजीआर 23% ।

इन सभी नवाचारों ने कृषि उत्पादन को अधिक लचीला और संसाधनों के प्रति संजीदा बनाया है। तेलंगाना में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल में एआई-चालित मिट्टी की जाँच और डिजिटल मार्केटप्लेस के प्रयोग से मिर्च किसानों की पैदावार में 21% की वृद्धि हुई और बिक्री मूल्य 8% तक बढ़ गया। इस प्रकार के सफल प्रयोग दर्शाते हैं कि नवाचार भारतीय कृषि में तेजी से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

नवाचारों को अपनाने की वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ:

भारत में कई नवाचारी प्रयास शुरू हो चुके हैं पर इनके समुचित विस्तार में चुनौतियाँ भी हैं। देश के कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय नई प्रौद्योगिकियाँ विकसित कर रहे हैं, लेकिन उनका तेजी से प्रसार सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण रुक जाता है। सबसे बड़ी बाधा छोटे एवं मझोले किसानों की वित्तीय स्थिति है। अधिकांश कृषक 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करते हैं, उनकी आय सीमित है और नवोन्मेष को अपनाने का जोखिम वहन कर पाना उनके लिए मुश्किल है।

तकनीकी अवसंरचना की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण इलाकों में बिजली-अक्षमता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और डिजिटल साक्षरता में अंतर से किसानों को आधुनिक तकनीक सीखने में कठिनाई होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में समन्वित प्रयास हों। संक्षेप में कहा जाए तो: तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना, ऋण समर्थन और बीमा योजनाओं का विस्तार करना, तथा किसानों की जागरूकता बढ़ाना और प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार की योजनाएँ

सरकार ने कृषि सेक्टर में जलवायु जोखिम को कम करने और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं:

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्रॉप मोर क्रॉप":** यह योजना खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने से छोटी-छोटी जल स्रोतों से भी पर्याप्त सिंचाई संभव हो रही है। पीएमकेएसवाई के तहत अब तक लाखों हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे किसानों की पैदावार और आय दोनों में सुधार हुआ है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:** यह व्यापक बीमा कवरेज प्रदान कर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाती है। पीएमएफबीवाई के तहत धान, गेहूं सहित लगभग सभी खाद्यान्न, तेलहन और व्यावसायिक फसलों का बीमा किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के प्रति प्रोत्साहित करना है।
- **राष्ट्रीय संवहनीय कृषि मिशन एवं एनआईसीआरए:** राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की एक प्रमुख मुहिम है, जिसका लक्ष्य कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना है। इसी कड़ी में 2011 में एनआईसीआरए परियोजना शुरू की गई, जिसके तहत सूखा, बाढ़, गर्मी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए नयी तकनीक और किस्में विकसित की जा रही हैं। पिछले वर्षों में इनका कई संवेदनशील जिलों में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है।

कृषि वित्तीय समर्थन और बैंकिंग की भूमिका:

जलवायु-स्मार्ट कृषि के प्रसार में वित्तीय संस्थाओं का भी विशेष योगदान हो सकता है। वर्तमान में निजी क्षेत्र का कृषि में निवेश काफी हद तक जोखिमपूर्ण समझा जाता है। शोध बताते हैं कि कृषि एवं उद्योग को जीरो कार्बन बनाने के लिए अलग-अलग वित्तीय तंत्र चाहिए, क्योंकि कृषि को अक्सर "अस्तित्व के लिए उत्सर्जन" (सर्वाइवल एमिशन) माना गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा एवं परिवहन के बाद कृषि भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है (लगभग 14.5%) लेकिन

निजी जलवायु फंडिंग में इसकी हिस्सेदारी 4% से भी कम है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ जलवायु-स्मार्ट कृषि को अक्सर जोखिम भरा मानती हैं। इससे किसानों को कर्ज प्राप्ति में कठिनाई होती है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि नाबार्ड और सिडबी जैसे विकास बैंक को जलवायु हितैषी विशेष क्रेडिट स्कीम और ऋण योजनाएँ स्थापित करनी चाहिए। इनसे किसानों को लघु अवधि के ऋण सब्सिडी और गारंटी मिल सकेगी।

सुझाव और नीतिगत सिफारिशें:

भारत की कृषि को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

1. **नीतिगत कदम:** कृषि नीति में जलवायु-स्मार्ट दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि नीति में अनुकूलन रणनीतियाँ शामिल करनी चाहिए, जैसे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, जलवायु जोखिम आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली विकसित करना, और कृषि अनुसंधान को जलवायु केन्द्रित करना।
2. **वित्तीय उपाय:** कृषि नवाचारों को सब्सिडी एवं कर्ज़ सुविधा देने से तेजी से अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ड्रिप इरिगेशन लगाने पर अधिक सब्सिडी, सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्पों पर छूट, या कार्बन क्रेडिट के रूप में किसानों को इनाम। विकास बैंक (नाबार्ड, एसआईडीबीआई) और वाणिज्यिक बैंक मिलकर हरित कृषि ऋण के विशेष कोष बनाएँ, जिसमें आसान चुकौती शर्तें हों।
3. **शैक्षिक/प्रशिक्षण:** किसानों को नई तकनीक और जलवायु परिवर्तन के विषय में शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र तथा किसानों के सहयोगी समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना आदि।
4. **अनुसंधान एवं विकास:** जलवायु-हितैषी कृषि प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाया जाए। इसमें सिंचाई के नए तरीकों के साथ-साथ एकाधिक फसल आधारित तकनीकें, जलवायु-प्रतिरोधी बीज, जैविक उर्वरक आदि शामिल हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से नवोन्मेष केंद्र स्थापित कर अंतरराष्ट्रीय सहयोग (जैसे नासा, आईएसआरओ, सीजीआईएआर) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन उपायों से कृषि क्षेत्र में नवाचारों को अपनाने की गति बढ़ेगी और भारत की कृषि दीर्घकालीन रूप से अनुकूल एवं विकासशील बनेगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ असमय नहीं रुकेंगी, लेकिन उचित नीतिगत, वित्तीय और शैक्षिक हस्तक्षेप से भारत अपनी कृषि को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है।

बृजेश कुमार शुक्ला
यू.एल.ए, हैदराबाद

विकसित भारत

ग्राम विकसित, शहर विकसित,
विकसित हो जब हर नर नारी,
तब ही बनता देश अग्रणी,
और तभी जागती आशा सारी।

सबका सपना हो साकार,
तभी लेगा विकसित भारत आकार,
शिक्षा विज्ञान और उन्नति,
हर कोना हो सृजन धार।

नारी शक्ति को बनाए आधार,
हर माँ बेटी को मिले अधिकार,
गो ग्रीन से स्वच्छ हो पर्यावरण हमारा,
हरा भरा हो आसपास हर किनारा।

सद्भाव शांति सच्चाई का पाठ,
विकसित भारत का हो यही रथ,
जन-जन का हो योगदान,
तब होगा साकार स्वप्न महान।

जब खुद जागोगे, देश जागेगा,
हर कोना रोशन हो जाएगा,
आम नागरिक जब बदल जाएगा,
तभी भारत विकसित देश कहलाएगा।

उपासना सिरसैया
क्षे.का., बड़ौदा

साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता का महत्व

बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल क्रांति ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। ऑनलाइन लेनदेन, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाई है और हमारे संचालन को अधिक कुशल बनाया है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि हमारे ग्राहकों और स्वयं हमारे लिए एक नए, अधिक जुड़े हुए भविष्य का मार्ग है। यह डिजिटल परिवर्तन अत्यधिक लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही नए जोखिम भी आते हैं।

साइबर सुरक्षा का अर्थ है प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का उपयोग करके सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम, डिवाइस और डेटा को साइबर हमलों से बचाना। इसका लक्ष्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करना और सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के अनधिकृत शोषण से बचाव करना है ।

मुख्य सिद्धांत (सीआईए ट्रायड):

- **गोपनीयता:** संवेदनशील जानकारी को निजी रखना, एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल जैसे उपकरणों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना कि डेटा केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है ।
- **अखंडता:** यह सुनिश्चित करना कि डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। सिस्टम को अपने पूरे जीवनचक्र में जानकारी की सटीकता और पूर्णता बनाए रखनी चाहिए ।
- **उपलब्धता:** यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम और डेटा अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहें, साथ ही साइबर हमलों जैसी बाधाओं से बचाव हो ।

बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते साइबर खतरे: प्रकार और प्रभाव:

सामान्य साइबर खतरे और उनसे बचाव के तरीके

खतरा:- फ़िशिंग/विशिंग/स्मिशिंग

संक्षिप्त विवरण - नकली ईमेल/एसएमएस/कॉल के माध्यम से व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी चुराने का प्रयास।

बचाव के उपाय - संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें; अनचाही जानकारी न दें; प्रेषक की पहचान सत्यापित करें; एंटी-वायरस/फ़ायरवॉल का उपयोग करें; ईमेल डोमेन और एचटीटीपीएस जांचें।

खतरा:- मैलवेयर/रैंसमवेयर

संक्षिप्त विवरण -दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करता है या डेटा को एन्क्रिप्ट कर फिरौती मांगता है।

बचाव के उपाय - एंटी-वायरस/एंटी-स्पाइवेयर सॉफ़्टवेयर अपडेट रखें; स्वचालित डाउनलोड अक्षम करें; अज्ञात स्रोतों से फ़ाइलें स्कैन करें; सुरक्षा पैच तुरंत लागू करें ।

खतरा:- पहचान की चोरी/खाता अधिग्रहण

संक्षिप्त विवरण - व्यक्तिगत जानकारी चुराकर ऑनलाइन खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना।

बचाव के उपाय - मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड/पासफ्रेज़ का उपयोग करें; बहु-कारक प्रमाणीकरण (एमएफ़ए) सक्षम करें; लॉगिन विवरण सहेजें नहीं; खातों की नियमित जांच करें।

खतरा:- सिम स्वैप

संक्षिप्त विवरण - मोबाइल नंबर का नियंत्रण प्राप्त कर दो-कारक प्रमाणीकरण (ओटीपी) को बायपास करना।

बचाव के उपाय - संदिग्ध गतिविधियों के लिए मोबाइल नेटवर्क प्रदाता से संपर्क करें; अनजान कॉल/एसएमएस से सावधान रहें; दो-कारक प्रमाणीकरण के लिए ऐप-आधारित ओटीपी को प्राथमिकता दें।

खतरा:- सार्वजनिक वाई-फाई का खतरा

संक्षिप्त विवरण - असुरक्षित सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा इंटरसेप्शन या हैकिंग का जोखिम।

बचाव के उपाय - सार्वजनिक वाई-फाई पर ऑनलाइन बैंकिंग या संवेदनशील लेनदेन से बचें; यदि आवश्यक हो तो विश्वसनीय वीपीएन का उपयोग करें ।

डिजिटल साक्षरता: डिजिटल साक्षरता व्यक्ति और समाज की डिजिटल तकनीकों को समझने और सार्थक कार्यों में इसका उपयोग करने की क्षमता है। यह नागरिकों को सूचना, ज्ञान और कौशल के माध्यम से सशक्त बनाता है, जिससे वे 'राष्ट्र निर्माण' में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल साक्षरता महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, शैक्षिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों तक अधिक सुगमता के साथ पहुँचने में मदद कर रही है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास में सुधार हुआ है ।

ऑनलाइन जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे करें:

- **नकली खबरों के प्रकार:**
- **व्यंग्य या पैरोडी:** हास्य के लिए बनाई गई सामग्री जो गलत समझी जा सकती है।
- **झूठे कनेक्शन:** क्लिकबेट शीर्षक जो सामग्री से मेल नहीं खाते।

- **भ्रामक सामग्री:** जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत की गई जानकारी।
- **नकली प्रसंग:** पुरानी जानकारी को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना।
- **धोखेबाज सामग्री:** किसी और का प्रतिरूपण करना।
- **हेरफेर की गई सामग्री:** सच्ची जानकारी में बदलाव करना (जैसे एडिट की गई तस्वीरें/वीडियो) ।
- **गढ़ी गई सामग्री:** पूरी तरह से गलत जानकारी ।

सत्यापन के तरीके:

- **गूगल रिवर्स इमेज सर्च:** किसी भी फोटो की उत्पत्ति और पूर्व उपयोग का पता लगाने के लिए। यह पता लगाने में मदद करता है कि फोटो पुरानी है, एडिट की गई है या किसी और देश की है।
- **पीआईबी फैक्ट चेक और सरकारी वेबसाइट्स:** सरकार से संबंधित किसी भी दावे की पुष्टि के लिए। PIB भारत सरकार का आधिकारिक स्रोत है और फेक खबरों की सच्चाई सामने लाता है।
- **स्रोत की विश्वसनीयता:** जानकारी के स्रोत की जांच करें। क्या यह एक प्रतिष्ठित समाचार संगठन है? क्या लेखक एक विशेषज्ञ है?
- **यूआरएल और डोमेन की जांच:** संदिग्ध यूआरएल या असामान्य डोमेन नामों से सावधान रहें।
- **अत्यधिक भावनात्मक भाषा:** ऐसी सामग्री से सावधान रहें जो अत्यधिक भावनात्मक या सनसनीखेज भाषा का उपयोग करती है।

सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के लिए आवश्यक आदतें:

- **लोकेशन सेवाएँ बंद रखें:** अनावश्यक रूप से अपना लोकेशन साझा करने से बचें ।
- **सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करते समय सतर्क रहें:** मुफ्त सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट हैकर्स के लिए एक जाल हो सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो एक अच्छा पेड वीपीएन का उपयोग करें ।
- **पिन या ओटीपी कभी साझा न करें:** नेट बैंकिंग या शॉपिंग करते समय अपना पिन या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। बैंक या कोई भी वैध संस्था आपसे फोन/ईमेल पर ये जानकारी नहीं मांगेगी।
- **बच्चों और बुजुर्गों को शिक्षित करें:** घर के बच्चों और बुजुर्गों को इंटरनेट सुरक्षा और सावधानियों के बारे में जागरूक करें, क्योंकि वे साइबर अपराधियों के आसान शिकार होते हैं ।

ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन में सुरक्षा: आपकी और बैंक की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर जोखिमों से बचाने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचा स्थापित किया है। यह ढाँचा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है।

प्रमुख दिशानिर्देश और नियंत्रण:

- **आईटी परिसंपत्ति प्रबंधन:** हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सहित सभी आईटी आस्तियों की अद्यतन सूची बनाए रखना और उनकी संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकरण करना।
- **अनधिकृत सॉफ़्टवेयर निष्पादन की रोकथाम:** दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर से जुड़े जोखिमों को कम करना।
- **नेटवर्क सुरक्षा:** नेटवर्क में डेटा को एन्क्रिप्ट करना, भेद्यता मूल्यांकन और पैठ परीक्षण करना।
- **सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन:** सिस्टम और एप्लिकेशन को सुरक्षित रूप से कॉन्फ़िगर करना।
- **एप्लिकेशन सुरक्षा जीवनचक्र:** परिनियोजन से पहले भेद्यता मूल्यांकन और पैठ परीक्षण करना।
- **उपयोगकर्ता एक्सेस कंट्रोल:** मजबूत प्रमाणीकरण तंत्र (बहु-कारक प्रमाणीकरण सहित) स्थापित करना और उपयोगकर्ता एक्सेस अधिकारों की नियमित समीक्षा करना।
- **ग्राहक जागरूकता:** ग्राहकों को सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना और धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम प्रणालियों को लागू करना।

नए पहल:

- **दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (एएफ़ए):** भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफ़ए)' लागू करने की योजना बनाई है। घरेलू ऑनलाइन भुगतान के लिए अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन (एएफ़ए) पहले से अनिवार्य है ।
- **सारथी और प्रवाह पहल:** भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आंतरिक कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाने के लिए 'सारथी' (जनवरी 2023) और नियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 'प्रवाह' (मई 2024) जैसी पहल शुरू की हैं, जो केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग से सुसज्जित हैं ।
- **वित्तीय साक्षरता अभियान:** भारतीय रिजर्व बैंक, एनसीएफ़ई के माध्यम से वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम चलाता है, जिसमें बचत, उधार, ब्याज और जोखिम जैसे मौलिक सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। वे वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिकाएँ और मोबाइल संदेश भी जारी करते हैं ।

ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा युक्तियाँ: आपकी व्यक्तिगत भूमिका:

यदि कोई व्यक्ति अनजाने में अपने क्रेडेंशियल से समझौता करता है या सामाजिक इंजीनियरिंग के झांसे में आता है (उदाहरण के लिए, ओटीपी साझा करना), तो सबसे मजबूत तकनीकी सुरक्षा को भी बायपास किया जा सकता है। यह व्यक्ति को सुरक्षा श्रृंखला में "अंतिम कड़ी" बनाता है।

सुरक्षित ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

मजबूत और अनोखा पासवर्ड - प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए एक अलग, लंबा (कम से कम 12 वर्ण), और जटिल पासवर्ड (अक्षर, संख्या, प्रतीक का मिश्रण) का उपयोग करें।

बहु-कारक अधिप्रमाणन (एमएफ़ए) - जहाँ भी संभव हो, एमएफ़ए सक्षम करें। यह पासवर्ड के अलावा एक अतिरिक्त सत्यापन चरण (जैसे ओटीपी या बायोमेट्रिक्स) जोड़कर सुरक्षा को बढ़ाता है ।

सॉफ्टवेयर और ऐप अपडेट - अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र और सभी बैंकिंग ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट रखें।

सार्वजनिक वाई-फाई से बचें - ऑनलाइन बैंकिंग या अन्य संवेदनशील लेनदेन के लिए असुरक्षित सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग न करें। हैकर्स इन नेटवर्क पर आसानी से डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसके बजाय मोबाइल डेटा या सुरक्षित निजी नेटवर्क का उपयोग करें ।

संदिग्ध लिंक/अटैचमेंट पर क्लिक न करें- अज्ञात या संदिग्ध स्रोतों से आने वाले ईमेल या SMS में भेजे गए लिंक या अटैचमेंट पर कभी क्लिक न करें। ये फ़िशिंग या मैलवेयर हमले हो सकते हैं ।

ओटीपी/पिन/सीवीवी साझा न करें- अपना वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी), पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (पिन), या कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (सीवीवी) किसी के साथ, यहाँ तक कि बैंक के कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के साथ भी साझा न करें।

खातों की नियमित जांच -अपने बैंक स्टेटमेंट और लेनदेन इतिहास की नियमित रूप से जांच करें ताकि किसी भी असामान्य या अनधिकृत गतिविधि का तुरंत पता चल सके ।

वेबसाइट की प्रामाणिकता जांचें - ऑनलाइन बैंकिंग करते समय, सुनिश्चित करें कि वेबसाइट का URL "https://" से शुरू होता है और उसमें एक पैडलॉक आइकन है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए. Bank.in या. Fin.in जैसे विशिष्ट डोमेन नामों की तलाश करें ।

व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने में सावधानी - गूगल फॉर्म, विज्ञापनों या संदिग्ध लिंक पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी ऑनलाइन दर्ज न करें। हमेशा सीधे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें ।

धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें - किसी भी संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी के प्रयास, या साइबर घटना की तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें ।

बैंक द्वारा अपनाई गई साइबर सुरक्षा नीतियां और उपाय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापक साइबर सुरक्षा ढाँचे का पालन करता है, जिसमें आईटी परिसंपत्ति प्रबंधन, नेटवर्क सुरक्षा, सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन, एप्लिकेशन सुरक्षा और उपयोगकर्ता एक्सेस कंट्रोल जैसे आधारभूत नियंत्रण शामिल हैं। बैंक की साइबर सुरक्षा के प्रयास एक सतत यात्रा है, जिसमें प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और मानव पूंजी में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है।

कर्मचारियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण का महत्व: कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा से संबन्धित खतरों से निपटने के लिए ज्ञान से लैस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व की प्रतिबद्धता साइबर लचीलेपन की कुंजी है । इसके बिना, प्रभावी प्रक्रियाओं को स्थापित करना या लागू करना कठिन है। नियमित साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षणों में फ़िशिंग सिमुलेशन और "जीरो ट्रस्ट" मानसिकता को अपनाना शामिल होना चाहिए, जहाँ किसी भी अनुरोध या स्रोत पर तब तक भरोसा नहीं किया जाता जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए।

साइबर घटनाओं की रिपोर्ट और सहायता:

किसी भी संदिग्ध गतिविधि या साइबर घटना को तुरंत रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है। देरी से बड़ा नुकसान हो सकता है।

रिपोर्टिंग प्रक्रिया:

- तत्काल अपने विभाग प्रमुख और आईटी/साइबर सुरक्षा टीम को सूचित करें।
- बैंक द्वारा निर्दिष्ट आंतरिक रिपोर्टिंग चैनलों का उपयोग करें।
- किसी भी साइबर घटना को रिपोर्ट कर सकते हैं या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। https://cybercrime.gov.in/ से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नीरज कुमार गुप्ता
वित्त एवं लेखा,
कें.का., मुंबई

Economic Leadership and Financial Inclusion

India stands at a breath-taking crossroad. As the nation charts its course towards its centenary of independence in 2047, the ambition isn't just to be an economic giant, but a developed one – a vision where prosperity is shared, growth is sustainable and every citizen is an active participant "Sabka Sath- Sabka Vikash- Sabka Vishwas". At the very heart of this monumental quest lie two inseparable forces: robust economic leadership that fuels innovation and investment and profound financial inclusion that empowers every individual. These aren't parallel tracks, they are strands of the same rope pulling India towards its destiny. And India's banking sector? It's not just a spectator, it's the master weaver, uniquely positioned to intertwine these strands into a fabric of unprecedented national progress.

"Banks are master weavers of India's progress"

What does "economic leadership" truly mean for India today? It's about cultivating industries that compete globally, empowering a new generation of entrepreneurs brimming with ideas and financing the arteries of a modern nation – its infrastructure. The goal is a GDP rocketing towards an estimated $10 trillion by 2035. But this grand vision remains incomplete if its fruits don't reach everyone.

This is where financial inclusion transforms from a social goal into an economic imperative. It's about ensuring the farmer in a remote village, the gig worker navigating the bustling city and the woman entrepreneur dreaming big, all have the tools – banking, credit, savings, insurance – to not just survive, but to thrive and contribute.

Think of it as a virtuous cycle:

- Inclusive finance provides the fuel – consumption, savings, investment – for individual and local economies.
- A robust, growing national economy, in turn, creates more demand for financial services and offers more opportunities for those newly included.

Banks, with vast network of over 1.6 lacs branches and a digital nervous system supercharged by the revolutionary Unified Payments Interface (UPI), are the natural linchpins of this synergy. They possess the scale, the trust and increasingly, the technological prowess. Yes, challenges like the last-mile gap in rural areas or the operational costs of serving diverse populations persist. But by fundamentally reimagining their role, banks can do more than just bridge these divides. The critical question is no longer if banks should lead, but how they can innovate to power India's economic journey, ensuring no one is left behind.

Mapping the Terrain: India's Inclusion Gaps

India's financial inclusion progress is remarkable—PMJDY brought 500 million into banking and UPI processes ~135 billion transactions yearly. Yet, gaps remain:

- **Access Divide:** 200 million adults (20%) lack bank accounts, especially in rural areas.
- **MSME Credit Gap:** MSMEs, contributing 30% to GDP, face a ₹20-25 trillion credit shortfall.
- **Digital Disparity:** Urban digital banking thrives, but rural adoption lags due to illiteracy and infrastructure issues.
- **Gender Gap:** Only 27% of women access formal credit vs. 52% of men. Banks have channelled ₹60 trillion to MSMEs, infrastructure and start-ups but face challenges like rural expansion costs and fintech competition.

These are opportunities to tap millions of new customers, driving sustainable growth. Those currently unbanked or underbanked – rural households, women, informal sector workers – represent millions of potential customers. By strategically addressing these gaps, banks aren't just fulfilling a social mandate, they are unlocking new avenues for sustainable growth and profitability.

Forging Transformative Growth

To spearhead India's journey to 2047, banks need more than incremental changes. They need a bold, multifaceted strategy– one that's audacious, technology-driven, deeply human-centric and relentlessly collaborative. Here are some actionable strategies poised for transformative impact:

Digital Frontiers: Technology as the Great Equalizer

Technology isn't just an enabler, it's the cornerstone of scalable, affordable inclusion.

- Embrace India's world-class Digital Public Infrastructure (DPI) – Aadhaar for identity, UPI for payments, e-KYC for seamless onboarding.
- The agility of fintech is a powerful complement to the scale of banks. Collaborative ventures can deliver hyper-local solutions – think micro-savings apps tailored for daily wage earners, or instant, UPI-powered micro-loans for street vendors, perhaps through a partnership with a platform like Paytm.
- AI can analyse alternative data streams to assess the creditworthiness of informal workers, opening up a vast, previously inaccessible market. Personalized financial advice and dynamic interest rates, powered by AI, can also revolutionize customer engagement and retention.
- Move beyond traditional credit scoring: These moves can slash operational costs by 30-40%, bring an estimated 50 million unbanked individuals into the fold and significantly boost transaction volumes.

Fuelling India's Growth Engines

Generic financial products won't cut it. Banks must craft solutions finely tuned to the needs of India's economic powerhouses:

- **Empower MSMEs and Start-ups:** Go beyond traditional lending. Offer collateral-free loans leveraging schemes like PM Mudra Yojana. Provide sophisticated trade finance solutions for India's 80,000+ start-ups. Consider dedicated "Start-up Banking" divisions offering credit lines up to ₹10 crore, mentorship and networking – capturing high-potential clients early.
- **Cultivate Sustainable Agriculture:** India's farmers need more than just loans, they need financial partnership. Develop "crop-cycle" loans perfectly synchronized with harvest seasons. Champion green finance by offering accessible loans for solar irrigation pumps – financing 1 million such pumps at, say, 5% interest, could transform rural energy reliance and align with our ambitious net-zero goals.
- **Build Tomorrow's Infrastructure:** India's $1.5 trillion infrastructure vision (roads, railways, smart cities, renewable energy) needs robust financial backing. Banks can provide the long-term, strategically-priced capital essential for these nation-building projects.

These focused initiatives can significantly shrink the ₹20 trillion MSME credit gap, catalyse the creation of millions of jobs and fortify bank loan portfolios with diversified, high-impact assets.

Nurturing Financial Resilience

True inclusion extends beyond a bank account, it's about building lasting financial well-being.

- **Embed Financial Literacy Everywhere:** Launch engaging campaigns in vernacular languages. Develop intuitive app tutorials that demystify digital banking. Partner with NGOs to conduct, for instance, 10,000+ financial literacy workshops in villages, building trust and significantly reducing vulnerability to fraud.
- **Design for Resilience:** Craft products that meet real-life needs. Offer affordable micro-insurance (health, crop, life) and accessible high-yield savings schemes for low-income groups. A simple ₹500 monthly recurring deposit for gig workers can become a powerful tool for wealth creation.
- **Champion Women's Economic Empowerment:** This is a game-changer. Introduce zero-fee accounts specifically for women. Forge deeper partnerships with Self-Help Groups (SHGs), leveraging their community trust to disburse credit and promote financial discipline. Targeting 10 million women isn't just a number, it's unlocking a market with exponential potential.
- **Impact Snapshot:** These efforts cultivate deep customer loyalty, attract stable deposits and drive profound social equity, strengthening the very fabric of communities.

Collaborative Innovation:

No single entity can achieve this monumental task alone. Collaboration is the accelerator:

- **Fintech and Telco Synergies:** Imagine UPI-linked digital wallets co-created with telecom giants like Jio or Airtel, seamlessly integrated for India's massive base of gig workers and mobile-first users, potentially reaching 400 million subscribers.
- **Start-up and NGO Alliances:** Tap into the innovative spirit of start-ups for cutting-edge financial apps. Leverage the deep community roots of NGOs for effective last-mile outreach and financial literacy programs. Supporting, for example, 1,000 women-led tech start-ups through bank-sponsored incubators can yield both social impact and brand elevation.

- **Strategic Government Tie-Ups:** Proactively align banking products and services with national missions like Start-up India, Skill India, or state-level agricultural initiatives, ensuring policy synergy and maximizing impact.
- **Impact Snapshot:** Partnerships fast-track innovation, slash time-to-market for new products and help banks connect with younger, tech-savvy demographics more effectively.

The Vital Role of Policy and Regulation

The Reserve Bank of India (RBI) and the government have been pivotal, laying the groundwork with initiatives like PMJDY, priority sector lending mandates, OCEN, ULI, BBPS and the UPI revolution. To truly unleash the banking sector's potential in this next phase, further strategic policy support is key:

- Consider targeted tax breaks for banks expanding their branch network in underserved rural areas. Simplify compliance requirements for micro-loans to reduce operational friction.
- Actively encourage and facilitate collaborations between banks, fintech's and state governments to co-fund initiatives.

Towards a Synergistic Future: Measuring Impact, Realizing the Vision

To navigate this transformative journey effectively, banks must anchor their strategies to clear, measurable outcomes:

- **Inclusion Metrics:** Track the number of new accounts opened (aiming for, say, 100 million new quality accounts by 2030), the volume of rural loan disbursals and the penetration of banking services among women.
- **Economic Impact Metrics:** Monitor the growth in MSME credit, the quantum of startup financing and the volume of loans channelled towards infrastructure development.
- **Digital Adoption Metrics:** Measure the year-on-year growth in UPI transactions, the uptake of digital banking services in Tier 2/3 cities & rural areas and the reach of financial literacy programs.

By weaving these goals into their core business strategy, banks will not only drive their own growth but also become powerful engines propelling India towards its 2047 vision: a $10 trillion economy where every citizen is financially empowered and resilient. This journey perfectly aligns with overarching national priorities like Aatmanirbhar Bharat (Self-Reliant India), Digital India and the Sustainable Development Goals (SDGs), positioning banks as indispensable architects of national progress.

The transformative potential is truly immense. By strategically scaling digital banking, an additional 50 million individuals could be brought into the financial mainstream. By thoughtfully closing the MSME credit gap, an estimated 10 million new jobs could be created. By specifically empowering women, banks can unlock the immense potential of 48% of India's human capital. These endeavours are not just about bottom lines, they are about building a legacy – a legacy of banks as catalysts for an inclusive, equitable and prosperous India.

Conclusion: A Clarion Call to Action with a Global Lens

India's ascent to becoming a developed nation by 2047 demands a banking sector that is not just robust but also profoundly innovative, deeply inclusive and courageously visionary. The strategy is clear: embrace digital transformation as a force for good, tailor financial solutions to the nation's growth engines, empower communities with financial literacy & resilience and forge strategic partnerships that amplify impact.

This journey, while uniquely Indian in its context and scale, resonates with global trends in financial inclusion. For instance, the rapid adoption of mobile money in Sub-Saharan Africa has demonstrated the power of technology to leapfrog traditional banking infrastructure and bring financial services to previously unreached populations. Similarly, the burgeoning fintech sector in Latin America is pioneering innovative digital lending and payment solutions that cater to the underserved.

The collaborative spirit between Indian banks, fintech's and the government, if sustained and strengthened, could position India not just as an economic powerhouse, but also as a global leader in crafting and implementing a truly inclusive financial ecosystem. As Independent India marches confidently towards its centenary, its banks stand at a historic juncture. They have the opportunity – indeed, the responsibility – to lead not merely as financial intermediaries, but as architects of a future where every Indian dream has the financial wings to fly, offering a compelling blueprint for the world. The time for incremental change is past. The time for bold, decisive action is now.

Jeetendra Yadav
Digitization Vertical,
C.O. Mumbai

India's Journey Towards Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Goals, often called the Global Goals, are a worldwide call to action for a better and more sustainable future for everyone. They were agreed upon by all United Nations member countries in 2015, as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. This agenda gives us a shared plan for peace and prosperity for all people and our planet, now and in the future.

These goals build on earlier efforts, like the Millennium Development Goals, but they go much further by aiming to end all forms of poverty. There are 17 interconnected goals that cover a wide range of important challenges and opportunities facing humanity and nature. These include ending poverty and hunger, improving health and education, ensuring clean water and energy, promoting good jobs and economic growth, reducing inequalities, taking strong action on climate change, protecting oceans and lands for building resourceful societies.

A key idea behind the SDGs is that they are universal. This means they apply to all countries – whether rich, poor, or middle-income. They represent a shared vision for progress towards a safe, fair and sustainable world where everyone can thrive. Every country has a common responsibility to play its part in reaching this global vision and no one should be left behind. While all goals are important for everyone, different countries will focus their efforts differently based on their current situation, their unique challenges and the resources they have.

NITI Aayog: Leading India's SDG Plan

NITI Aayog, started in 2015, changed how India plans its development. It moved from a top-down approach to one that uses teamwork and smart thinking. NITI Aayog acts as a modern resource centre, helping with research, giving policy guidance and leading India's 2030 Agenda.

NITI Aayog's plan uses "cooperative and competitive federalism." This means it supports States and Union Territories (UTs) in tracking progress and working together. It also encourages healthy competition among them through tools like the SDG India Index, pushing them to achieve goals faster. This approach helps create local solutions and makes people more responsible, all contributing to the vision of Viksit Bharat.

Key Ways to Check Progress

To track India's SDG progress, NITI Aayog uses important tools:

- The SDG India Index is the main tool for checking progress at national and state levels. It uses 113 indicators to score each State and UT, giving clear pictures of their performance. The index has grown, showing India's increasing ability to use data for policy.
- The North-Eastern Region District SDG Index is a special index for districts in the eight north-eastern states, giving specific insights for that region.
- The National Multidimensional Poverty Index (MPI) helps measure progress in reducing poverty, showing that poverty nearly halved from 24.8% to 14.96% between 2015-16 and 2019-21.

India's Progress on SDGs: What the SDG India Index 2023-24 Shows

India's national SDG score has steadily improved: from 58 in 2018 to 71 in 2023-24. Many States and UTs are now "Front Runners" (scoring 65-99), with 32 in this group in 2023-24. States like Assam, Manipur, Punjab, West Bengal and Jammu and Kashmir showed big improvements.

In the following goals, good progress has been observed:

- **SDG 1 (No Poverty):** This goal has seen big progress, improving by 12 points from the 2020-21

version to 2023-24, moving from the "Performer" to the "Front Runner" group. The fact that multidimensional poverty was almost cut in half between 2015-16 and 2019-21 highlights its success.

- **SDG 7 (Affordable and Clean Energy):** India has achieved the highest score among all SDGs for this goal, greatly improving from 51 in 2018 to 96 in 2023-24. This amazing progress includes 100% household access to electricity under the Saubhagya Scheme and a big increase in access to clean cooking fuel (LPG + PNG) from 92.02% in 2020 to 96.35% in 2024.
- **SDG 8 (Decent Work and Economic Growth):** This area has also shown good progress, contributing to the overall national score improvement.
- **SDG 13 (Climate Action):** This goal had the biggest jump in score, rising from 54 in 2020-21 to 67 in 2023-24.
- **SDG 15 (Life on Land):** Good progress has been seen, with almost a quarter of India's land covered by forests and trees (as per the India State of Forest Report 2021) and a 1.11% increase in carbon stock.

Other SDGs showing improvement include SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 10 (Reduce Inequalities) and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities). Kerala remains a top-performing state, along with Tamil Nadu, Goa, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Chandigarh and Jammu & Kashmir lead among UTs.

While the overall national score is going up and many states are reaching "Front Runner" status, the fact that "Aspirant" and "Performer" groups still exist, along with mentions of states falling behind like Bihar and Jharkhand, shows unequal progress across the nation. This means that using the same approach to development might not be enough. The growth in "Front Runner" states shows successful policy work and the chance to copy good practices. However, the continued existence of lower-performing states highlights the need for specific actions. This unevenness means that NITI Aayog must work harder on its "cooperative federalism" efforts to help these lagging regions, possibly through more tailored support, specific money allocation and strong sharing of knowledge. While healthy competition among states drives some progress, it must be balanced with strong teamwork to avoid making differences worse and to make sure development includes everyone, truly building a Viksit Bharat.

India's Voluntary National Review (VNR) 2025: Working Together

India will present its third Voluntary National Review (VNR) report at the UN in July 2025. NITI Aayog is leading this report, which will show India's successes, challenges and lessons learned in reaching the SDGs.

The VNR preparation involves wide talks with many groups, showing an "everyone-involved" approach. This includes:

- **Civil Society Organizations (CSOs):** Special talks have been held, especially one focusing on forced labour and human trafficking, with a special focus on groups that are often left behind ("Leave No One Behind" - LNOB). Over 140 CSOs from 15 states took part in these talks, sharing problems and ideas for solutions. The findings from these talks will go into the VNR and also help create a separate CSO report for wider policy support.
- **Private Sector:** NITI Aayog held talks specifically about private sector involvement in reaching the SDGs and helping with the plan for Viksit Bharat 2047. The discussions covered spending for social good, the Corporate Social Responsibility (CSR) system, responsible business practices, charity and new business ideas. The ideas from these talks will be added to India's VNR, showing how good business practices can make things more sustainable, strong and new.
- **Farmers:** The Food and Agriculture Organization (FAO),

working with the Watershed Support Services and Activities Network (WASSAN), held national and regional talks involving over 300 farmers and CSO representatives as part of the VNR process. This way of involving everyone ensures that ideas from local communities and real-life views from the farming sector are included.

These wide talks help make the VNR more believable and useful by including real-life challenges and showing a commitment to "Leaving No One Behind," which is key to Viksit Bharat.

Challenges and What's Next

Despite good progress, India still faces challenges. SDG 5 (Gender Equality) is the only goal where India's score is below 50, showing a key area needing more focused effort.

India's SDG efforts are guided by the Prime Minister's idea of "Sabka Saath, Sabka Vikas", which matches the global goal of "Leaving No One Behind" and is essential for Viksit Bharat.

The accuracy of data is crucial for India's SDG progress. NITI Aayog, MoSPI and the UN have an agreement to support data and monitoring, showing how important reliable data is for good policy making and its implementation.

Keeping Up the Pace Towards 2030

India has made big steps towards the Sustainable Development Goals, thanks to NITI Aayog's leadership and its approach of teamwork, competition, strong tracking and wide involvement. The positive trends in the SDG India Index and the detailed VNR 2025 show India's strong commitment to the 2030 Agenda. India's journey is a good example of how global goals can be met through national plans and local actions.

Moving forward, it's vital to address challenges like Gender Equality to ensure development reaches everyone. This commitment aligns with "Leaving No One Behind" and India's vision for Viksit Bharat 2047.

Mani Bhushan Kumar
U.B.K.C, Bengaluru

दिनांक 05.05.2025 को श्री रामकृष्णपुरम शाखा, हैदराबाद-कोटी के ऑनसाइट एटीएम से पैसे निकालने के दौरान ग्राहक को अचानक दिल का दौरा पड़ा, ऐसे समय में श्री वंगरा श्रीधर बाबू ने तत्परता एवं सूझबूझ दिखाई और ग्राहक को सीपीआर दिया, जिससे 30 मिनट के पश्चात ग्राहक की तबीयत में सुधार हुआ। सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री कारे भास्कर राव, अंचल कार्यालय, हैदराबाद ने श्री वंगरा श्रीधर बाबू की फोन पर सराहना की तथा श्री सत्यम पलुगुला सिंहय्या, क्षेत्र प्रमुख, श्री एम महेश्वर स्वामी तथा श्री नन्द किशोर कुमार, उप क्षेत्र प्रमुख ने सम्मानित किया।

Renewable Energy and India's Future

India, with its strong population and rapid economic growth, stands tall facing a transformative energy future. As the world battles climate change, energy security and environmental degradation, renewable energy has emerged as a pivotal solution to meet the needs of the future. Being one of the largest energy consumers in the world, we are heavily dependent on fossil fuels, transitioning to renewable energy sources offers both a challenge and an opportunity. We could explore the role of renewable energy in India's future, the nation's current energy landscape, its renewable energy potential, the policies driving this transition, the challenges it faces and the prospects for a sustainable energy future.

India's Energy Landscape: Current Scenario

India, with a population of over 1.4 billion, is the third-largest energy consumer in the world. The country's rapid industrialization, urbanization and increasing standards of living have led to a steady rise in energy demand. However, majority of India's energy consumption is met through non-renewable sources, predominantly coal, oil, nuclear power and natural gas. Coal alone accounts for nearly 70% of India's total electricity generation. While these fossil fuels have supported India's economic development, they come with significant drawbacks: high greenhouse gas emissions, radiation hazard, environmental degradation and dependency on imported raw materials like nuclear fuel, oil and gas, which can lead to energy security concerns.

Due to price volatility in the global oil market and the environmental cost of burning fossil fuels It is a need of the hour to reduce dependency on commercial non-renewable energy sources. As the world becomes more conscious of climate change, the need for a cleaner, more sustainable energy future is pressing. Renewable energy offers a viable solution to reduce dependence on fossil fuels and mitigate the adverse environmental impacts.

India's Renewable Energy Potential

India is blessed with abundant renewable energy resources, making it one of the most promising countries in the world for the expansion of clean energy. The nation has tremendous potential in various forms of renewable energy, particularly solar and wind power.

1. **Solar Energy:** India is endowed with vast solar potential due to its geographic location. The country receives ample sunlight throughout the year, making it an ideal location for solar power generation. According to the National Institute of Solar Energy (NISE), India has a potential of around 750 GW from solar energy. In recent years, solar power has experienced rapid growth, with India becoming one of the world's largest markets for solar energy. Government backed schemes like 'PM Surya Ghar Muft Bijili Yojana' distributed through various channels especially public sector banks are expected to play a key role in the process. Such schemes also highlight the commitment of government in harnessing the solar energy.
2. **Wind Energy:** India's wind energy potential is more impressive, particularly in the coastal regions and in the states of Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra. The Indian Wind Energy Association estimates the total onshore wind energy potential at 302 GW. The country is already the fourth-largest producer of wind energy globally and the sector continues to grow rapidly, with substantial investments in both onshore and offshore wind farms.

   Unlike onshore wind turbines offshore ones are larger in size and due to lack of any obstruction they can contribute as a more stable renewable energy source unlike solar or hydel power. A single offshore wind turbine can be developed to produce upto 15 MW or even higher like 20MW capacity unlike common onshore ones that can produce a capacity of mere 2MW. India has vast coastline of several thousands of kilometers which holds a huge potential of approximately 300 GW estimated only through offshore wind farms which is more than 50 times when compared to the largest nuclear power project (6000 MW in Kudankulam, Tamil Nadu) in India. The estimate on comparison will be more than 63% of the current installed capacity of the entire nation.
3. **Hydropower:** India's mountainous terrain offers significant hydropower potential. The country's total potential is estimated at over 148 GW, with substantial untapped resources in the northeastern states and the Himalayan region. Although hydropower has faced environmental and social challenges in certain areas, it remains an important source of renewable energy.

4. **Biomass and Other Renewables:** Biomass power, generated from agricultural residues, is another potential energy source for India. The country has an abundance of agricultural waste and harnessing this for energy production can reduce waste while meeting energy needs. Small-scale hydropower, Tidal energy and geothermal energy also offer additional renewable energy avenues, although they are less developed compared to solar and wind.

Policy and Regulatory Framework

India's renewable energy sector has witnessed significant growth in recent years, largely due to supportive government policies and initiatives. The Indian government through the ministry of New and Renewable Energy has made renewable energy a key priority in its energy policy and development agenda. Several initiatives have been launched to accelerate the transition to a green energy future.

1. **National Action Plan on Climate Change (NA**PCC): Launched in 2008, NAPCC outlines India's strategy for addressing climate change through a range of mitigation and adaptation measures, including renewable energy development.
2. **Renewable Energy Targets:** India has set ambitious renewable energy targets. In 2015, India pledged to install 500 GW of renewable energy capacity by 2030, which includes solar power, wind power and other renewable sources. These targets reflect the government's commitment to scale up renewable energy generation.
3. **Favourable Investment Climate:** The Indian government has implemented several policies to attract investment in the renewable energy sector. These include financial incentives, in partnership with public sector banks such as subsidies and tax breaks, as well as the establishment of renewable energy parks, auctions for power purchase agreements and power transmission projects. India has also simplified procedures for setting up renewable energy projects to improve the ease of doing business.
4. **International Collaboration:** India has taken a leadership role in international climate diplomacy. It is a founding member of the International Solar Alliance (ISA), an initiative aimed at promoting solar energy globally. India is also part of the Paris Agreement and has committed to reducing its carbon intensity (emissions per unit of GDP) by 33-35% by 2030 compared to 2005 levels.

Key factors in the Renewable Energy Transition

In addition to India's vast renewable energy potential and supportive policies, some key factors should be considered for the smooth transition to a green energy future.

1. **Grid Infrastructure:** One of the primary challenges is the existing energy grid infrastructure, which is not equipped to handle the intermittent nature of renewable energy. Solar and wind power generation can vary depending on weather conditions and time of day, which poses challenges for grid stability. Upgrading and modernizing the power grid to accommodate renewable energy is becoming a simple task with growing research and development.
2. **Financing and Investment:** Although India has attracted significant foreign direct investment (FDI) in the renewable energy sector, financing holds a huge demand. The country's banking sector had been cautious in providing loans to renewable energy projects, particularly for smaller developers. High interest rates and the financial viability of projects can deter potential investors. But the scenario is changing towards a more sustainable outcome.

Realizing India's Future

India's renewable energy future holds tremendous promise but realizing this potential will require continued investment in infrastructure, technology and policy support. The country's renewable energy sector is already one of the fastest growing in the world and with the right support & strategies like technological & financial support, India can become a global leader in clean energy.

Advances in energy storage, smart grids and energy efficiency technologies will play a crucial role in overcoming some of the challenges associated with renewable energy integration. India's growing research and development sector can play a key role in these innovations.

The banking sector will continue to be a major driver of India's renewable energy growth. Government partnerships and collaboration with various stakeholders will help attract the necessary investment and expertise to scale up renewable energy deployment.

Arun Sudarshan S
R.O., Kadapa

UBI's Accessible CBDC App

In today's digital age, "Accessibility" is a key factor in ensuring financial inclusion. As India takes strides toward a digital economy, we are also keeping in pace with the recent financial trends in global economy. CBDC (Central Bank Digital Currency) is the emerging global trend in global economy which is poised to take over the financial landscape. Our Bank has always been pioneering with the change in financial landscape. And, keeping up with financial trend, Union Bank of India has introduced an accessible Central Bank Digital Currency (CBDC) app to empower all customers, including persons with disabilities, in their banking journey.

Understanding CBDC: The Future of Digital Currency

The Central Bank Digital Currency (CBDC) is a digital form of the Indian Rupee, issued and regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Unlike cryptocurrencies, CBDC is a sovereign-backed digital currency that offers the safety and stability of traditional cash while harnessing the efficiency of digital payments. CBDC aims to revolutionize the financial ecosystem by providing a secure, fast and inclusive means of conducting transactions, reducing dependency on physical cash and enhancing transparency in the banking sector.

Recognizing the potential of digital currency and focusing on inclusion, Union Bank of India has embraced this transformation by launching its accessible CBDC app—ensuring that every customer, including persons with disabilities, can fully participate in the digital economy.

Marking a significant milestone, our Bank launched its accessible CBDC app reinforcing its long-standing commitment to inclusive banking. This launch symbolizes the Bank's vision of fostering digital accessibility and financial empowerment for all, setting an example in the Indian banking sector.

Benefits of CBDC Application

Following are some of the benefits of CBDC:

1. **Lower Transaction Cost:** In physical currency lot of funds goes into sourcing raw materials, processing, printing, storage, transportation, security costs etc. But, with CBDCs the transaction cost is very less. As they are digital in nature, they save costs like sourcing raw materials, processing, printing, storage, transportation, etc.
2. **Reduces risk of fraud & is more secure:** Physical currency has lots of risks involved -counterfeit, theft, etc. But there is no risk of counterfeit currency in CBDC and it is password protected. This helps in curbing a lot of losses to economy which happens due to counterfeit currency, fraud attempts. In addition to its CBDCs are password protected and no debit card is required to operate them.
3. **Durability:** CBDC denominations do not degrade with time. They are resistant from physical damage and time.
4. **It helps in reducing damage to environment:** CBDC does not have any natural resources, processes, transportation involved. Hence, it curbs the risks of affecting/ damaging the environment.
5. **UPI Interoperability:** CBDC also has feature of UPI Interoperability which gives added advantage of perusing it.

Bridging the Digital Divide

Digital banking has transformed financial transactions, making them faster and more convenient. However, accessibility barriers often hinder persons with disabilities from fully benefiting from these advancements. Union Bank of India, a pioneer in inclusive banking, has taken a significant step by making its CBDC app accessible, ensuring that digital currency is easy to use for everyone, including those with visual, auditory and motor impairments.

Financial Inclusion is the need of present Economic Landscape

It is important to reiterate the need of enabling banking systems to be accessible for all. The economy cannot thrive without including all sections of society. Persons with Disabilities are a significant section, as, they comprise of significant part

of population, which cannot be ignored. As per the Census 2011, nearly about 2.68 Crore of people are Persons with Disabilities which is around 2.21% of the total population.

Hence, including persons with disabilities in banking environment will not only help them to be financially independent but it will also help our economy flourish by enabling them to contribute in economy.

Union Access: Pioneering Inclusive Banking

Union Bank of India's accessibility initiatives extend beyond the CBDC app through its flagship program, "Union Access". This initiative focuses on making banking services universally accessible by enhancing digital platforms and customer support for persons with disabilities. Through 'Union Access', the Bank is redefining financial inclusion, ensuring that every customer can access banking services independently and with dignity.

A First in India's Digital Banking Landscape

Union Bank of India is the first bank in India to integrate accessibility features into its CBDC app, setting a milestone in inclusive digital banking. This initiative reflects the bank's commitment to ensure that financial technology is accessible to all, regardless of disability.

Key Accessibility Features

The CBDC app has been designed with accessibility at its core, incorporating the following features:

- **Screen Reader Compatibility:** The app is fully optimized for screen readers like Talkback and Voiceover, enabling visually impaired users to navigate effortlessly.
- **Improved contrast settings** enhance readability for users with low vision.
- **Selection of Tokens:** Users can conveniently select and manage their digital tokens within the app.
- **Minimal Cognitive Load:** The app follows a simple, intuitive interface with clear labels and easy-to-understand instructions, ensuring a smooth experience for users with cognitive disabilities.
- **Accessibility Help in the App:** A dedicated section provides guidance on how to use accessibility features, ensuring that users can navigate the app with ease.

Empowering Independent Banking

By integrating accessibility features into the CBDC app, Union Bank of India is fostering financial independence among Persons with Disabilities. Users can seamlessly perform transactions, check balances and make digital payments without relying on others. This aligns with the Bank's mission to provide barrier-free secure banking services to all its customers.

Union Bank of India's accessible CBDC app is a testament to its commitment to digital inclusivity. As technology evolves, the Bank remains dedicated to enhance accessibility in all its digital offerings, ensuring that no customer is left behind.

With this initiative, Union Bank of India is not just embracing digital transformation but also setting a benchmark for inclusive banking in India. The future of digital finance must be accessible to all and Union Bank is leading the way.

TalkBack Screen Reader Navigation and Operation Tips

1. **Add or Deduct Notes/Coins:** Swipe up with two fingers to add the selected note/coin. Swipe down with two fingers to deduct it.
2. **Navigating Notes/Coins:** Swipe left or right with two fingers to switch between pages showing different denominations.
3. **Sending and Loading Money:** The amount field is editable, so you can type the amount. Use two-finger swipes up/down on the focused note/coin to add/deduct the amount with specific denominations.
4. **Vibration and Audio Clues:** The app provides vibration and audio feedback for actions like PIN entry, adding/deducting notes/coins, or successful transactions.

Rahul Gambhir
Union Access

केदारनाथ यात्रा.....

हर हर महादेव !!!

केदारनाथ धाम की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है, जो आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और कठिन परिश्रम का संगम है। यह यात्रा उत्तराखंड में स्थित चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है । मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव कि खोज में हिमालाय आए थे । भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर केदार की भूमि में जाकर लिप्त हो गए थे । उन्होनें एक बैल का रूप धारण कर लिया लेकिन पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होनें इसी स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग रूप प्रकट किया। यही स्थल कालांतर में केदारनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ ।

कपाट खुलने के खास मौके पर पहले दिन ही हजारों की संख्या में लोग मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ भोले बाबा का पवित्र स्थान, केदारनाथ, जहाँ भक्त हर साल बाबा की अपने हाथों से सेवा करते हैं। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर में लाखों भक्त दुःख और कठिनाइयाँ झेलते हुए बाबा के घर पर दस्तक देते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान, आप हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों, हरी-भरी घाटियों और झरनों का आनंद ले सकते हैं। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 3,553 मीटर (11,657 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ को भारी क्षति पहुंची थी , लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर की मुख्य संरचना सुरक्षित रही। यह भी एक कारण है कि आज इसे शिव की महिमा और संरक्षण का जीवंत प्रमाण माना जाता है ।

केदारनाथ यात्रा की हवा में आस्था है, पत्थरों में इतिहास है और घाटियों में गूँजता है "हर हर महादेव" का नाद । यह अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जिसको मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ ।

सौरभ राठी
क्षे.का., बड़ौदा

100% Skilled Workforce: Challenges and Solutions

As India marches toward its centenary of independence in 2047, the dream of becoming a Viksit Bharat (Developed India) is no longer abstract — it is a national commitment. It is emerging as the collective mission of every citizen. But to transform this vision into reality, India must unlock its greatest asset: its people. And not just people in numbers, but people with skills as no nation becomes developed without developing its people first. Achieving a 100% skilled workforce is not merely a labour market goal — it is a social, economic and cultural revolution.

India's demographic dividend — the world's largest youth population — is both a blessing and a burden. If empowered with the right skills, this generation could drive innovation, build global enterprises and solve India's deepest problems. But if left untrained or undertrained, they risk becoming a frustrated, underemployed majority. The goal, therefore, is clear: Every Indian must have access to relevant, high-quality and future-ready skills.

The Challenges: What Holds Us Back

A 100% skilled population is not a utopian ideal, however, despite the government's ambitious policies, several barriers continue to prevent the realization of a fully skilled workforce.

1. **The Skill-Education Mismatch:** One of the most pressing issues is that our education system continues to focus on rote learning and theoretical knowledge rather than practical skills. Though millions graduate each year, a large portion remain unemployed. Education and skill often run on separate tracks and when these tracks diverge too far, economic opportunity shrinks. According to the India Skills Report, only about 45% of Indian graduates are employable, not due to a lack of degrees, but due to a lack of industry-aligned competencies.
2. **Regional and Socio-Economic Disparities:** Access to skilling opportunities is highly unequal. A student in metropolitan city may have access to coding bootcamps, robotics labs, or mentorship, while a student in remote area may not even have a stable internet connection. This regional imbalance is further exacerbated by caste, gender and class barriers.
3. **Perception of Vocational Skills:** In Indian society, vocational education is often viewed as inferior to traditional academic degrees. Many parents still push their children toward engineering, medicine, or government jobs — even when the child's interests or the job market suggest otherwise. This mindset discourages skill-based learning and innovation.
4. **Lack of Integration and Quality Control:** India has multiple govt. promoted skilling schemes — PMKVY, Skill India Mission, ITIs, NSDC initiatives — but they often lack cohesion, standardized curricula and effective implementation. Additionally, many training programs are short-term and fail to ensure long-term employability.
5. **Rapid Technological Changes:** The future of work is being redefined by AI, automation, green energy and the digital economy. India's skilling programs need to be agile enough to match this pace. Training for jobs that will no longer exist in five years is a waste of both time and resources.

The Solutions: India's Path to a Skilled Nation

Solving this complex challenge requires a layered approach — involving policy reform, societal transformation, public-private collaboration and tech-driven scalability.

1. **Make Skills Aspirational:** We must flip the narrative: skills are not fall-back options, they are superpowers. Campaigns that showcase successful electricians who use IoT, farmers who fly drones, or women entrepreneurs running e-commerce businesses from villages can change perceptions. We need a cultural shift where hands-on knowledge is celebrated.
2. **Early Integration of Skills in School Education:** Skills must be taught from the school level. NEP 2020 has taken a promising step by proposing vocational education from Class 6 onwards, including coding, carpentry and digital skills. But we need rapid, quality implementation across rural and urban schools alike.

A student should graduate Class 12 with not just marks, but a portfolio of real-world competencies — graphic design, coding, plumbing, robotics, AI modelling, whatever suits their interests and job markets.

3. **Decentralized and Localized Skilling:** India cannot adopt a one-size-fits-all model. The skilling needs of a fishing village in Kerala are different from those of a mining district in Jharkhand. Each district must have a local skilling blueprint, aligned to its natural resources, economy and youth aspirations. District Skill Committees and local innovation hubs can play a central role in customizing and delivering relevant training.
4. **Digital Tools for Mass Access:** Technology is India's greatest equalizer. With smartphones and vernacular apps, even remote villages can access world-class content. AI tutors, AR/VR simulations for hands-on practice and gamified learning platforms can revolutionize how skills are taught and retained. The government must invest in digital infrastructure — broadband in every panchayat, tablets in every school and free access to skilling platforms like SWAYAM, DIKSHA and Skill India Digital.
5. **Public-Private Synergy:** Industries must not just hire — they must train. We need large-scale partnerships where companies help co-create curricula, offer apprenticeships and fund rural training centres. MSMEs and start-ups, too, should be roped in to train youth in scalable, digital-first roles. This approach ensures that skills taught in classrooms are the same as skills needed in workplaces.
6. **The Missing Link:** The Role of Public Sector Banks: Often left out of the skilling conversation, Public Sector Banks (PSBs) have an unmatched reach and infrastructure to accelerate India's skilling mission. Their role should extend far beyond traditional banking.

➢ **Financing Skill Aspirations**

PSBs can provide low-interest, collateral-free loans for skill development, much like they do for higher education. Youth in Tier 2 and 3 cities often drop out of skilling programs due to affordability issues. PSBs can create a "Skill Loan Yojana" under the Viksit Bharat banner, making skilling financially accessible to all.

➢ **Supporting Skilling Start-ups and Micro-Enterprises**

Skilled youth often lack capital to apply their skills in business. A young woman trained in beauty services or solar panel installation may not have ₹20,000 to start her work. PSBs, through Mudra Yojana and Stand-Up India, can aggressively fund these micro-entrepreneurs — ensuring skills turn into sustainable livelihoods.

➢ **Bank-Enabled Skilling Centers**

With over 1.5 lakh bank branches across India, PSBs have the physical infrastructure to host Skill Helpdesks or even small skilling kiosks — especially in underserved regions. These centers can connect youth with courses, financial products and mentors.

➢ **Financial Literacy as a Skill**

PSBs can integrate financial literacy modules in skilling programs, training youth not just to earn, but to manage, invest and grow their income wisely. This creates a financially aware and empowered workforce — crucial for a self-reliant nation.

Corporate Social Responsibility (CSR) for Skilling

Under CSR, banks can fund cutting-edge skilling labs, provide scholarships and support EdTech innovation. Instead of only funding infrastructure, they can invest in human capital.

➢ **Skilling for the Future, Not the Past**

India must move beyond basic skills to future-ready capabilities — green jobs, cyber security, data science, AI ethics, electric vehicle repair, climate tech, biotech and blockchain. Skilling must not be seen as a one-time event but a continuous & lifelong process of upskilling and reskilling.

The Real Meaning of Viksit Bharat

Viksit Bharat is not just about GDP numbers or infrastructure. It is about giving every Indian — from a young girl in a tribal school to a street vendor— the power to build their own future. A 100% skilled workforce means:

- Women who can code, lead and innovate.
- Farmers using AI and sensors to double their yield.
- Youth from small towns launching global start-ups.
- Blue-collar workers trained in high-tech industries.

We need to have this vison of reaching a scenario where a young man in a remote village learning AI-driven agriculture on a PSB-sponsored mobile app, a woman in North-east receives a ₹50,000 loan to open her solar repair centre, a student from unprivileged community in Central India gets a fully funded skilling scholarship, directly disbursed through her Jan Dhan account- This should be the blueprint for Viksit Bharat.

A truly developed India will be one where a degree is not the only path to dignity. Where skills — digital or manual, technical or artistic — are valued equally. Where no Indian feels unemployable, underqualified, or left behind.

Conclusion:

Achieving a 100% skilled workforce is not a distant dream. It is a challenge worth embracing. With the right blend of vision, execution, inclusivity and innovation, India can build a workforce that is globally competitive and locally rooted. That need not just government action, but a nationwide coalition — of educators, employers, civil society and yes, even banks.

Viksit Bharat begins not in policy papers, but in classrooms, community centers, mobile screens and minds that dare to learn.

A 100% skilled India is the heartbeat of a developed India. But to realize this vision, every citizen — across caste, gender, geography and income, needs a collaborative, ground-up model that doesn't just train but transforms. In a future-ready India, skills will not just give a job — they will provide freedom. And that, truly, is the essence of development.

Let every Indian not just be counted, but skilled, empowered and ready to build the India of tomorrow.

V. Mohana Sruthi
R.O., Bengaluru (S)

Bookworms

Bookworms are often called Bibliophile
Reading habit fuels them to run extra mile

They can read Night and Day
Be it December or in May

Sometimes they sleep with books in the night
They don't care if it's sunny or dim-light

They read throughout, be it winter or summer
That makes them master of grammar

Book is their best friend
For knowledge, there is no end

Today they all read
So that tomorrow they can lead

Every book opens a new story
And empowers them to face any worry

For them, Sky is the limit
Cause they are untimid

They have a heart of gold
Always ready to give back ten-fold

They create their own powerful base
Which make them fearless

Their actions are strong & bold
They are not easy to mould

Their Vision is clear
Doesn't know meaning of fear

They learn to fight for right
And spread wings to flight

They are out of the box
Doesn't care if anybody mocks

Their imaginations can paint thousand rainbows
One day this power will let them outgrow

They can cry for Bambi, laugh for Birbal

Happiness Unlimited without any haul

Bookworms are warm & pure

Have got a happy Soul, it is for sure

They can think at the speed of light
Which gives them power to write

For them nothing is impossible
Because they are truly unstoppable

They are just like Books
Should not be judged by looks

Maa Saraswati's Blessing is with them
That is enough to earn Name & Fame

Be it Baby Boomers or Generation Alpha
In the end, Bookworms will always laugh Ha Ha Ha!!

Trivia:

Since the year 1996, every year, 'National Reading Day' in India is celebrated on June 19th to remember & recognize the contribution of Late Shri Puthuvayil Narayana Panicker (Nicknamed as the "Father of Reading"), who is the man behind the Library and Literacy movement in Kerala. This day encourages people of India to develop the habit of reading and remind us how books and education help both individuals and society to grow.

Mriganka Chowdhury
DMD, C.O., Mumbai

Women Entrepreneurship and Start up Participation

"I measure the degree development of a community with the degree of progress women have achieved" – Dr. B R Ambedkar.

In recent decades, the global business landscape has undergone a dramatic transformation with the rise of women entrepreneurs who are challenging traditional norms and redefining leadership. Women entrepreneurship, once marginalized and underrepresented, has emerged as a crucial component of economic development, innovation and social empowerment. Across the world—and particularly in emerging economies like India—women are launching start-ups, running successful ventures and driving change in diverse sectors such as technology, education, healthcare, fashion, agriculture and finance.

In India, where gender roles have historically influenced professional opportunities, the rise of female entrepreneurs signifies a positive cultural and economic shift. Government initiatives like Start-up India, Stand-Up India and the Women Entrepreneurship Platform (WEP) have played a pivotal role in creating a more inclusive ecosystem. Furthermore, the digital revolution & access to social media and e-commerce platforms have enabled women—even in rural areas—to start and scale businesses with relatively low investment.

However, the journey of women entrepreneurs is not without hurdles. Structural barriers such as limited access to capital, societal expectations, lack of mentorship and gender bias continue to pose challenges. Despite these obstacles, a growing number of women are leading successful startups, creating jobs and contributing to nation building.

Let us explore the depth and breadth of women's participation in startups—from historical context to modern-day case studies, from policy frameworks to sociocultural dynamics. It aims to provide a comprehensive understanding of the factors driving women's entrepreneurship, the barriers they face and the strategies that can foster a more gender-inclusive startup ecosystem.

Indian women have come a long way and are becoming increasingly visible and successful in all spheres and have shifted from kitchen to higher level of professional activities. Today's women are taking more and more professional and technical degrees to cope with market need and are flourishing as bankers, designers, exporters, garment manufacturers and still exploring new avenues of economic participation. It is perhaps for these reasons that government bodies, NGOs, social scientists, researchers and international agencies have started showing interest in the issues related to entrepreneurship among women in India.

First Prime Minister of India, Mr. Jawarhal Nehru said, "When a woman moves forward, the family moves, the village moves and the nation moves."

The surge of women entrepreneurship is a global phenomenon, driven by increasing access to education, finance and technology. Women are now leading startups, small businesses and multinational corporations, demonstrating their versatility and resilience. They are leveraging their skills and knowledge to create innovative solutions, fostering inclusive growth. The increasing presence of women as entrepreneurs in India has led to a significant growth in the social, cultural, economic and business sector. The once perceived "homemaker" has gradually evolved into the formidable "backbone of the economy". From education to social awareness, today's women are profoundly interested in self-improvement and growth. From small business to start ups, women are driving innovation and growth in their respective industries. They are helping in the generation of employment opportunities and inspiring the next generation women of society.

In the words of our ex-president APJ Abdul Kalam, "empowering women is a prerequisite for creating a good nation, when women are empowered, society with stability is assured. Empowerment of women is essential as their thoughts and their value

systems lead to the development of a good family, good society and ultimately a good nation."

As per recent figures, women comprise 14 % of the total entrepreneurs in India, which works out to 8 million. Also, 10% of all formal enterprises are owned by women. Every person's existence must include education, but when women are educated nations are strengthened and prosper. Women can prove their worth in any field by demonstrating their expertise, talent and innovative mindset. In India, 20.37% of women are MSME owners which accounts for 23.3% of the labour force. They are considered to be the backbone of the economy. According to McKinsey Global, India can potentially add US$ 700 billion to global GDP by increasing women's participation in the labour force. The percentage of women working in the manufacturing and agriculture sector is higher than that of men. These sectors are usually credited with helping families come out of poverty and contributing to higher household income.

According to the Global Entrepreneurship Monitor (GEM), India saw a significant increase in women's entrepreneurship. This surge in women entrepreneurship contributes to job creation, which is crucial for India's burgeoning population.

India's Initiatives:

With a view to support sustainable development in the country, various schemes, initiatives, partnerships and communities have been developed. Government of India has taken various steps towards women's economic empowerment by way of initiatives/ Government Sponsored Schemes like Stree Shakti package, Udyogini scheme, Mahila Udyam Nidhi Scheme, Stand Up India Scheme, SHG (Self Help Group), Mahila-e-Haat, Mahila Bank, Mahila Coir Yojana, Women Entrepreneurship platform (WEP), Annapurna Scheme, Mahila Udyog Nidhi, PMMY, PMEGP, stand up India, Mahila Samman Saving Certificate etc.

Rural women are being encouraged to start cottage industries. Rural based micro enterprises have been encouraged by the government with various schemes such as Integrated Rural Development Program (IRDP), Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM) and development of women and children in rural areas (DWCRA).

Following organizations are actively working in the area of women entrepreneurship:

- ✓ National Alliance of Young Entrepreneurs (NAYE)
- ✓ India Council of Women Entrepreneurs, New Delhi
- ✓ Self Employed Women's Association (SEWA)
- ✓ Association of Women Entrepreneurs of Karnataka (AWEK)
- ✓ World Association of Women Entrepreneurs (WAWE)
- ✓ Associated Country Women of the World (ACWW)
- ✓ Entrepreneurship Development Institute of India
- ✓ Association of Women Entrepreneurs of Karnataka (AWAKE)
- ✓ Federation of Indian Women Entrepreneurs (FIWE)
- ✓ Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD)
- ✓ National Institute of Small Business Extension Training (NSIBET)
- ✓ Women's University of Mumbai

Women run businesses exist across a wide range of industries and sectors such as technology, fashion, education, healthcare and more. Some of the popular business choices for women are given below for further lead generation, target & customer onboarding by field functionaries: -

- ✯ Food & Beverage: (restaurants, food trucks, food products & catering services)
- ✯ Fashion & Beauty: (clothing, accessory design, makeup & skincare products, boutiques, etc.)
- ✯ E-commerce/ social media businesses: (online retail stores businesses on social media viz. Instagram/Facebook/amazon/ flipkart for jewellery, Clothing, shoes, home furnishings etc)
- ✯ Health & Wellness (yoga, meditation, fitness studios, gyms, health coaching, nutrition consulting)
- ✯ Education & training: (online courses, coaching & consulting, training programs, home-schooling curriculum design, etc.)
- ✯ Social Enterprises: (social justice, fair trades etc)

Entrepreneurs play an important role in the development & growth of

economy by not only generating income for self but also generating employment for others as their business grows.

As India moves towards a more inclusive and diverse economic landscape, the role of women entrepreneurs will continue to be pivotal in shaping the nation's future. Women entrepreneurship must be moulded properly with entrepreneurial traits and skills to meet the changes in trends, challenges global markets and also be competent enough to sustain and strive for excellence in the entrepreneurial arena. For India to become a $5 trillion economy, entrepreneurship by women must play a bigger role in its economic development. India's gender balance is among lowest in the world and improving it is important not just for gender equality, but the entire economy.

The story of women entrepreneurship is one of resilience, innovation and transformation. Across sectors and geographies, women are not only participating in the startup revolution but are also shaping its trajectory. Their ventures are creating employment, solving pressing social challenges and inspiring the next generation of changemakers.

Yet, the path is far from equal. While initiatives and platforms have emerged to support women entrepreneurs, much remains to be done in terms of financial inclusion, capacity building, mentorship and removing institutional and cultural barriers. A truly inclusive startup ecosystem demands targeted policies, gender-sensitive funding mechanisms and a broader societal shift in attitudes toward women in business leadership roles.

As we move further into the digital age and a knowledge-driven economy, empowering women through entrepreneurship is no longer just a matter of equity—it is a strategic imperative for sustainable development. By investing in women entrepreneurs, we invest in a more balanced, innovative and prosperous future.

Ravindra Singh
Z.O., Jaipur

बैंक क्वार्टर "संजना अपार्टमेंट"

बैंक क्वार्टर "संजना अपार्टमेंट" का वो नज़ारा,
जहाँ हर कोना लगता है किसी सपने से प्यारा।
मंगलूरु की हवा में है अपनापन घुला,
हर चेहरे पर मुस्कान, हर दिल है खुला।

बच्चों की किलकारियां गूंजती हर कोने में,
उनके खेल-कूद से रौनक हर क्षण में।
कभी पकड़म-पकड़ाई, कभी क्रिकेट का शोर,
उनकी हंसी में छुपा है जीवन का जोर।

"संजना अपार्टमेंट" का वो खूबसूरत बसेरा,
जहाँ हर मंज़िल को है प्यार ने घेरा।
रात में बैडमिंटन की वो मस्त चमक,
हर पसीने की बूंद में दिखती है धमक।

शाम की बैठक की है एक अलग ही कहानी,
महिलाओं की गपशप, चाय और चटपटी कहानी।
कभी रसोई की बात, तो कभी रिश्तों का जिक्र,
हर पल में छुपा है जीवन का एक चित्र।

त्योहारों में रंग भरते है सब मिलकर,
दिवाली के दीयों से जगमगाता हर कोना घर।
होली की पिचकारी, नवरात्रि की मिठाई,
हर पल में बसती है खुशियों की परछाई।

"संजना" का आंगन, हरे पेड़ों की छांव,
सुबह की चाय, और शाम का ठहराव।
यहीं बसी है ज़िंदगी की हर एक सच्चाई,
प्यार, सम्मान और सुख की परछाई।

आज भी यहीं, इसी फ्लैट का हूं मैं वासी,
मंगलूरू का प्यार है जैसे कोई सुगंधित काशी।
यह शहर और यह क्वार्टर है मेरा जहान,
जहाँ हर पल मिलता है खुशियों का आह्वान।

स्वप्निल गुप्ता
अं.का., मंगलूरु

India's Mission Zero Poverty

India, the world's most populous democracy, has made significant strides in poverty reduction over the past few decades. However, eradicating poverty completely remains an ambitious and pressing goal. With the launch of the Viksit Bharat (Developed India) Vision 2047, the Government of India has renewed its commitment to create a poverty-free, inclusive and equitable society. One of the core pillars of this vision is **"Mission Zero Poverty"** which aims not merely to alleviate poverty but to eliminate it entirely. Viksit Bharat @ 2047 is a long-term national development plan coinciding with 100 years of India's independence. The objective is to transform India into a fully developed nation by the year 2047. The vision encompasses several goals, including:

- A $30 trillion economy
- World-class infrastructure
- Sustainable urban and rural development
- Technological leadership
- Social justice and equality
- Zero poverty and zero hunger

Among these, ending poverty is foundational, as it directly affects health, education, employment, gender equality and national productivity.

Current Status of Poverty in India: According to the NITI Aayog's Multidimensional Poverty Index (MPI), India saw a significant decline in multidimensional poverty between 2015-16 and 2019-21 — from 24.8% to 14.9%. Whereas, The World Bank (2022) estimated that less than 10% of Indians now live below the international poverty line of $2.15/ day (PPP). However, about 135 million people still live in multidimensional poverty, with the largest concentrations in rural areas, tribal regions and among women and children. The COVID-19 pandemic further exacerbated poverty due to job losses, healthcare burdens and economic disruptions. However, a rapid recovery followed due to strong policy responses and welfare schemes.

Challenges to Achieving Zero Poverty: Achieving zero poverty in India is an ambitious but essential goal, especially under the Viksit Bharat 2047 vision. While India has made substantial progress in reducing poverty, numerous complex challenges continue to hinder the complete eradication of poverty. Here are the key challenges to achieving zero poverty in India:

- The top 10% of India's population holds a disproportionately large share of national wealth. While average income levels have risen, the benefits of growth are not equitably shared. Inequality in access to education, health and job opportunities prevents upward mobility for the poor.
- High Informal Employment, over 80% of India's workforce is in the informal sector with low wages, no job security and lack of access to social protection (pensions, insurance, maternity benefits). Informality keeps large sections of the population in vulnerable poverty, even if they are employed.
- Healthcare costs are a leading cause of debt and poverty in Indian households. Public healthcare facilities are often underfunded or inaccessible. Diseases, malnutrition and lack of sanitation trap poor families in a poverty-health-poverty cycle.
- Rapid urbanization has led to the growth of slums and informal settlements like Poor housing, Unsafe working conditions and limited access to water, sanitation and healthcare. Migrant workers and daily wage laborers in cities face volatile incomes and high living costs.
- Gender inequality is one of the major challenges that India is facing from ages. Women face issues like lower wages, job insecurity and limited access to assets or credit. Women-headed households are particularly vulnerable. Lack of childcare, unpaid domestic work and social norms restrict their economic participation.
- Poor communities are most affected by floods, droughts, heatwaves and crop failures. Climate shocks can push millions back into poverty by destroying livelihoods and homes. Environmental sustainability is key to long-term poverty eradication.
- India's demographic dividend requires the creation of millions of jobs annually. Slow growth in manufacturing limits employment opportunities.

Youth unemployment remains high, even among graduates.

Key Strategies of Mission Zero Poverty: Achieving zero poverty in India- under the Viksit Bharat 2047 vision requires a comprehensive, multi-pronged strategy that addresses the structural roots of poverty, improves economic opportunities and ensures equitable access to basic services. Some key strategies we must pursue to eliminate poverty:

- Make in India and Start-Up India aim to boost entrepreneurship, manufacturing and employment. PM Gati Shakti and National Infrastructure Pipeline focus on creating millions of jobs through infrastructure development. Promotion of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) provides income-generation opportunities in rural and urban India.
- India has rolled out robust welfare programs viz., PM Jan Dhan Yojana (financial inclusion), PM Garib Kalyan Anna Yojana (food security), PM Awas Yojana (housing for all), Ayushman Bharat (health insurance), MGNREGA (rural employment guarantee)

These programs directly impact poverty by providing access to essential services and reducing expenditure burdens.

- Inclusive growth ensures that the benefits of development reach the marginalized — women, SC/ST communities, differently-abled individuals and remote populations. Digital India enables remote regions to access services, education and e-commerce. Gender Budgeting allocates resources specifically for women's welfare.
- Nation Education Policy (NEP) 2020 brought restructuring in education to improve quality and access from primary to higher levels. Scholarships, mid-day meals and digital classrooms promote school enrolment, especially in underserved areas. Kaushal Vikas Yojana focuses on vocational and skill-based education.
- Ayushman Bharat covers over 50 crore Indians with free health insurance. Whereas, Poshan Abhiyan tackles malnutrition in children, pregnant women and lactating mothers. Investments in health infrastructure and digitization of health records under ABHA (Ayushman Bharat Health Account) ensure better healthcare delivery.
- PM-KISAN provides direct income support to farmers. FPOs (Farmer Producer Organizations) help farmers access markets and fair prices. Irrigation, electrification and soil health card schemes improve agricultural productivity. Digital agriculture aims to modernize farming using AI, sensors and real-time data.
- Female workforce participation has increased through skilling, entrepreneurship workplace safety, promoting women-led SHGs (Self-Help Groups) under DAY-NRLM and promoting land & asset ownership.
- Prioritized development in Aspirational Districts, tribal regions and conflict-affected zones irrespective of regional and social equality. Focus more on marginalized groups like SCs, STs, OBCs, minorities & disabled. Ensure affirmative action and representation in governance and policy-making.

Vision for 2047: Govt. has envisioned poverty-free, empowered India, by 2047, under Viksit Bharat, The vision is to create:

- A nation where every citizen has a dignified standard of living
- No child is malnourished or uneducated
- Every family has access to healthcare, housing and sustainable livelihoods
- Women, youth and vulnerable groups are empowered and productive contributors to the economy

Mission Zero Poverty under Viksit Bharat is not just a developmental target—it is a moral imperative. A nation cannot truly claim to be developed while millions still suffer from deprivation. India's success in this mission will depend on how inclusively it grows, how justly it governs and how deeply it values human dignity. The path is challenging, but with collaborative effort, innovative policy and people-first governance and above all, compassion for the last person in line, a poverty-free India is possible by 2047—a vision where every Indian not only survives but thrives.

K. Vasudeva Reddy
Bhadrachalam Branch,
R.O., Khammam

बैंक में आयोजित विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (एनसीआर)

क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर पुणे

क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-वाशी

क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे-मेट्रो

अंचल कार्यालय, बेंगलूरु

क्षेत्रीय कार्यालय, बोरीवली

क्षेत्रीय कार्यालय, गुंटूर

क्षेत्रीय कार्यालय, मैसुरु

क्षेत्रीय कार्यालय, राजमंड्री

क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-अंधेरी

क्षेत्रीय कार्यालय, हासन

क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर-पुणे (पौड-मुलशी क्लस्टर)

क्षेत्रीय कार्यालय, कडपा

क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा

क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (उत्तर)

क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शूर

क्षेत्रीय कार्यालय, उडुपि

क्षेत्रीय कार्यालय, देहारादून

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद-पंजागुट्टा

Digital Rails to a Brighter Financial Future

Imagine a world where banking is instant, effortless and tailored to you. This is rapidly unfolding reality powered by Digital Public Infrastructure (DPI) which is shared digital systems like identity, payments and data exchange, built securely and interoperably for public benefit. DPI represents a paradigm shift, moving beyond mere digitization to a fundamental rethinking of service delivery. It provides the foundational "rails" for innovative public and private services, underpinned by robust governance, legal frameworks and a steadfast commitment to core principles like inclusion, openness, modularity, user-centricity and privacy by design.

The Building Blocks of Trust and Transformation

DPI's transformative power in banking stems from the synergistic interplay of several core components:

1. **Digital Identity (Digital ID)- The Cornerstone of Trust:** Digital ID systems are the bedrock, providing reliable authentication. India's Aadhaar, a 12-digit unique biometric ID, is a prime example, instrumental in bringing millions into formal banking by simplifying e-Know Your Customer (e-KYC) processes. This dramatically reduced verification costs from approximately ₹1000/- for physical KYC to a mere ₹6/- for e-KYC. Robust Digital ID systems require interoperability standards, reliable verification technologies (like biometrics) and comprehensive data governance to safeguard personal information, enabling trust at scale.
2. **Digital Payment Systems- The Economy's Virtual Operating System:** These act as the "virtual operating system" for a nation's economy, facilitating instant, low-cost, 24/7 fund transfers.

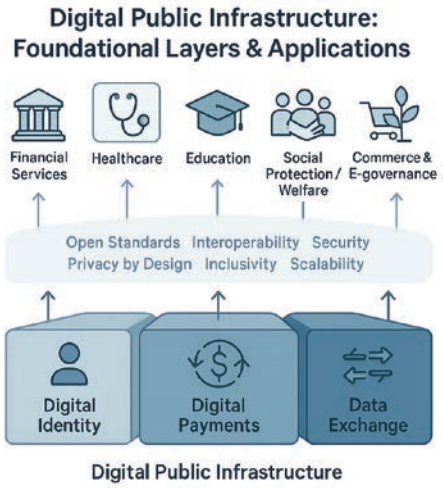

Systems like India's Unified Payments Interface (UPI) exemplify this. Built on open, interoperable architectures, they support diverse form factors and credentials. A daily wage earner receiving pay instantly via UPI illustrates improved cash flow and reduced reliance on informal lenders.

3. **Data Exchange Layers- Fuelling Open Finance and Innovation:** These layers enable secure, consented sharing of data across institutions, forming the bedrock of Open Finance initiatives like India's Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA) and the Account Aggregator (AA) framework. With user consent, Financial Information Users (FIUs) like lenders can receive data from Financial Information Providers (FIPs) like banks. These systems rely on open standards and APIs, promoting interoperability, consent-based sharing, robust security and user empowerment by breaking down data silos.
4. **Consent Management Frameworks- Empowering the User:** The ethical and legal linchpin of data sharing, these frameworks allow individuals to grant, manage and revoke consent for their data use. Transparency is paramount. Users must be fully informed about data usage. Robust consent builds trust and ensures individuals retain control.

These components create a virtuous cycle: Secure ID enables payments; payment data, with consent, feeds data exchange for innovative products, fostering inclusion and efficiency. Seamless integration is paramount for realizing DPI's full potential.

A World Remade- The Ripple Effects of DPI

DPI's implementation yields multifaceted benefits:

- **Skyrocketing Financial Inclusion:** DPI dramatically expands financial access by cutting costs, simplifying processes like e-KYC and extending digital reach. India's Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity propelled financial inclusion from 25% in 2008 to over 80% of adults in six years. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts reached 549.1 million by February 2025, with women owning 305.6 million. This initial access often catalyzes broader economic participation.
- **Massive Operational Efficiencies & Cost Reductions:** DPI streamlines processes, significantly cutting costs. For Indian banks, customer onboarding costs plummeted considerably. Cloud computing can further cut bank IT costs by 30-50%. India's Aadhaar-linked Direct Benefit Transfers (DBT) saved an estimated ₹ 3.48 lakh crore. This frees capital for reinvestment.
- **A Surge in Innovation:** DPI's open, interoperable "building blocks" lower entry barriers for fintech's, promoting competition. This fosters novel solutions like micro-insurance or MSME cash-flow based lending, moving beyond traditional asset-based assessment. The Reserve Bank of India's regulatory sandboxes nurture this by allowing controlled testing.
- **Revolutionized Customer Experience:** DPI, often with AI, ushers in hyper-personalized, convenient banking. Customers get tailored recommendations, 24/7 AI support, seamless omnichannel integration and faster services like instant loan approvals. Financial institutions should prioritize CX as a key differentiator.
- **Broader Economic Development:** DPI stimulates economic growth, transparency and resilience. It improves financial intermediation, enables entrepreneurship and reduces corruption in G2P payments. Digitalization also improves tax collection.

Let us see how nations have implemented DPI.

Global Pioneers and Local Realities

Key global DPI examples offer lessons: India Stack (Aadhaar, UPI, Account Aggregators) is a comprehensive model with phenomenal success in inclusion and digital payments (UPI: >15 billion monthly transactions by late 2024). Challenges include UPI market concentration and boosting AA awareness. Brazil's Pix, a Central Bank-operated instant payment system, saw rapid adoption (76% of population by 2023, $1.3 trillion processed), spurring competition, but has faced disinformation and fraud.

Estonia's X-Road (since 2001) is its e-government backbone, saving working time and fostering trust. Kenya's M-Pesa revolutionized mobile money (over 40 million users by 2024) but faces fee/dominance criticisms. Togo's Novissi showed agile digital emergency cash transfers using USSD/AI. PAPSS aims for real-time, local currency cross-border payments in Africa. Open Source Solutions like MOSIP (130M+ IDs across 26+ countries) and Mojaloop are democratizing DPI development.

The Indian Context: Despite India Stack's national success, achieving universal benefits requires addressing diverse regional realities like the digital divide (connectivity, devices), varying digital/financial literacy (requiring multilingual approaches) and specific local economic needs. Ensuring agricultural communities can leverage DPI for credit requires different strategies than for urban workers. State-level initiatives and community engagement are crucial for last-mile effectiveness.

These experiences highlight that technology alone isn't enough; overcoming challenges is vital.

Navigating the Digital Frontier: Key hurdles for DPI adoption:

- **Cybersecurity Threats:** Expanded digital footprints increase risks from sophisticated malware, Ransomware, AI-driven fraud and exposed APIs. Mitigation needs robust national strategies, adaptive regulation and strong authentication. Continuous investment in cyber defenses is crucial.
- **Data Privacy & Ethics:** Responsible handling of sensitive financial data is paramount. Risks of privacy violations, surveillance and algorithmic bias

must be mitigated by strong data governance, privacy-by-design principles, clear data rights and independent audits.

- **Digital Divide:** Globally, 2.6 billion people remain offline. In India, disparities in access to affordable internet, devices and digital literacy persist, hindering equitable DPI access. Targeted interventions focusing on skills and inclusive design (e.g., USSD support, vernacular interfaces) are vital.
- **Interoperability Hurdles:** Seamless communication between diverse systems is complex. High costs, lack of incentives, technical issues with legacy systems and regulatory fragmentation can lead to siloed ecosystems. Solutions involve harmonizing policies and promoting open standards. Collaboration between regulators and industry is essential.

Steering the Ship: Governance and Regulatory Frameworks

Robust and adaptive regulatory frameworks are non-negotiable. International bodies (G20, World Bank, OECD, UN) emphasize principles like inclusivity, security, privacy, interoperability and public benefit. Regulators must balance innovation with risk management and consumer protection. Approaches like principles-based regulation, regulatory sandboxes, risk-based oversight and techno-legal solutions are vital. Consumer protection laws and specific data/ cybersecurity regulations are essential. Effective Public-Private Partnerships (PPPs) are indispensable but need governance aligned with public good, ensuring accountability.

The Next Wave: DPI and Emerging Technologies

- **Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning (ML):** AI will hyper-personalize banking, optimize systems, enhance fraud detection (potentially reducing false positives by 50%) and improve accessibility. Managing computational costs and ensuring data privacy for AI training is key.
- **Internet of Things (IoT):** IoT devices will generate real-time data for smart branches, predictive maintenance and new service models like usage-based insurance. Data volume management and end-to-end security are critical.
- **Blockchain Technology & Decentralized Finance (DeFi):** Blockchain offers potential for more secure and transparent ID, payments and data exchange. DeFi applications, using smart contracts, could integrate with DPI for identity verification and settlement, leading to tokenized assets on "unified ledgers" (BIS "Finternet" concept).

Conclusion: The Enduring Promise of Inclusive Digital Finance

Digital Public Infrastructure is fundamentally rewiring the financial world, offering unprecedented opportunities for a more inclusive,

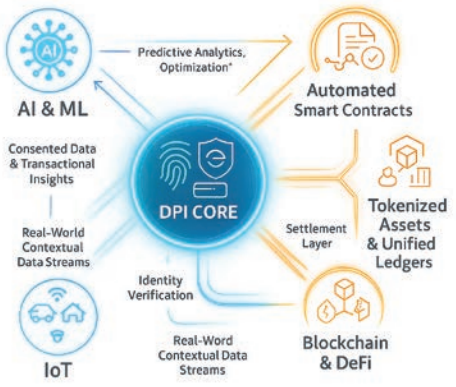

efficient, innovative and resilient banking sector. From India's UPI-driven marketplaces to Africa's mobile money, DPI is demonstrating its transformative power.

The journey requires continuous learning, adaptation and collaboration among governments, private sector and civil society to navigate challenges like security, privacy and digital divide. As emerging technologies amplify DPI's potential, the banking sector must embrace these digital rails responsibly, contributing to a financial future that serves for the public good. The digital pulse is strong and its continued success globally hinges on a collective commitment—from policymakers fostering enabling environments, to innovators building responsible solutions, to citizens engaging with digital literacy so as to ensure these digital rails pave a path to a truly inclusive and prosperous future for every citizen.

Ashish Jha
Z.L.C., Bhubaneshwar

India@2047: Health, Education and Equality

As India approaches the centenary of its independence in 2047, it stands at a pivotal juncture—a moment rich with both promise and peril. Having emerged as one of the world's fastest-growing economies, India's ambitions must now be matched by transformative progress in its social sectors. Health, education and equality are not only fundamental rights but also foundational pillars of a sustainable and just society. Let us examine the trajectory of these three sectors, their current challenges and the envisioned milestones India must reach by 2047 to fulfil its constitutional commitment to justice, liberty, equality and fraternity.

Health in India@2047

The Current Landscape

India has made remarkable strides in healthcare since independence, with rising life expectancy, declining infant mortality and a growing network of healthcare infrastructure. However, the sector continues to grapple with persistent challenges:

India's public health spending remains around 2.1% of GDP (as of 2023), well below the global average; Urban-rural and rich-poor disparities remain stark. Rural areas suffer from a shortage of hospitals, doctors and specialists; India faces the dual challenge of infectious diseases (e.g., tuberculosis, dengue) and non-communicable diseases (e.g., diabetes, hypertension) and lack of sufficient primary health centers (PHCs) and inadequate medical personnel hinders universal healthcare.

Vision for 2047

By 2047, India must transition from a reactive, curative model to a proactive, preventive and wellness-oriented system. Key goals include:

Universal Health Coverage (UHC): Every citizen must have access to affordable, quality healthcare without financial hardship. All children and youth should have access to 12 years of free, quality school education and affordable higher education.

Digital Health Transformation: Building on initiatives like Ayushman Bharat Digital Mission, telemedicine, AI-assisted diagnostics and electronic health records should be universal.

Strengthening PHCs: A robust three-tier system—comprising PHCs, district hospitals and specialty institutions—must form the backbone of Indian healthcare.

Public Health Cadre: A dedicated cadre trained in epidemiology, public policy and community health can ensure swift, science-based responses to health crises.

Education in India@2047

India's education system has made significant progress since independence, with literacy rates rising from 18% in 1947 to over 77% in 2021 (Census of India). However, issues such as rote learning, inadequate infrastructure, low teacher-student ratios and stark urban-rural disparities continue to challenge educational outcomes.

India boasts the world's largest youth population and a rapidly expanding network of schools and higher education institutions. Yet, critical issues persist.

The Annual Status of Education Report (ASER) consistently highlights poor foundational literacy and numeracy in primary students; among girls and marginalized communities, secondary school dropout rates remain high due to economic constraints and social barriers; Private institutions often offer better quality education but are inaccessible to the poor, perpetuating inequality; Indian universities lag in global rankings, hindered by bureaucratic rigidity and inadequate funding which hamper Research and Innovation.

Vision for 2047

The National Education Policy (NEP) 2020 lays a transformative roadmap, but its effective implementation will determine India's educational future. By 2047, India must aim to ensure universal access to quality education across all regions and socioeconomic strata. This includes:

Foundational Literacy and Numeracy (FLN): Every child under age 10 must achieve basic reading and arithmetic skills.

Inclusive and Equitable Education: Gender parity, regional equality and inclusive curricula that embrace diversity and local knowledge systems are essential.

Skilling and Employability: Education must align with the future of work—integrating vocational training, digital literacy and soft skills into mainstream education.

Research Ecosystem: Funding and autonomy must be increased to foster research, patents and global academic collaborations.

Curriculum Reforms: Shifting from rote memorization to critical thinking, creativity and problem-solving.

Digital Inclusion: Bridging the digital divide through affordable internet, devices and localized content, especially in rural areas.

Vocational and Skill-Based Learning: Aligning education with employability through skill development in AI, green technologies, healthcare and entrepreneurship.

Gender Equity in Education: Encouraging female education through scholarships, safety measures and awareness campaigns.

Equality in India@2047

The Challenge of Inequality

Despite constitutional guarantees, caste, gender, religion and economic disparities remain deeply entrenched in Indian society. Women's labour force participation hovers around 20%, Dalits and tribal communities face systemic discrimination and income inequality is rising. Despite constitutional safeguards, economic and social inequalities continue to marginalize large sections of society.

Vision for 2047

True equality in 2047 means more than legal rights—it requires tangible socio-economic justice. Key priorities include:

Gender Justice: Equal pay, political representation, protection from violence and access to reproductive and educational rights for all genders.

Affirmative Action 2.0: Policy tools must evolve to include economic criteria and intersectionality, ensuring equity in access without rigid quotas.

Redistributive Justice: Progressive taxation, wealth redistribution mechanisms and social safety nets can mitigate inequality.

Digital Inclusion: Universal digital literacy and infrastructure, especially in rural areas, are critical too closing the opportunity gap.

Interlinkages: Health, Education and Equality

Health, education and equality do not function in isolation. Poor health undermines educational attainment; lack of education affects employment and access to healthcare; and both are deeply embedded within the framework of social inequality. For instance, malnutrition in children leads to cognitive delays, affecting learning.

Educated women are more likely to access maternal healthcare and ensure their children attend school.

Discrimination against marginalized communities often results in poorer health outcomes and limited access to quality education.

2047 vision must therefore adopt an integrated approach, recognizing these sectors as interdependent systems that must evolve in tandem.

Strategic Enablers

Digital Health Mission: Leveraging AI, telemedicine and electronic health records to bridge access gaps.

Public Health Policy Reform: Focused investment in nutrition, sanitation, mental health and emergency preparedness.

Research and Innovation: Indigenous R&D in pharmaceuticals, vaccines and health technologies.

Education: Fostering Knowledge, Skills and Citizenship

Policy Recommendations for India@2047

Schemes such as Ayushman Bharat, which aims to provide free health coverage to over 500 million people and Mission Indradhanush, focusing on immunization, are significant steps taken by govt. However, budgetary allocations must increase and health governance at the state level must be strengthened for long-term impact.

Integrated Social Policy Framework:

Ministries of health, education and social justice must collaborate on joint programs with common metrics for success.

Increased Public Investment:

Increase spending on health to at least 3% and on education to 6% of GDP, as recommended by multiple committees.

Decentralized Governance:

Empower local bodies (Panchayats, municipalities) with funds, functions and functionaries to implement customized solutions.

Data-Driven Reforms:

Build open, interoperable data systems for health, education and social welfare to enable evidence-based policymaking. India's strength in IT, biotechnology and digital infrastructure can accelerate its progress toward this vision. Key innovations include:

- EdTech platforms (like DIKSHA) offering multilingual, free learning resources.
- Telemedicine reaching remote populations.

- Blockchain and AI for managing public health records.
- GIS mapping for identifying education and health service gaps.

Community Participation:

Empowering Panchayati Raj institutions, local schools, community health workers and civil society organizations ensures that policies reflect ground realities. Active participation from youth, women and marginalized communities in local governance can catalyse change and make interventions sustainable. Civil society, especially youth and women are to be involved in designing and monitoring development programs.

India@2047 envisions a society where every child is educated, every citizen is healthy and everyone has an equal opportunity to thrive. This is not merely a dream—it is an achievable reality if the nation prioritizes inclusive policies, grassroots empowerment and sustained investments in human development. The road ahead requires political will, public-private partnerships, technological innovation and a collective commitment to justice and equity. As India celebrates "Azadi ka Amrit Mahotsav", let it also celebrate the liberation of its people from ignorance, illness and inequality. India@2047 is not merely a symbolic milestone—it is an opportunity to redefine the nation's commitment to its people. Health, education and equality are not separate policy issues but interwoven threads in the fabric of a resilient, inclusive democracy. By investing in human capital, dismantling systemic barriers and ensuring every citizen lives with dignity and opportunity, India can fulfil the dreams of its founders and emerge as a truly developed nation by 2047. The path is arduous, but the destination is both noble and necessary.

Alam Shahzad
R.O., Patna

दिल से आभार

डूब जाते हैं इत्तेफाकन,
वो भी जो तैरना जानते हैं,
किनारे पर पहुँच जाते हैं कभी-कभी
जो नौसिखिए कहलाते है...
शिकायत शिकवों में ही कट जाती है उम्र सारी,
नेमतों का धन्यवाद देना भूल जाते हैं।

तेज गर्मी -प्रचंड सर्दी का अवसर
मिलते ही शिकन मनाते हैं,
जो हो बाहर अच्छा मौसम तो सोचो भला
प्रकृति के साथ भी कब समय बिताते हैं ।।
जब मेघ गरज़-गरज़ कर रौद्र रूप दिखाते हैं,
व्यथित हो हम भी, चादर तान सो जाते हैं ....

गिरती है जब शुष्क धरा पर बारिश की पहली बूंद,
महकते आँगन में कब सुकून से दो पल बैठ पाते हैं।
देख दूसरे की थाली हम भी
आधार-हीन स्वप्न सजाते हैं,
प्रेरित हो सोशल मीडिया से
लगामहीन इच्छाओं के घोड़े दौड़ाते हैं ।।

कभी अपनों से तो कभी गैर से,
मन में उठी जो शिकायतें हैं
फ़क़्त एक ही माजरा दर्शाती हैं,
झोली में जो भरा उसे छोड़कर...
'और' की तरफ बढ़ते हुए
हमारी नैया डगमगाती है ।।

इस फिसलती सी जिंदगी में
चलो आज स्थिर बैठ जाते हैं....
भूल कर सब शिकन-शिकायतें....
साँसों के चलने का जश्न मनाते हैं,
जो मिला उसका तहेदिल से आभार दिखाते हैं ।।

शिल्पा मेहता
भिवानी शाखा,
क्षे.का., हिसार

Powering Growth While Pursuing Net Zero

India stands at a critical juncture in its development journey, where rapid economic growth must be balanced with environmental responsibility. As the world's 4th largest economy and home to 140 crore people, India's decisions and actions have a profound impact on the global climate trajectory. The country's bold commitment to achieve net-zero emissions by 2070, while ensuring inclusive and equitable development, sets the stage for an ambitious transformation. India is charting a path toward a greener, more resilient future through energy transition, the adoption of green technologies, strong policy frameworks, climate finance and active citizen engagement.

The Green Energy Revolution:

Unprecedented Growth in Renewables

India's renewable energy capacity has witnessed remarkable growth, expanding five-fold from 24 GW in 2014-15 to 136 GW in 2024-25. Non-fossil fuel sources now account for 45% of the total energy mix, a significant leap from just 29% a decade ago. The nation has set an ambitious target of 500 GW of non-fossil fuel-based capacity by 2030, with 135 GW already under construction.

Solar, wind, nuclear and biofuels form the backbone of this transition. Solar energy, in particular, has seen exponential expansion, supported by large-scale solar parks and decentralized rooftop installations. Wind energy projects along the western and southern coasts, along with emerging offshore wind initiatives, further diversify the renewable portfolio. Nuclear power, though a smaller component, is gaining renewed attention with the introduction of small modular reactors.

Balancing Fossil Fuels and Clean Energy

Despite the surge in renewables, coal remains the dominant source, contributing around 56% of India's primary energy supply in 2023. The government's approach is pragmatic—while scaling up coal production to meet growing energy demands, it simultaneously accelerates the deployment of renewables and nuclear power, creating a diversified and resilient energy mix.

Strategic Policies and Technological Innovation:

Policy Support and Regulatory Frameworks

India's energy transition is underpinned by robust policy support and innovative regulatory mechanisms. Key policies include:

- **Renewable Purchase Obligations (RPOs):** Mandating industries and power distribution companies (DISCOMs) to procure a fixed percentage of power from renewable sources.
- **Emission Trading Systems (ETS):** Market-based mechanisms to incentivize emissions reduction.
- **Biofuel Blending Mandates:** The National Policy on Biofuels requires 20% ethanol blending in petrol by 2030, while thermal power plants must co-fire 5% biomass.

Green Hydrogen Mission

The National Green Hydrogen Mission, with an outlay of INR 19,744 crore (US$2.4 billion) until 2029-30, aims to make green hydrogen a viable alternative for hard-to-abate sectors such as steel, cement and chemicals. Five states have already announced independent hydrogen policies, attracting significant investment and signalling a shift towards a hydrogen-based economy.

Production Linked Incentives (PLIs) and Domestic Manufacturing

To reduce import dependency and stimulate job creation, India has introduced PLIs for clean energy components such as solar PV modules, batteries and advanced chemistry cells. This strategy strengthens domestic manufacturing capabilities and enhances economic resilience.

Sustainable Transportation and Electric Mobility:

Decarbonizing Transport

Transport accounts for 18% of India's greenhouse gas emissions. The government is promoting a multi-pronged approach:

- **Electrification of Vehicles:** The PM E-DRIVE scheme, incentives for EV adoption and expansion of charging infrastructure aim for 30% electric vehicle penetration by 2030.
- **Ethanol Blending:** Mandates for 20% ethanol blending in petrol by 2035 reduce reliance on fossil fuels and support rural economies through increased demand for bio-crops.

  As of early 2025, the country has reached a blending rate of

approximately 19.6%. To meet the E20 target, an estimated 1,016 crore litres of ethanol will be required, with total demand, including other uses, projected at 1,350 crore litres. This necessitates an ethanol production capacity of about 1,700 crore litres, assuming plants operate at 80% efficiency

- **Public Transport Expansion:** Investments in metro rail, electric buses and last-mile connectivity enhance urban mobility while reducing emissions.

Indian Railways: A Green Backbone

Indian Railways, one of the world's largest networks, is targeting 100% electrification by 2030. Initiatives such as regenerative braking, LED lighting and afforestation are expected to save over INR 14,500 crore (US$1.7 billion) annually and significantly cut emissions.

Financing the Green Shift:

Investment Needs and Current Gaps

Achieving India's climate goals requires annual investments of ₹12.45–16.60 lakh crore, with cumulative needs exceeding ₹830 lakh crore by 2070. Currently, only about 25% of this requirement is being met, underscoring the urgent need for increased private sector participation and innovative financing solutions.

Innovative Financial Instruments

- **Green Bonds:** The government has issued sovereign green bonds worth INR 16,000 crore (US$2 billion) to finance green infrastructure projects.
- **Green Deposits:** The Reserve Bank of India's green deposit framework channels capital into sustainable sectors like renewable energy and green buildings.
- **SEBI's Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR):** Mandates the top 1,000 listed companies to disclose ESG metrics, enhancing corporate transparency and accountability.

Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)

India is aligning its CCTS with global standards, enabling domestic participation in international carbon markets. The scheme's cap-and-trade model operates alongside a voluntary carbon market, providing dual incentives for emissions reduction across industries.

A Multi-Sectoral Approach to Decarbonization:

Agriculture and Bioenergy

India's agricultural sector is being transformed through climate-smart practices:

- **Natural Farming:** The government aims to convert one crore farmers to natural farming within two years, promoting soil health and reducing chemical residues.
- **Crop Residue Management:** Using crop residues for bioenergy production reduces air pollution and provides alternative income for farmers. Farmers, cooperatives and Panchayats receive up to 80% financial assistance for purchasing CRM machinery, also plans to build 333 depots with a capacity of 4,500 MT each in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh to facilitate the collection and utilization of paddy straw.
- **Sustainable Aviation Fuel:** Plans to introduce a 1% blending mandate for international flights by 2027 to support the decarbonization of aviation

Compressed Bio-Gas (CBG)

CBG, produced from organic waste, is an emerging solution for transport and residential energy. While blending is currently voluntary, it may become mandatory post-2025, offering another pathway to reduce fossil fuel dependency.

Urban Sustainability and Infrastructure:

Smart Cities and Urban Greening

The Smart Cities Mission, PM Awas Yojana and waste-to-wealth initiatives are driving urban sustainability. Focus areas include:

- **Water Reuse and Circular Economy:** The Union Budget 2024-25 emphasizes water resource management, sanitation and the use of treated sewage water for irrigation in 100 cities.
- **Green Buildings:** Incentives for energy-efficient construction and retrofitting support the creation of sustainable urban spaces. Interest rate concessions for IGBC (Indian Green Building Council) certified homes.
- **Public Transport and Transit-Oriented Development:** Investments in metro systems and transit-oriented urban planning reduce congestion and emissions

Waste Management and Zero-Waste Cities

Budget provisions for solid waste management and resource recovery aim to create zero-waste cities, improve municipal finances and promote circular economy principles.

Swachh Bharat Mission Urban 2.0 (SBM-U 2.0) aims to make Indian cities "garbage-free" by 2026. As of September 2024, approximately 38% of legacy waste has been cleared, with efforts ongoing to address the remaining landfill sites.

Critical Minerals and Clean Energy Manufacturing:

Critical Mineral Mission

The launch of the Critical Mineral Mission, with exemptions from customs duties on 25 critical minerals such as lithium, cobalt and copper, aims to reduce import dependency and support domestic production of EVs, batteries and renewable energy components. Sourcing these minerals sustainably, including from waste streams through recycling, aligns with circular economy principles and supports India's clean energy roadmap.

Support for MSMEs and Industry:

Energy Efficiency and Cleaner Production

The Budget 2024-25 includes plans to conduct energy audits in 60 MSME clusters and provide financial assistance for cleaner energy adoption. Improved credit access for MSMEs and the strengthening of institutions like SIDBI are expected to lower the cost of capital and encourage the adoption of cleaner production technologies.

Policy and Budgetary Support:

Union Budget 2024-25: A Strategic Shift

The Union Budget 2024–25 has been hailed as a landmark in aligning India's economic and developmental goals with sustainability and climate resilience. Key highlights include:

- **Green Taxonomy:** The introduction of a finance sector vision document and a taxonomy for climate finance to streamline and boost green investments.
- **Promotion of Rooftop Solar:** The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana aims to provide rooftop solar installations for one crore households.
- **Expansion of Pumped Storage and Small Modular Nuclear Reactors:** These initiatives diversify the energy mix and enhance grid stability.
- **Advanced Ultra-Super Critical (AUSC) Thermal Power Plants:** Developed with indigenous technology, these coal-based plants are designed to reduce emissions by 10%, representing a pragmatic approach by bridging the transition gap.

Citizen and Community Engagement:

Grassroots Movements and Public Participation

Campaigns like the India Sustainability Mission and the efforts of grassroots heroes such as the Guardians of the Earth (Padma Shri Tulsi Gowda, Jadav Payeng, Rameshwar Nath Kao & Chipko Villagers) highlight the critical role of community engagement. From afforestation drives to school-led sustainability projects, citizen participation is driving tangible change across the country.

Environmental Governance and Outcome-Based Budgeting:

Strengthening Institutions and Accountability

The Ministry of Environment's focus on outcome-based budgeting and improved environmental governance is enhancing transparency and accountability in the implementation of sustainability initiatives. This approach ensures that policy measures translate into measurable results on the ground.

The Road Ahead

India's Sustainable Development Goals (SDG) Index has improved from 57 in 2018 to 71 in 2023, reflecting consistent progress across multiple dimensions of sustainability. The nation's journey towards net zero is a multi-decade, multi-stakeholder commitment, encompassing clean energy, sustainable cities, financial innovation and inclusive growth.

With continued policy innovation, technological advancement and active citizen participation, India is well-positioned to achieve and potentially surpass its net-zero goals before 2070. The mission is vast and the stakes are high, but with concerted action, India is poised to lead the world in green transformation, setting an example for emerging economies and established powers alike.

India's pursuit of a sustainable future is not just about reducing emissions; it is about securing energy independence, fostering economic growth and ensuring environmental resilience for generations to come. The country's holistic approach spanning policy, finance, technology and community engagement demonstrates that environmental stewardship and development can go hand in hand. As India continues to innovate and lead, its journey offers valuable lessons and inspiration for the global community in the fight against climate change.

Ajay Pandey
U.L.A., Bhopal

ट्वीट लिखें / Write a Tweet

फोटो – मुनीष रैली
क्षे.का., लुधियाना

एक हज़ार शब्द मौन में गूँजते हैं, स्मृतियां जागती हैं, भावनाएं फूटती हैं, रचनात्मकता खिलती है... अपने कलम को जादू बुनने दें ! यह चित्र कौन सा किस्सा बयां कर रहा ? यदि आप अपने भावों को चंद शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो तुरंत अपनी कलम का जादू दिखाते हुए इस चित्र के लिए 50 शब्द की एक ट्वीट लिखें और अपने कार्यालय/क्षेत्र के संवाददाता के माध्यम से हमें प्रेषित करें ।

अपनी प्रविष्टि भेजते समय निम्नलिखित का ज़रूर ध्यान रखें:

- ट्वीट अधिकतम 50 शब्द की ही हो ।
- प्रविष्टि हिंदी या अंग्रेजी में भेजी जा सकती है. परिपत्र सं. 8303-2024 दि: 12.06.2024 के अनुसार दोनों श्रेणियों में अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे ।
- **एक स्टाफ सदस्य एक ही प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो हिंदी या अंग्रेज़ी में ।**
- प्रतियोगिता केवल बैंक के सेवारत कार्मिकों के लिए ही है ।
- सभी संवाददाता अपने क्षेत्र से प्राप्त प्रविष्टियों को समेकित कर निर्धारित समय सीमा में uniondhara@unionbankofindia.bank पर प्रेषित करें. सारणी में प्रविष्टि के साथ स्टाफ का नाम, पदनाम, शाखा/कार्यालय का नाम, सोल आईडी की सूचना अवश्य दें ।
- प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है ।
- शब्द संख्या का ध्यान रखते हुए अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रविष्टियों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा ।

"A thousand words echo in silence, Memories awaken, emotions unfold, creativity stirs... Let your pen weave magic! What tale does this picture tell you? If you want to express your feelings in a few words, then let your pen create magic. Write a tweet of 50 words on this picture and send it to us through the correspondent of your office/Region.

Please ensure the following while submitting your entry:

- Tweet should be of max 50 words.
- The entry may be sent in Hindi or English. In terms of circular no. 8303-2024 dt. 12.06.2024 separate prizes shall be awarded under each language category.
- **A staff member may submit only one entry, either in Hindi or in English.**
- This contest is open only for the staff members presently in service of the Bank.
- All correspondents are requested to consolidate the entries of their Region within stipulated time and send them to uniondhara@unionbankofindia.bank. Invariably give details of staff name, designation, branch/office name, SOL ID along with the entries.
- The last date for sending entries is 30th September, 2025.
- Entries, duly adhering to the specified word limit, received by the last date, shall only be included in the competition.

यूनियन धारा प्रतियोगिता क्रमांक 173 - 'एक छंद लिखें'

पुरस्कार	हिंदी श्रेणी
प्रथम	सुश्री रामचंद्रुनी पावनी, क्षे.का., हैदराबाद-पंजागुट्टा
द्वितीय	श्री ज्ञानेश्वर जाधव, अं.का., पुणे
तृतीय	श्री गौरव त्रिपाठी, क्षे.का., आगरा
प्रोत्साहन	श्री निमेष दीवान, क्षे.का., बड़ौदा

पुरस्कार	अंग्रेजी श्रेणी
प्रथम	सुश्री रोशनी येरने, क्षे.का., अहिल्यानगर
द्वितीय	श्री आकाश सिडोला, क्षे.का., हल्द्वानी
तृतीय	श्री विपिन मौर्य, क्षे. का., मुंबई-ठाणे
प्रोत्साहन	श्री के. कासीबाबू, क्षे.का., हैदराबाद-सैफाबाद

Uncertainty of the Certainty

That which is not ambiguous is Certainty and that which is ambiguous is Uncertainty. This universal game of certainty and uncertainty is the cause of all the activities occurring in the world. This exploration of the Uncertainty behind Certainty centers on the simple statement: "I don't know whether this is the truly right or not". Knowledge that appears certain about a specific context becomes uncertain when viewed through the holistic lens of life. Similarly, what seems uncertain about specific activity also remains uncertain in the similar holistic lens of life. So, put simply, the goal of this topic is to understand the beauty of uncertainty through the holistic lens of "I don't know."

Let us examine how this plays out in the day-to-day world of decisions and governance through a hypothetical scenario.

The CMD and his Secretary:

Anand leads Neuroloom, a cutting-edge tech company which aims to connect technology to biology, as its CMD and his secretary, Maya, is a former executive in product strategy. After three years in stealth mode, Neuroloom is set to launch a groundbreaking product- Mind Mesh- a wearable neuro-interface that allow users to interact with digital environments using thought alone. It is pitched as the next revolution after smart phones. The product has had internal demos and a few private investor previews, all seemingly successful. The hype is astronomical. Investors are onboarded. Media is primed. The launch is to be streamed globally. On the day of the launch, during the live demo, the product malfunctioned- not just a glitch, but a failure so profound it raised security concerns. Social media exploded. Stocks plummeted. The board got furious.

In this scenario, the sample demos misled both the CMD and his secretary. The secretary, who was so certain about the success, was flabbergasted with the results. Her experience, the sample demos and investor previews did not help her to foresee the failure of the product.

This clearly shows that whatever experience and knowledge we have is a combination of ignorance and knowledge. This ignorance, when seen through the lens of holistic life, creates a transformative impact on the human being. Thus, when someone asks: "Are you sure it is correct?" or "Don't you know? the answer is "I don't know", which is not a humble answer but a fact which we are always living in.

Fear of Insecurity:

The Secretary and the other employees responsible for the failure of the product were harshly criticized by the board members before the CMD.

The CMD summoned the responsible staff to his office. Everyone entered, fearful of losing their jobs. The CMD was calm and his subtle smile put everyone at ease. He simply said, "Just bring me the reasons for the failure of the product."

Stunned by the CMD's calmness, the secretary went home, questioning herself- why was she unable to maintain the same calmness in such an intense situation. What is lacking in her? She remembered a story from the scriptures where Lord Shiva reprimands sage Sanatkumara offering reverence to the divine couple on their arrival at his hemitage. Sage Sanatkumara responds that he does not see duality between himself and Lord Shiva and hence, he doesn't see the need for obeisance, Lord Shiva is pleased with sage Sanatkumara's demeanor and asks him to seek a boon. In response, Sage Sanatkumara replies to Lord Shiva: "I am neither afraid of your curses nor get excited with your boons."

Conflicts:

The secretary started writing in her daily diary like this: "From ancient times to the modern era, there has never been a period without wars. It is a human tendency to be in conflict. If you avoid wars, there will be cold wars. These cold wars – on a small scale - can be seen in our homes, with our relatives, friends, spouse, colleagues and among companies.

So, the fight between two children for a pen is parallel to the fight for land between two countries. Only the

scale is different. That is how time is defined: The universe is never in order; it will always be in disorder. If the students are required to stand in line height-wise, the probability of standing in line correctly is one in a million. Hence, it clearly proves that it is in the nature of things to be in disorder."

The Secretary, for the first time in her life, began reflecting inward. She realized the thoughts are always in disorder, though outward discipline is maintained. She also realized that we always try to keep the thought in order, but it is nearly impossible. It reacts negatively within a short period if we force it to be disciplined without purpose and it takes time to react if we try to discipline it with purpose. It is the nature of the thought to react.

She contemplated deeper into her thoughts and reflected: this reaction is conflict. This conflict at a bigger scale is the cause of wars. From this, she drew two conclusions: One, the nature of thought is that if it becomes complacent with what it has, it will become lazy. Two, if the thought is not complacent, but the opponent side's 'thought' has the idea of inventing better weapons backed by the financial support, the opponent is bound to win the war. Hence, it is clear that thought is relative, action is relative and verbal action is also relative. The thought which is certain & negatively assertive is dangerous. On the contrary the thought which is certain and positively assertive produces good or best results. The thought which is ambiguous cannot make any decisions and will be neutral.

In this way, the secretary could see the positive and negative shades of the thought. Does thought exist at all? If thought does not exist, then all types of emotions, feelings and mental activity come to an end. But, how to do it? If I have to take a decision or feel emotional, all thoughts related to that decision or emotion will generate. For every YES thought, there is a NO thought and vice versa. This chain is an unending cycle.

I DON'T KNOW

She intensely worked on it for a few days and finally she gave up as she could not conclude. The minute she gave up, all thoughts vanished. She was shocked with the result. She shared this elaborate analysis with the CMD, who smiled and said, "Perception. Understand what it is. That is all you have to know." The secretary respectfully replied that she could not understand. CMD said "With the experience you have and with the data you had, you were convinced that the product would be a huge success. This certainty is perception. Data is one type of perception. The methodologies you use to conclude are also a perception. Your experience is a perception. This is useful in career and in dealing with personal life. But, what about the life as a whole? Can you perceive totally? Being certain or uncertain about an activity creates a cycle of thoughts. You are strongly pushed to decide or to react. For example, you see a tree. I say the tree exists and you may say as per quantum physics, the tree does not exist, it exists only when you see it or else it exists in a wave form. These opposite thoughts will be going on and on. Actions will be going on and on. That is the nature of time. Don't relate with the movement. Be uncertain of thought-based certainty or uncertainty- whether it is correct or wrong or ambiguous." That not doing is being.

Conclusion:

Life is full of ups and downs. The results are always uncertain. This uncertainty should be dealt using the fact that perceptions are just manifestations like waves in an ocean but not the Ocean itself. Being uncertain about everything at the core of the heart makes you to witness life as it is as you cannot do anything about it. That is the only certainty we can have which is to be uncertain. That witnessing is non-doing. When a Yogi was asked why he was so famous, his reply was- "I know two things- First, I know nothing and Second, I can't do anything." The statements look passive and disinterested, but they are not. It is the essence of equanimity.

N. Uday Kiran
R.O., Kurnool

The Digital Fraud Fiasco: A Comedic Cautionary Tale

Welcome to the digital age—where we can order groceries, book vacations and unfortunately can get scammed all with just a few taps on our screens! India, with its ever-growing internet user base, has become a goldmine for cybercriminals who come up with tricks so bizarre that they could be mistaken for plots from a Bollywood comedy. From Ponzi schemes wrapped in golden promises to hilarious "digital arrests," the world of online fraud is both terrifying and, at times, unintentionally hilarious.

The Rise of Digital Fraud in India

With over 900 million internet users, India is like a grand buffet for cybercriminals. These tricksters have evolved beyond the old-school phishing emails and now use high-tech (and sometimes laughably absurd) methods to dupe unsuspecting victims.

Take the case of Mr. Sharma, a retired teacher who one day received a video call from a stern-looking man in uniform. The officer claimed Mr. Sharma was under investigation for "international money laundering." Terrified, he nearly wired his entire life savings until his no-nonsense wife, Mrs. Sharma, glanced over his shoulder and scoffed, "Since when do the police call via WhatsApp video?" That moment of clarity saved their bank account and the scammer vanished faster than a magician's rabbit.

The Funniest Frauds You Won't Believe Exist

1. **The Digital Arrest Scam: "Bhaiya, Jail Ka Address Kya Hai?"**

   Imagine waking up to a call that declares you are about to be "digitally arrested" unless you pay a fine. Sounds like a ridiculous Bollywood plot, right? Well, thousands of people have fallen for this scam. Fraudsters pose as police officers and claim the victim's Aadhaar or PAN card is linked to criminal activities. Panicked, people transfer money, hoping to "clear their record." Even Prime Minister Narendra Modi had to reassure citizens—there is no such thing as a "digital arrest."

2. **The Ponzi Scheme Parade: "Double Your Money, Triple Your Regret"**

   If someone offers you guaranteed returns of 22%, chances are they're not your financial advisor but a fraudster. The Falcon Invoice Discounting scheme promised investors massive returns before disappearing into thin air, along with Rs. 1,700 crores. Investors were left scratching their heads while the scamsters were probably sipping cocktails on a beach somewhere.

3. **Spam Calls Galore: "Mubarak Ho! Aap Jeet Gaye Ek Sar Dard"**

   Ever received a call claiming you've won a lottery you never entered? Congratulations—you've just been introduced to one of India's oldest frauds! From bank officials to fake astrologers, scamsters try everything to get your OTPs and card details. One quick-thinking Mrs. Kapoor once responded to such a call by saying, "Great! Can you park my new luxury car in my driveway first?" The scammer hung up faster than you can say "fraud."

4. **Conference Call OTP Fraud: "Hello, Can You Hear Me Scam You?"**

   This scam is a team effort. Fraudsters add victims to a conference call and impersonate bank officials, demanding OTPs for "account verification." The moment you share it, your bank account transforms into a magician's trick—your money disappears.

5. **Fake Customer Support: "Hello Sir, Your Money is Gone"**

   Beware of those Google searches for customer care numbers! Fraudsters create fake helpline numbers and trick desperate customers into revealing sensitive details. If a customer care executive asks for your PIN, know that the only thing they're helping is their own bank balance.

6. **GPay Refund Scam: "Maine Galti Se Paise Bhej Diye, Wapas Kar Do"**

   A scammer calls, claiming they accidentally sent money to your account and begs you to return it. In reality, no money was ever transferred and the moment you "refund" the amount, you're simply giving away your own cash. The scammer? They disappear like a magician after the grand finale!

7. **ATM Cloning & Fake Dispensers: "Nikalna Tha Cash, Gaya Saara Balance"**

   ATM fraudsters have stepped up their game. They install skimming devices that clone your card details while fake ATM dispensers record PINs before

refusing to give cash. By the time victims realize, their accounts have been wiped clean.

8. **The ATM Card Exchange Hustle: "Bhai Sahab, Jaldi Jaldi Karo"**

This scam relies on distractions. Fraudsters pretend to be helpful by helping at ATMs but secretly swap the victim's ATM card with a fake one. By the time you realize something is wrong, they've already emptied your account.

How to Outsmart the Tricksters

If scammers are getting smarter, so can you! Here's how to stay ahead of the game:

1. **Trust, But Verify:** Never take financial advice from a random caller, no matter how professional they sound. Always double-check with the official bank helpline.
2. **Strengthen Your Digital Hygiene:** Use strong passwords, enable two-factor authentication and never share OTPs, CVVs, or PINs. If someone from a bank asks for it, know that they are about as legit as a three-rupee coin.
3. **Think Before You Click:** Fraudsters love sending fake banking links. Check URLs carefully—if there's a spelling mistake (like "Union Bank" instead of "Union Bank"), run faster than Usain Bolt.
4. **Hang Up Like a Boss:** If someone calls you demanding money or threatening jail time, hang up without a second thought. Remember, real police officers don't threaten legal action over WhatsApp.
5. **Educate the Less Tech-Savvy:** Many victims are elderly individuals who aren't familiar with online scams. Take a moment to educate them—it could save them from a financial disaster.

Final Thoughts: Laugh, Learn & Stay Safe

While some frauds are so absurd they could be turned into comedy sketches, their consequences are no joke. The best way to fight back is through awareness, humour and good old-fashioned scepticism. Next time someone offers you a free car, just ask them to drive it over—watch how quickly they hang up!

By staying informed and alert, we can turn the tables on fraudsters and ensure the only thing getting scammed is their time.

Stay safe, stay sceptical and remember—when in doubt, just laugh it off and hang up!

Manish Lamba
R.O., Karnal

हमें गर्व है

दिनांक 09.05.2025 को वंदना डांस अकादमी, तड़ीपत्री, आंध्र प्रदेश 12,078 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर में आयोजित कुचिपुडी शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनी में सुश्री नागानंदी हरिप्रिया सुपुत्री श्री एन मधु, शाखा प्रमुख, रैतुनगरम शाखा, क्षे.का., कर्नूल ने 13 अन्य छात्राओं सहित भाग लिया और "उच्चतम स्थल पर सर्वाधिक छात्रों द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य" का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर श्री एस अब्दुल नजीर, राज्यपाल, आंध्र प्रदेश ने 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया।

सुश्री ऋषवार्षिनी सुपुत्री श्री नागेश्वर राव, अहोबिलम शाखा, क्षे.का., कर्नूल का चयन रायलसीमा की ज़ोनल क्रिकेट टीम में हुआ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन बैंक असोशिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित केस स्टडी लेखन प्रतियोगिता 2025 में श्री सी चन्द्रशेखर, मुख्य प्रबन्धक, वरंगल विजेता रहे। दिनांक 25.04.2025 को आयोजित आईबीए एचआर कॉन्क्लेव में उन्हें सम्मानित किया गया।

विशेष साक्षात्कार

सुश्री आयुषी, आईएएस

"एक माटी का दिया है, जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है
तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है
हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुक्कद्दर ढूँढता है
सीख उस समंदर से, जो टकराने के लिए पत्थर ढूँढता है"

इन पंक्तियों की तरह ही शुरू होती है सुश्री आयुषी की कहानी जो जन्म से दृष्टिबाधित होते हुए भी दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी, साहसी और कर्मठ हैं. आपने मुश्किलों को केवल हराना ही सीखा है. कहते है न डर सिर्फ मन का होता है, और जो उस डर से आगे निकल जाए, जमाना उसका होता है। उसी डर को पार करते हुए आपने न केवल 2 बार सरकारी शिक्षक के रूप में चयनित हुई, अपितु आज आईएएस अधिकारी के तौर पर पदस्थ है। जन्म से दृष्टि दिव्याङ्ग होने के बावजूद, माता-पिता के अथक प्रयासों और लगन के कारण आज आपने अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। आइए खुद आयुषी जी से ही जानते है उनकी यात्रा के बारे में:

1. अपने बचपन और परिवार के बारे में कुछ बताएं?

नमस्ते मेरा नाम आयुषी है, वर्तमान में मैं एसडीएम कझावला के तौर पर कार्यरत हूँ। सिविल सर्विसेस 2021 में 48 रैंक के साथ मेरा चयन हुआ और मेरी नियुक्ति एक आईएएस अधिकारी के रूप में हुई। मैंने कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा एक सामान्य स्कूल से, सामान्य बच्चों के साथ रहकर प्राप्त की। मेरे जो दोस्त, शिक्षक और परिवार के सदस्य थे, वे सब मुझे किताबें पढ़कर सुनाते थे और मैं उन्हें याद करती थी। मैंने सामान्य बच्चों की तरह हिन्दी, इंग्लिश और रोमन में लिखना भी सीखा था। मैं चेस, लूडो, कैरम भी खेला करती थी। मेरे या मेरे भाई के जन्मदिन पर हम लोग ऐतिहासिक इमारतों को देखने जाते थे, जहां मैं उन्हें छू कर महसूस करती थी। तो इस तरह मेरा बचपन सामान्य बच्चों की तरह ही मिला जुला था। मेरी माँ की चिंता का विषय हमेशा यही रहा कि एक तो मैं दिव्यांग हूँ साथ ही लड़की भी, तो उनकी यही इच्छा थी कि मैं अपनी पैरों पर खड़ी हो जाऊँ।

2. आपको आईएएस बनने की प्रेरणा कैसे मिली

आईएएस अधिकारी बनने की यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरी माँ मेरी पथ प्रदर्शक हैं वह भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के तौर पर कार्यरत थी। 2020 में उन्होंने मेरे लिए वीआरएस ले ली। वह मुझे आईएएस अधिकारी के रूप में देखना चाहती थी। मेरे जन्म के बाद जब उन्हें पता चला कि मैं देख नहीं सकती, यह बात उनके लिए बहुत दुखदाई थी, फिर भी उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए मुहिम किया। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी मेरी माँ ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरी माँ का सपना था कि मैं आईएएस अधिकारी बनूँ। सबसे पहले उनका सपना था कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊ। मेरा बचपन से सपना एक शिक्षक बनने का था, और मुझे खुद पर उतना विश्वास भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी माँ का ही विश्वास और भगवान के आशीर्वाद और सभी के साथ से यह संभव हो पाया।

3. प्राथमिक विद्यालय से राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तक आपकी यात्रा के बारे में बताएं?

2009 में 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद मेरिट के आधार पर मेरा चयन DIET केशवपुरम में हुआ था. 2011 में कोर्स पूरा करने के बाद, मैंने 2012 में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर एमसीडी स्कूल में, अनुबंध पर कार्य करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)से 2014 में स्नातक की डिग्री पूरी की। उसके बाद इग्नू से एम.ए. इतिहास में एडमिशन लिया। इसी दौरान 2016 में मेरा चयन डीएसएसएसबी में स्थायी तौर पर हो गया। उसके बाद 2019 में मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी बी.एड की शिक्षा पूरी की। उसके बाद मैं डीएसएसएसबी में इतिहास की प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त हो गई। इस परीक्षा में दिल्ली में मेरा प्रथम स्थान रहा। 2016 से मेरी सभी चीजें साथ-साथ चल रही थी, मेरी नौकरी, बीएड और यूपीएससी की तैयारी।2015-16 में मैंने जब यूपीएससी की तैयारी प्रारम्भ की उस समय मेरा पूरा परिवार मेरे लिए सम्पूर्ण सामग्री को रिकॉर्ड करता था। मैं उसे बार-बार सुनकर और ब्रेल पर लिखकर याद करती थी। उसके बाद ही स्मार्ट फोन, लैपटाप और तकनीक से मैंने अपनी पढ़ाई करनी शुरू की। मेरी हर दिशा का चयन मेरी माँ द्वारा किया गया और मैंने उस दिशा पर चलकर अपने सपने पूरे किए।

4. आप किसे अपना आदर्श मानती है?

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानती हूँ। मुझे इस कुर्सी पर बैठते ही उनके और गांधी जी के आदर्श याद आते है कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हम आज ऐसी स्थिति में जहां हम किसी जरूरतमन्द की सहायता कर सकते है, तो हमें वे कार्य करने चाहिए। साथ ही हमें ट्रेनिंग के समय यह सिखाया भी गया था कि आने वाली कोई भी फ़ाइल, सिर्फ फ़ाइल नहीं होती, वह किसी की पूरी जिंदगी होती है। तो हम इन छोटे-छोटे माध्यमों से किसी की ज़िंदगी बदल सकते है।

5. आईएएस बनने से पूर्व आपने एक अध्यापिका के रूप में कार्य किया है। कैसा था आपका वह अनुभव?

शिक्षक के रूप में मेरा अनुभव बहुत अच्छा था. प्राथमिक शिक्षक के तौर पर मैंने पहली कक्षा के छोटे बच्चों को गोद में बैठाकर पढ़ना लिखना सिखाया था. बच्चों के साथ खाना, खेलना, बाहर जाना, इससे उनका मेरे साथ बहुत गहरा लगाव भी हो गया था। फिर जब मैंने प्रवक्ता के रूप में कार्य शुरू किया वह अलग अनुभव था, जहां 11-12वीं के बच्चों के साथ उनके दोस्त की तरह व्यवहार करना होता था। अपनी कक्षा में मैं बच्चों को इतिहास याद करवाने के लिए संगीत का सहारा भी लेती थी, उन्हें संगीत में ट्रिक बनवाकर याद करवाती थी, जोकि उनके लिए एक अलग अनुभव होता था और मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे 3 साल के अनुभव में मेरी क्लास का परिणाम सबसे अच्छा आता था। मैं बच्चों को खुदसे सीखने पर बल देती थी, ताकि उन्हें चीजें याद हो सकें।

6. आपकी व्यावसायिक उपलब्धियों के बारे में बताएं।

शिक्षक के तौर पर मेरा हमेशा 100% परिणाम रहा, आधी से ज्यादा क्लास के बच्चों की डिस्टिंशन आती थी। जब मैं प्राथमिक शिक्षक थी तो बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला था। मुझे प्रशिक्षण के दौरान गोवा आवंटित हुआ था। मैंने एक साल वहाँ विभिन्न विभागों में रहकर काम सीखा जैसे:- शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग आदि। वहाँ मुझे एक-एक महीने के लिए तहसीलदार/ ममिलदार, सब डिविजन मजिस्ट्रेट आदि के पद पर रहकर काम करने का अनुभव मिला। उसके बाद मुझे 17 देशों के विशिष्ट लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों और उपलब्धियां के संबंध में आयोजित पर्पल फेस्टिवल के लिए अंतरराष्ट्रीय नोडल अधिकारी के रूप में चयनित किया गया। वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों जैसे 150 से अधिक फिल्म, व्हीलचेयर बास्केट बॉल, दृष्टिहीन लोगों के लिए क्रिकेट, बीच वॉलीबाल जैसी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया था। जब हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय गोवा आए थे तब मुझे राजभवन का वेन्यू कमांडर बनाया गया था। एसडीएम के तौर पर मैंने गोवा में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की अगुवाई की। इन सभी कार्यों के लिए मुझे गोवा के माननीय गवर्नर के हाथों प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। अपने बैच में मैं अकेली थी जिसे गवर्नर के हाथों से प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल मिला हो। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अध्ययन दौरे पर कैडर दर्शन के लिए कश्मीर में गई थी तो मेरा अवार्ड मेरी माँ ने प्राप्त किया। मैं यहाँ सितम्बर 2024 से हूँ, यहाँ मैं स्वास्थ्य, राष्ट्रीय शहरी आजीविका, जिला बैंकिंग कमेटी, शिक्षा के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों को देख रही हूँ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विस्थापितों एवं 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए भी राहत कार्य के साथ अलग-अलग कार्य देखती हूँ। इन सभी के अलावा मैंने लीड भूमिका में दिसम्बर में कार्निवल का आयोजन किया जिसके अंतर्गत वोटर को जागरूक करने के साथ ही सेल्फ ग्रुप के स्टॉल, बैंक के स्टॉल लगाकर लोगों को वित्तीय जागरूकता प्रदान की गई।

7. क्या आपकी यात्रा के अविस्मरणीय पल हमारे पाठकों के साथ साझा करेंगी?

हमारे प्रशिक्षण के दौरान हमें 45 दिनों की भारत यात्रा पर ले जाया गया था जोकि अविस्मरणीय अनुभव रहा। हमें 20-20 अधिकारियों के विभिन्न ग्रुप में बांट दिया गया था और फिर एक-एक ग्रुप को 45 दिनों के लिए अलग अलग रूटों पर भेजा जाता है। मेरा जो रूट था वह कश्मीर के कुपवाड़ा से शुरू हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के साथ हमने कार्य का अनुभव लिया। यह एक तरह का शिक्षण दौरा था। दौरे के दौरान ही हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने गणतन्त्र दिवस पर मुझे कुछ चयनित अधिकारियों के साथ चाय के लिए आमंत्रित किया था। तो मैंने इस दौरे के बीच में ही अनुमति लेकर राष्ट्रपति महोदय से मुलाक़ात की। मेरे पूरे प्रशिक्षण के दौरान मुझे काफी एक्सपोजर मिला खास कर, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय श्री राम नाथ कोविद जी से मिलने का मौका मिला। चार बार व्यक्तिगत तौर पर हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विभिन्न जगह पर मिलने का मौका मिला, यह ऐसी सर्विस है। जिसमें मुझे श्रमिकों से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक से मिलने का मौका मिला। हमने यह महसूस किया कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इस मुहिम में कौन, कितना और कैसे अपना योगदान दे रहा है।

8. आपकी हॉबी क्या हैं?

मुझे चेस खेलना, किताबें पढ़ना, गाने सुनना बहुत पसंद है. कभी कभी अपनी खुशी के लिए और अपने दोस्तों के लिए गाना गाना भी पसंद करती हूँ। मैं उन्हें अपने रिकॉर्ड किए गाने भी भेजती हूँ।

9. हमारे पाठकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे ?

मेरा यही संदेश है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें, अपनी शक्ति पहचानें। आपको आगे बढ़ाने वाले लोगों की बाते सुने न कि पीछे खींचने वालों की। नकारात्मक्ता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने ऊपर विश्वास रखें और जीवन में एक लक्ष्य हमेशा रखें। जो आपको हमेशा आगे बढ़ने की ऊर्जा देती रहेगी। अपनी सीमा को पहचान कर अपना गोल सेट करें। अपने ऊपर रिऐलिटि चेक कर सके। मैं अंत में अपने पाठकों को "तीन C" का संदेश देना चहुंगी – courage, confidence, Care। निर्णय लेने का जज्बा जरूर रखे, आत्मविश्वास रखें और अपना ध्यान रखें। खास कर महिलाएं, जिन्हें अपने साथ पूरी दुनिया का ध्यान रखना पड़ता है।

उषा
क्षे.का., दिल्ली (उ)

सीएसआर गतिविधियां

दिनांक 11.04.2025 को अंचल कार्यालय, पटना की सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने महावीर कैंसर संस्थान, फुलवारीशरीफ़, पटना को रु 2.0 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किया। इस अवसर पर महावीर मंदिर परिसर का दौरा करते हुए सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ।

दिनांक 12.05.2025 को अंचल कार्यालय, पटना की सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत अजय कुमार सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंका ने स्थानीय इस्कॉन मंदिर परिसर में हेतु वाटर कूलर प्रदान किया। इस अवसर पर श्री गुना नंद गामी, अंचल प्रमुख उपस्थित रहे।

दिनांक 14.04.2025 को अंचल कार्यालय, विशाखपट्टणम तथा क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम की डॉ बीआर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत मनकुटुंबम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं गुरुकुलम संस्थाओं को एसी यूनिट, इनवर्टर व अन्य जरूरत के समान दिए गए। इस अवसर पर श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख तथा श्री आर. नरसिम्ह कुमार, क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे।

दिनांक 21.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, बालेश्वर की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत बालेश्वर स्थित खिरचोरा मंदिर में रिफ्रिजरेटर लगाया गया। इस अवसर पर श्री हरे कृष्ण दास, अंचल प्रमुख, भुवनेश्वर तथा श्री आशुतोष पट्नायक, क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे।

दिनांक 23.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, हासन की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत श्रवणबेलगोला मठ को आरओ वॉटर प्यूरिफाइर प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री राजेंद्र कुमार, अंचल प्रमुख, मंगलूरु और श्री अरुण कुलकर्णी, क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे।

दिनांक 19.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेलगावी की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत श्री राजेंद्र कुमार, अंचल प्रमुख, मंगलूरु द्वारा महालक्ष्मी मंदिर, शाहपुर को ई-हुंडी प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री राघवेंद्र बीएस, क्षेत्र प्रमुख, मनीष मेघन्नावर, उप क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

दिनांक 20.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, महबूबनगर की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी को एम्ब्युलेन्स प्रदान की गई। साथ हैं साथ हैं श्री आर. सत्यनारायण, क्षेत्र प्रमुख तथा अन्य कार्यपालक गण।

दिनांक 27.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर की सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत पुरी में आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पानी बोतल, टोपी एवं छाता वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री हरे कृष्ण दास, अंचल प्रमुख, श्री निरंजन बारिक, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री जितेंद्र कुमार सामल और श्री विनय शर्मा, उप क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे।

दिनांक 03.04.2025 क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-ठाणे द्वारा सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत जिला परिषद स्कूल, आनगांव में वॉटर प्यूरीफायर और कंप्यूटर दिया गया। इस अवसर पर सुश्री सी एस जननी, क्षेत्र प्रमुख, सुश्री आशा मोहिते, मुख्य प्रबंधक, श्री हेमंतकुमार इंगले, शाखा प्रमुख – आनगांव उपस्थित रहे।

दिनांक 04.04.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, गुंटूर द्वारा सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत स्थानीय स्कूल में जल डिस्पेंसर और कंप्यूटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री एस जवाहर, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री ए राजेश, उप क्षेत्र प्रमुख, गुंटूर उपस्थित रहे।

दिनांक 04.04.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेलगावी की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत आरती रौनियार, क्षेत्र प्रमुख द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी (केएएचईआर), बेलगावी को हाई-टेक एम्बुलेंस प्रदान की है। साथ हैं डॉ. प्रभाकर कोरे, कुलाधिपति, केएएचईआर, डॉ. नितिन गंगाने, कुलपति तथा डॉ. एमएस गनाचारी, रजिस्ट्रार, मनीष मेघन्नावर और ज्ञानेश कुमार, उप क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 10.04.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, मचिलीपट्नम के फाउंडर्स शाखा द्वारा सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत निःशुल्क पेय जल केंद्र का उद्घाटन श्री के. वेंकट राव, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री के. यू.आर. एल. रेड्डी, उप क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

दिनांक 22.04.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, सैफाबाद द्वारा सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत सौ लड़कियों को सरवाईकल कैंसर टीकाकरण हेतु बसवतारकम कैंसर अस्पताल, हैदराबाद को सहायता राशि दी गई। इस अवसर पर डॉ. कुरापति के कृष्णय्या, सीईओ, बसावतारकम कैंसर अस्पताल, हैदराबाद को चेक देते हुए श्रीमति सोनालिका, क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद-सैफाबाद।

दिनांक 05.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (उत्तर) के आर.टी. नगर शाखा में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत बापिस्ट अस्पताल, हेब्बाल को दो पहिया वाहन दिया गया। इस अवसर पर श्री जी रामप्रसाद, क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

दिनांक 20.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे मेट्रो द्वारा सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत पुणे पालखी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पेयजल, खाद्य सामाग्री, स्वास्थ्य सुविधा, छाया व्यवस्था और प्राथमिक सहायता शिविर की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर श्री मयंक भारद्वाज, क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

दिनांक 19.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर पुणे द्वारा सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत आलंदी शहर से पंढ़रपुर तक जाने वाली संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पेयजल तथा खाद्य सामाग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री अंकित महाजन, शाखा प्रमुख, आलंदी सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

जिल्द 4 अंक 1&2 Vol.4 issue 1&2, 1979

बालक वर्षाभिनंदन

प्रिय बालको,
तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन।
तुम्हारे जीवन को प्रभात
बहुत शुभ हो, तुम जुग जुग जीओ।
रोटी कपड़ा और मकान की चिंता तुम्हें
कभी भी न रहे।
महान मूल्यों की उपासना करने का
तुम्हें सदा अवसर मिले।
संस्कृति के बंधनों की मर्यादा एवं
उपयुक्तता तुम जान लो।
धरती का निःस्वार्थ,
सृष्टि का सौंदर्य,
सागर की गंभीरता
और आकाश की विशालता
तुम जीवन में अपना लो।
तुम्हारा जोवन नये युग का
एक अविस्मरणीय दिन हो।

श्री कृष्णकुमार देसाई
प्रेषण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

दोस्त और दोस्ती

मित्र व मित्रता के प्रारूप नहीं होते,
उसके कोई प्रकार नहीं हुआ करते,
यह तो हृदय का पवित्र संगम है,
प्रेम को पवित्रता का मंथन है.

मित्र, मित्र के लिए कुछ खो बैठता है.
सभी कुछ दे देने को विकल होता है.
मित्रता, त्याग की सुन्दरतम पृष्ठभूमि है,
इसमें लुट जाने में खुशी मिलती है.

वीराने में भी न मालूम क्यों याद आती है,
दोस्ती के निश्चल व निर्निमेष स्नेह की,
हृदय गा उठता है मस्तिष्क के वाद्य पर,
सच है, वही भाग्य है, जिसे मीत मिले.

अपरिचित मार्ग पर साथ है 'जसबीर'
स्वप्न में भी उभरती है मधुर तस्वीर,
सींच जाती हैं मन में एक अनूठी लकीर,
याद हो आता है तुम्हारा प्यार इस
फकीर को,

स्नेह का विश्लेषण नहीं होता इस मूक
जिह्वा से,
केवल आत्मा तक पहुंचती है शान्ति
तुम्हारी याद से.

जे.सी.एल. जोशो
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र)

गज़ल

कल न मालूम कहां ले चले,
ये जिंदगी खींच के हमें।
आज बना ले जो बनाना है,
कल न मालूम बने न बने.
आज ले फिर हाथों में कलम,
लिख कोई सिसकता तड़पता हुआ राग,
कल न मालूम ये बे-दर्द दर्द भी,
अपना बने न बने।

आज ले स्याही ज़िदगी के,
जलते चिरागों को लकीरों से,
कल न मालूम ये ज़िदगी,
जलता दिया बने न बने,
कर ले सपनों को साकार, लेके,
दो घड़ी को फुर्सत जनाजे से,
कल न मालूम मौत को फुर्सत,
देने की फुर्सत मिले न मिले,

बांट दे करके टुकड़े दिल के,
आज अपने परायों में तू,
कल न मालूम ये दिल भी,
अपना बने न बने.

महेन्द्र पाल सिह 'आनंद'
शाखाः मन्सूरपुर (मुजफ्फरनगर)

AN ADVICE TO THE CREDIT

It is not uncommon that many of us are confronted with the problem of how to greet a colleague getting married more often than not, we are content with sending a greeting Telegram (eight or sixteen) from the list of standard phrases for Greeting & Telegram to the Post Office For a change here are ten banking ways of wishing happy married life to your colleague.

1. DEPOSIT your heart with her, FIXED for infinite maturity value.
2. Your love for her should be RECURRING day by day Then only you will feel the CUMULATIVE effect of it.
3. SHARE your views with her. It pays rich DIVIDENDS.
4. Take INTEREST in her INTEREST. It helps better understanding.
5. DRAFT all your programmes with her and do not SPEND all your time in the office.
6. ALWAYS try to keep cool and be BALANCED you will find DIFERENCE.
7. Don't ADVANCE too fast and land yourself in trouble beyond RECOVERY.
8. A give and take policy are a BONUS for your happiness.
9. Should there be a BRANCH expansion now?
   THINK THINK THINK!!!
10. SAVE the idea of expansion now and pave the way for a happier tomorrow!

T.S. Rachunathan
Tirunelveli Branch (Tamil Nadu)

Towards Smoother "Human Relations"

H	HAVE SELF CONFIDENCE
U	UNDERSTAND THE VIEW POINTS OF OTHERS
M	MAKE YOURSELF THE FRIEND OF ALL
A	ADMIT IT WHEN YOU ARE WRONG
N	NEVER MAKE A PROMISE YOU CANNOT KEEP
R	RESPECT AND COURTESY ARE IMPORTANT
E	EXPLAIN THOROUGHLY
L	LOOK, LISTEN AND LEARN
A	AVOID ARGUMENT
T	TRY TO BE APPROACHABLE AND SOCIABLE
I	INSIST ON SELFLESS SERVICE TO THE COMMUNITY
0	OTHERS FIRST: SELF LAST
N	NEVER CRITICISE IN PUBLIC
S	STRESS THE POSITIVE ALWAYS

Amod Kulshrestha
Shri Ganganagar Branch (Raj)

APOCALYPSE OF THE AUDIT WORLD

Hailing from the Section of Inspection,
Branches look upon us as an infliction
Are we to them an irritation.
Though be it for a short duration?

Our investigations, even
though all day
Should not affect you in any way
Granted you stick to the norm
Our pen will do just no harm

In error, be not terrified,
Promptly get them rectified.
Pursuing matters till the end
We're here to AID and befriend

During our short association
We always seek co-operation
Let there be no rift,
Inspection is for mutual benefit

Let us follow laid down Policies,
Thrashing out differences and fallacies
Auditors are not ogres, but human like you,
So kindly reconsider your view

E.A. Sadanand
Asst. Superintendent
Audit & Inspection Deptt.

Glimpse of Adventure

Shri M.R. Vijaya Raghavan of our Mysore Br., has been climbing the Himalayas for the past decade and has 04 Himalayan peaks to his credit. In 1980, he climbed a virgin peak with the Japanese, in Central Lahul Himalayas and in 1981, explored the inner 'Nandadevi Sanctuary' with the British. In 1982, he assisted the Himalayan Mountaineering Institute, as a Guest Instructor.

Adventure Club Bankers (affiliated to NAF, Meerut), has been the first at- tempt in South India at organising Bank employees in pursuit of adventure, and it has already gathered momentum, as is manifest in the establishment of similar clubs in Bangalore and Yelandur.

As Club Leader, Vijaya Raghavan gives us a spirited flashback of how they humbled the mighty 'Rangaswamy'.

Night pre-empted us. Yet we could clearly see the mighty 'Rangaswamy' Pillar, towering from the valley of the mountain slope over which we stood. A mild shiver ran through us, caused perhaps by the cold December breeze, or, the awe-inspiring sight of the 500 ft. rock-erect, that we were to encounter with the dawn.

Six of us (Adventure Club Bankers) had set out from Mysore on a 3-day expedition to negotiate the Pillar, situated in the green forests of the Blue Mountains. A safari-like bus journey through the wildlife sanctuaries of Bandipur and Madhu- malai, rejoicing at the sight of dancing peacocks and roaming deer was an unforgettable experience. A 7-kilometre trek from Kilkothagiri through the lush green tea-gardens and woods of Nilgiris, led us to camp site.

Prasad (guest member) and Prakash (Bank of India), at once, started improvising a shelter, while others flocked round Yeshawantha kumar (of our Domlur Br.) to cook our supper. I was pensive at the thought of leading four novice climbers up the gigantic rock-pillar, while the rest were in high spirits, singing and dancing over the campfire.

At sunrise, geared with ropes, pittons and carrabiners, we braved our way down the slope through the well-knit shrubs of the Nilgiris. A mongoose dived into the bushes while a bevy of birds took flight in protest at our intrusion. Soon, we arrived at the pillar-base. Well briefed on the basic techniques of rock- climbing and the use of belay rope, we roped-up together. A strict observance of safety techniques delayed us, yet we progressed steadily to a tiny table-land.

Prakash, a hefty chap, who had climbed remarkably, was reluctant to move further without quenching his thirst. Kumar, ever ready with a bag full of lemonade and biscuits, came to his help. Sheshidhar, more concerned about his camera rather than climbing, sprang into action, shooting anything he could espy.

We resumed climbing and traversed to the rear side of the pillar, one behind the other, cautiously, on a narrow path which led us to the base of the ultimate lap a 20 foot chimney. A wrong move at this stage would certainly roll us down to the virgin forests of Nilgiris-rocks permitting!!!

Prasad, securing himself to a rock-projection, belayed me while I inched up the yawning chimney. Kumar, the shortest of us, lagged behind, but managed. Then, a moderate climb saw us all atop the pillar.

We waved at the guides who stood watching us at the camp site, we waved at the rocks, trees, birds, and the sky, we waved at all our members who could not partake in the expedition. Enthralled by our success, Kumar threw his cap down the valley and exhausted the lemonade in a gulp.

Down we descended carefully to the foothills and climbed back to camp site, tired, yet delighted. The euphoria that swayed us atop the pillar, transported us to dizzy heights. We had lost our hearts to the Almighty 'Rangaswamy'.

THE LAWYER'S LANGUAGE

Suppose a man has to give another an apple, he would simply say "Have an apple". But when the transaction is entrusted to a lawyer, to make an offer in writing, he presents the transaction in this form:

"I hereby give and convey to you all and singular, my estate and interest, right, claim, title and advantages of and in said apple, together with all its juice, pulp & pips, rind and all rights and advantages therein, with full powers to eat or give the same away, with or without rind, pulp and pips, juice, anything hereinbefore and hereinafter or any other means of whatever nature or type or kind, whatsoever to the contrary in any wise notwithstanding."

Then another man will come to take away the apple.

Compiled by K.K. MADAN

Hissar Br., Haryana

WHEN THE HOBBYHORSE IS A CAMERA

The origins of photography date back to antiquity. A Chinese scholar claimed that he had found traces of china plates made sensitive to light by chemicals, 2000 years ago. The darkness of Silver Nitrate when exposed to light, was noted by Angelo Solo in 1614.

The Cornia Obscura (Dark Room) is rightly called the fore runner of our modern 5. L. R. Cameras. It was known to an Arabic scholar, Abram (a box with a mirror. at an angle of 45° and a hole in front). The mirror image of a landscape was projected on an oiled paper at the top and the artist traced the image on oiled papers.

A Frenchman called Josep N Neepee (1765-7833) was able to produce a plate, which could bear the latent image. The first Neepee photograph was made probably in 1826.

In 1829, Neepee joined Jacqus. U. Daguesra (1789-1851). Daguesra learnt all he could from Neepee. In 1833. Neepee died and in 1837, Daguesra produced his first photograph. In 1839, Daguesra photograph came into existence. In the same year, Fox Talbot produced the first paper negative, and photography as we know it today, came into existence.

According to me, Ansel Adams is the world's best pictorialist today? whom none of the national photographers can match. We Indians have not made headway due to non- availability of basic materials. Even so, we have produced a man like R.R. Bharadwaj (known as Guruji) whose work approximates to international standards.

The life of a good, properly processed photograph is 50 years, if sepia-toned, it could last for 75 to 100 years in case of monochrome photographs. A lot depends on storage and display conditions. Research is going on in the USA to increase the life of a colour photograph because it is much less than that of a black & white photograph.

It is extremely reprehensible that international photographers have often photographed incidents, macabre and horrifying, when they could have saved the victim, or, at least made an attempt to do so. But only the photographer can explain his conduct. He might argue that he himself could have been killed, if he had tried to save the victim. Each individual case should be decided on its own merits.

My interest in photography follows the 4-year Commercial Art Certificate Course, done through the Sir J.J. Institute of Applied Art Bombay. Moreover, photography is part and parcel of the advertising field, as also a universal medium of communication.

KERSI RABADI

BR. MGR., DR. AMBEDKAR RD., BANDRA

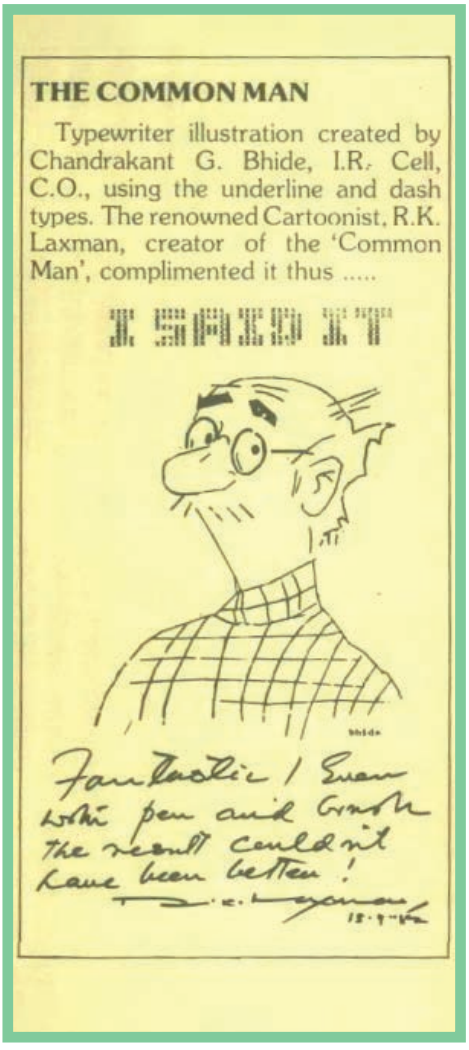

केंद्र समाचार

दिनांक 14.05.2025 को द ग्रेट इंडियन बीएफ़एसआई- 2025 के पांचवे एडिशन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय साइबर एवं फ्रॉड अवेयरनेस के कैम्पेन #jamkarphenko को उत्कृष्ट कैम्पेन से सम्मानित किया गया।

मई, 2025 में अंतरराष्ट्रीय कारोबार सम्मेलन- 2025 द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एचआर डिजिटलाइजेशन तथा लर्निंग & डेव्लपमेंट में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

समाचार (उत्तर)

दिनांक 11.04.2025 को अंचल कार्यालय, पटना के परिसर का उद्घाटन सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा किया गया। साथ हैं श्री गुना नंद गामी, अंचल प्रमुख, श्री बैजनाथ सिंह, अंचल प्रमुख, रांची तथा श्री मुकेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख, पटना।

दिनांक 12.05.2025 को श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंका द्वारा अंचल कार्यालय, पटना का दौरा किया गया। इस अवसर पर श्री गुना नंद गामी, अंचल प्रमुख उपस्थित रहे।

दिनांक 21.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय,आगरा में श्रीमती अर्चना शुक्ला, अंचल प्रमुख, मेरठ की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री पार्थ सारथी मिश्रा, उप अंचल प्रमुख, मेरठ और श्री देवेन्द्र कुमार चौबे, क्षेत्र प्रमुख,आगरा। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 23.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, समस्तीपुर में श्री गुनानन्द गामी, अंचल प्रमुख, पटना की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री राजेश कुमार क्षेत्र प्रमुख। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

समाचार (पूर्व)

दिनांक 03.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, जोरहाट के अंतर्गत आइज़ोल में "कैंसर के उपचार को सुलभ एवं व्यापक रूप से उपलब्ध बनाने के लिए तथा देश भर में सूखती नदियों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना" विषयों पर विचार विमर्श के लिए राज्यसभा की याचिका समिति द्वारा अध्ययन दौरा किया गया। इस अवसर पर श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक, श्री जी के सुधाकर राव, मुख्य महाप्रबंधक, कें.का., श्री लोकनाथ साहू, अंचल प्रमुख, कोलकाता, श्री भास्कर मंडल, क्षेत्र प्रमुख, जोरहाट द्वारा बैंक का प्रतिनिधित्व किया गया।

दिनांक 04.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में श्री हरे कृष्ण दास, अंचल प्रमुख, भुवनेश्वर की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री निरंजन बारिक, क्षेत्र प्रमुख। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 16.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, बालेश्वर में श्री हरे कृष्ण दास, अंचल प्रमुख, भुवनेश्वर की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री आशुतोष पट्नायक, क्षेत्र प्रमुख, बालेश्वर। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

समाचार (पश्चिम)

दिनांक 23.06.2025 को अंचल कार्यालय, गांधीनगर के दहगाम शाखा में श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में केवाईसी जागरूकता एवं वित्तीय समावेशन सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री अखिलेश कुमार, अंचल प्रमुख, गांधीनगर, श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी, क्षेत्र प्रमुख, गांधीनगर तथा श्री दिव्येश कालरा, क्षेत्र प्रमुख, अहमदाबाद।

दिनांक 24.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई (दक्षिण) द्वारा एचएनआई ग्राहक और निवेश जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री आशीष सोमैया, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, राइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, श्री बिरजा प्रसाद दास, अंचल कार्यालय, मुंबई, श्री सुमित श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, लीप, श्री शलज कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय, मुंबई तथा श्री राहुल जुयाल, क्षेत्र प्रमुख, मुंबई दक्षिण उपस्थित रहे।

दिनांक 09.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर पुणे में श्री पार्थ सारथी दाश, उप अंचल प्रमुख तथा श्री उपेंद्र कुमार पाल, क्षेत्र प्रमुख, ग्रेटर पुणे द्वारा शाखा प्रमुखों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 04.04.2025 को सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा अंचल कार्यालय कोयम्बत्तूर का उद्घाटन किया गया। साथ हैं श्री राजकुमार एस.ए., अंचल प्रमुख सहित अन्य कार्यपालक-गण ।

दिनांक 21.04.2025 को सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा अंचल कार्यालय, तिरुपति का उद्घाटन किया गया। साथ हैं श्री पत्रि श्रीनिवास कुमार, अंचल प्रमुख तथा आई के सूर्यप्रकाश राव, उप अंचल प्रमुख तिरुपति ।

दिनांक 29.04.2025 को आयोजित एस.एल.बी.सी. की 231 वीं बैठक के दौरान श्री एन. चन्द्र बाबू नायुडु, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का स्वागत करते हुए सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और श्री सी.वी.एन. भास्कर राव, अंचल प्रमुख।

दिनांक 09 जून 2025 को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य निष्पादन हेतु श्री प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री, गोवा से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री आशीष मालवीया, क्षेत्र प्रमुख, गोवा

दिनांक 12.06.2025 को अंचल कार्यालय विजयवाडा के अंतर्गत माननीय सांसद डॉ एम. तंबिदुराई की अध्यक्षता में अमरावती और तिरुपति, आंध्र प्रदेश सरकारी आश्वासनों पर राज्यसभा समिति ने अध्ययन दौरा किया। इस अवसर पर श्री एस. रामसुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक, श्री सी वी एन भास्कर राव, अंचल प्रमुख, विजयवाडा द्वारा बैंक का प्रतिनिधित्व किया गया।

दिनांक 26.05.2025 को श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का की उपस्थिति में श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद ने तेलंगाना स्टेट नॉर्थन पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TGNPDCL) के कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी को रु.1.00 करोड़ दुर्घटना मृत्यु बीमा चेक सौंपा तथा तेलंगाना राज्य के सभी कर्मचारियों का यूनियन बैंक कार्पोरेट वेतन खाता खोलने हेतु समझौता पत्र सौंपा। साथ हैं श्री सर्वेश रंजन, महाप्रबंधक, श्रीमती सी एस जननी, उप अंचल प्रमुख तथा श्रीमती अपर्णा रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख, करीमनगर।

दिनांक 22.05.2025 को यूनियन बैंक द्वारा समर्थित स्त्रीनिधि डिजिटल रि पेमेंट एप के विमोचन के दौरान श्री. के श्रीनिवास, एम एस एम ई & सेर्प, एन आर आई एम्पवारमेंट और संबंध मंत्री, आंध्र प्रदेश के साथ और श्री सी.वी.एन. भास्कर राव, अंचल प्रमुख, विजयवाडा.

दिनांक 09.05.2025 को श्री बाल मुकुंद शर्मा, अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया गया। उनका स्वागत करते हुए श्री एस. जवाहर, क्षेत्र प्रमुख, गुंटूर

दिनांक 28.05. 2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै में तमिल नाडु विशेष पुलिस बल 6 वी बटालियन के पुलिस कर्मियों के सुपर सैलरी खाते (राज्य सरकार वेतन पैकेज- SGSP) संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।

दिनांक 13.05.2025 को हैदराबाद में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्टार्ट-अप इंडिया और अन्य योजनाओं के तहत अ.जा.और अ.ज.जा. उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद तथा श्री रवि कुमार नर्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, डीआईसीसीआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया साथ हैं श्रीमती सी एस जननी, उप अंचल प्रमुख तथा अन्य।

दिनांक 21.05.2025 को श्री सीवीएन भास्कर राव, अंचल प्रमुख विजयवाडा की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय गुंटूर में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनाकं 28.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में श्री शक्तिवेल एस, अंचल प्रमुख, एर्णाकुलम की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री नरेश कुमार वाई, क्षेत्र प्रमुख, श्री दीपक चार्ली तथा श्री सोनी जेकब, उप क्षेत्र प्रमुख। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 03.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शूर में श्री शक्तिवेल एस., अंचल प्रमुख, एर्णाकुलम की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री सतीश कुमार एम. क्षेत्र प्रमुख, तृश्शूर। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 10.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु (उत्तर) में श्री कल्याण वर्मा, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 13.06.2025 को श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, खम्मम का दौरा किया गया। इस अवसर पर श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख का स्वागत करते हुए श्री ए हन्मंत रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख। साथ हैं श्री सर्वेश तेजावत तथा श्री एन सुधाकर राव, उप क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 17.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीकाकुलम में श्रीमती शलिनी मेनन, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्री पैडि राजा, क्षेत्र प्रमुख, श्रीकाकुलम। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 18.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, कडपा में श्री पत्रि श्रीनिवास कुमार, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ हैं श्रीमती ए. लक्ष्मी तुलसी, क्षेत्र प्रमुख, श्री शेक बाषा और श्री रंजीत कुमार एम. पी., उप क्षेत्र प्रमुख। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्टाफ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महिला हॉकी टीम की कप्तान, सुश्री रुतुजा दादासो पिसाल को महिला हॉकी एशिया कप 2025 हेतु चुना गया है। यह क्षण उनके समर्पण, नेतृत्व और उत्कृष्टता की अथक प्रयास को दर्शाता है। यूनियन बैंक की टीम का नेतृत्व करने से लेकर राष्ट्रीय रंग पहनने तक की उनकी यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं!

दिनांक 02.06.2025 से 15.06.2025 तक मुंबई में अंबरनाथ हॉकी वेल्फेयर असोशिएशन द्वारा आयोजित 14वां जो फर्नांडीस महिला हॉकी टूर्नामेंट- 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

दिनांक 01.05.2025 से 11.05.2025 तक मुंबई में सुपर लीग 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फेयर प्ले ट्रॉफी खेला गया।

दिनांक 20.05.2025 से 01.06.2025 तक मुंबई में आयोजित 49वां सेंट पीटर्स एलीट महिला हॉकी टूर्नामेंट- 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

दिनांक 07.04.2025 से 12.04.2025 तक बांद्रा जिमखाना, मुंबई में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट- 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

दिनांक 07.04.2025 से 12.04.2025 तक मुंबई में अंबरनाथ हॉकी वेल्फेयर असोशिएशन द्वारा आयोजित 14वां जो फर्नांडीस मेन हॉकी टूर्नामेंट- 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

आपकी पाती

"यूनियन धारा" के स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अंक को पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह अंक न केवल बैंक की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का दर्पण है, बल्कि इसमें संकलित विविध लेख, कविताएँ और अनुभव हमें समाज और संस्थान के साथ गहराई से जोड़ते हैं। इस अंक की विशेषता यह है कि इसमें 'RISE' जैसी रणनीतिक थीम के माध्यम से संगठन की प्रगति और समर्पण को उजागर किया गया है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की सृजनात्मकता और लेखन-कौशल को भी सम्मानजनक मंच प्रदान किया गया है। "अतीत के झरोखों से" स्तंभ ने इस पत्रिका की विरासत को और भी मूल्यवान बना दिया है। विद्यालयी दृष्टि से देखें तो यह अंक हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत है। इसमें निहित विचार, अनुशासन, समर्पण और नवाचार की भावना हमें यह सिखाती है कि संस्था की सफलता केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि उसके लोगों के विश्वास, मेहनत और रचनात्मक योगदान से सुनिश्चित होती है। मैं "यूनियन धारा" की सम्पादकीय टीम और सभी योगदानकर्ताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ और यह विश्वास व्यक्त करती हूँ कि यह पत्रिका भविष्य में भी इसी प्रकार ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहेगी।

महालक्ष्मी पाण्डेय
प्राचार्य, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय न.1, रीवा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय से प्रकाशित की जानेवाली द्विभाषी गृह पत्रिका "यूनियन धारा" का जनवरी - मार्च 2025 अंक हमें प्राप्त हुआ है। पत्रिका अत्यंत ही मनमोहक एवं प्यारी है। इसकी साज- सज्जा और कलेवर बेहतरीन है। पत्रिका में छपे सभी लेख एक से बढ़कर एक हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेख 'एनआरआई बैंकिंग' अत्यंत ही ज्ञानवर्धक लगा। बैंकिंग कारोबार से जुड़े समस्त कर्मियों हेतु यह अंक वाकई पठनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है। श्रीमती रीटा डिसूजा का साक्षात्कार हमें कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर और ध्यान केंद्रित कर अपने लक्ष्य हासिल करने हेतु अत्यंत प्रेरक है। यज्ञमूर्ति द्वारका नाथ जी का लेख 'The Magnificent Fort of Chitra Durga' पढ़कर मन रोमांचित हो उठा। लेख पढ़कर अनायास ही चित्रदुर्ग देखने की इच्छा मन में जाग्रत हुई है। कुल मिलाकर पत्रिका अत्यंत मनोरम, शिक्षाप्रद एवं पठनीय है। पत्रिका के समस्त संपादक मंडल को साधुवाद। आगामी अकं की प्रतीक्षा में...

गणेश प्रताप गुजर
केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेलगावी

हमें यूनियन बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका यूनियन धारा की स्वर्णिम वर्ष अंक की सॉफ्ट प्रति प्राप्त हुई है, धन्यवाद। पत्रिका में शामिल सभी आलेख ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक हैं। पत्रिका की साजो-सज्जा बहुत ही आकर्षक है। पत्रिका के प्रत्येक आयाम बेहद रोचक एवं प्रभावशाली हैं। पत्रिका में शामिल एनआरआई बैंकिंग एवं वैश्विक कर अनुपालन और पारदर्शिता हमारे लिए उपयोगी एवं पठनीय है। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुकामनाएं।

संजय कुमार
उप अंचल प्रबंधक, इंडियन बैंक

'यूनियन धारा' पत्रिका के इस अंक में विभिन्न विषयों पर सामयिक लेखों को समाहित किया गया है। पत्रिका के इस अंक में 'जीवनदायिनी नर्मदा नदी', 'यात्राएं क्यों महत्वपूर्ण हैं?' तथा 'एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व - रीटा डिसूजा' अत्यंत रोचक लेखों में से एक हैं, वहीं 'मेरा मोबाइल' और 'बैंक- एक अनमोल धरोहर' कविताओं ने इस पत्रिका की मूल्यता में असाधारण भूमिका जोड़ी हैं। 'यूनियन धारा' पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित सृजनात्मक लेखों हेतु रचनाकारों को अनंत शुभकामनाएँ एवं सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई। आगामी अंकों हेतु अशेष शुभकामनाएँ,

हेमलता
मुख्य प्रबंधक , यूको बैंक

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु का निरीक्षण - दि. 30.05.2025

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप- समिति के कर कमलों से सफल निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री कल्याण वर्मा, अंचल प्रमुख, बेंगलूरु साथ हैं श्री गिरीश चन्द्र जोशी, महाप्रबंधक (मासं एवं राभा), श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (राभा) श्री जॉन ए अब्राहम, मुख्य प्रबंधक (राभा), श्रीमती कौस्तुभा वी.एस, प्रबंधक (राभा), श्रीमती पूर्णिमा एस, व.प्र. (राभा) तथा श्री धर्मबीर, उप निदेशक, (राभा), वित्तीय सेवाएं विभाग

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (दक्षिण) का निरीक्षण - दि. 30.05.2025

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप- समिति के कर कमलों से सफल निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री असीम कुमार पाल, क्षेत्र प्रमुख, बेंगलूरु (दक्षिण) साथ हैं श्री कल्याण वर्मा, अंचल प्रमुख, बेंगलूरु, श्री गिरीश चन्द्र जोशी, महाप्रबंधक (मासं एवं राभा), श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (राभा) श्री जॉन ए अब्राहम, मुख्य प्रबंधक (राभा), श्रीमती कौस्तुभा वी.एस, प्रबंधक (राभा), श्रीमती पूर्णिमा एस, व.प्र.(राभा) तथा श्री धर्मबीर, उप निदेशक, (राभा), वित्तीय सेवाएं विभाग

Printed and Published by Gayathri Ravi Kiran on behalf of Union Bank of India, Printed at M/s. Printrade Issues (INDIA) Pvt. Ltd., Plot No. EL-179, TTC Industrial Area, Electronic Zone, Mahape, Dist. Thane - 400 710, Maharashtra and Published from Union Bank of India, Union Bank Bhawan, 239, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Editor - Gayathri Ravi Kiran.

कप्पिल बीच, वर्कला केरल
अंकित,
यू.एल.ए., गुरुग्राम

Union Dhara, R.N.27989/76